

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 2021-22 और 2022-23 में अब तक सुदृढ़ बना हुआ है, क्योंकि बैंकों ने ऋण में व्यापक-आधारित तेजी के कारण अच्छी तुलन पत्र वृद्धि देखी है। कोविड-19 के कारण एहतियाती वृद्धि से जमा वृद्धि में कमी आई है। संवर्धित पूंजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और बढ़ी हुई लाभप्रदता संकेतकों ने उनकी मजबूती को दर्शाया है। आने वाले समय में बढ़ी हुई नीतिगत ब्याज दर का पूर्ण संचरण जमा दरों तक करने से ऋण मांग को पूरा करने के लिए जमा वृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। पुनर्गठित आस्तियों में चूक की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

1. भूमिका

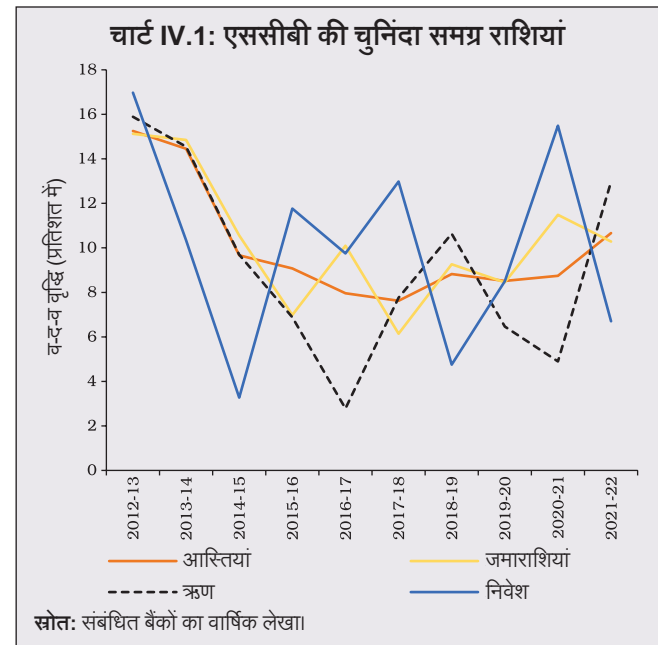
IV.1 2021-22 के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र का विस्तार बहु-वर्षीय उच्च गति से हुआ। समय पर नीतिगत समर्थन ने बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन और सुदृढ़ता संकेतकों पर महामारी के प्रभाव को कम किया। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पूर्व से जारी चुनौती कम हो रही है और लाभप्रदता क्रमिक रूप से सुधरकर 2014-15 के स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही हानि में कमी तथा पूंजी बफर में मजबूती आई है।

IV.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2021-22 और 2022-23 की पहली छमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन और प्रदर्शन पर चर्चा की गई है। उक्त के खंड 2 और 3 में क्रमशः तुलन पत्र संबंधी गतिविधियों और वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में उनकी वित्तीय सुदृढ़ता की चर्चा की गई है, जिसके पश्चात खंड 5 में ऋणों के क्षेत्रवार अभिनियोजन के पैटर्न का मूल्यांकन किया गया है। खंड 6 से 11 में स्वामित्व का स्वरूप, कॉरपोरेट अभिशासन एवं क्षतिपूर्ति प्रथाएं, भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन, भुगतान प्रणालियों की गतिविधियाँ, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेश से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), लघु वित्त बैंक

(एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) से संबंधित विशिष्ट विषयों की समीक्षा अलग से खंड 12 से 15 में की गई है। खंड 16 में विश्लेषण के पश्चात सामने आए प्रमुख मुद्दों को उजागर करके और प्रगामी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके अध्याय का समापन होता है।

2. तुलन-पत्र विश्लेषण

IV.3 सात साल के अंतराल के बाद 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) की समेकित तुलन पत्र में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई (चार्ट IV.1)। एक साल पहले कोविड-19



उत्प्रेरित सावधानी के कारण जमा वृद्धि में कमी आई है। दो साल के अंतराल के बाद उधारी में सुधार के कारण देयताओं में वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष पर, मुख्य रूप से ध्यान पूरे वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि को मजबूत करने पर रहा। निवेश में संयमित रूप से कमी आई।

IV.4 हाल की नरमी के बावजूद, समेकित तुलन पत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का अब भी बड़ी हिस्सेदारी है। मार्च 2022 के अंत में, उनकी हिस्सेदारी एससीबी के कुल जमा शेष का 62 प्रतिशत और कुल ऋण और अग्रिमों का 58 प्रतिशत थी (सारणी IV.1)।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1. पूंजी	59,328	71,176	30,641	31,243	91,465	1,01,933	5,375	5,800	1,300	4,287	1,88,109	2,14,439
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	6,49,142	7,27,852	7,07,346	8,08,446	1,24,693	1,39,569	14,800	16,543	-704	-2,533	14,95,278	16,89,877
3. जमाराशियाँ	99,00,766	1,07,17,362	47,91,279	54,64,181	7,76,266	8,45,482	1,09,472	1,45,731	2,543	9,954	1,55,80,325	1,71,82,709
3.1. मांग जमाराशियाँ	6,84,451	7,23,259	6,82,092	7,83,883	2,37,412	2,78,677	3,964	5,770	19	2,155	16,07,938	17,93,745
3.2. बचत बैंक जमाराशियाँ	34,62,923	38,20,484	14,55,976	17,47,958	87,032	92,120	22,198	43,577	2,524	7,799	50,30,653	57,11,938
3.3. मीयादी जमाराशियाँ	57,53,392	61,73,618	26,53,211	29,32,339	4,51,821	4,74,685	83,310	96,384	-	-	89,41,734	96,77,026
4. उधार	7,17,410	7,51,236	6,25,683	7,57,261	1,02,331	1,27,467	27,828	27,011	198	307	14,73,450	16,63,283
5. अन्य देयताएँ और प्रावधान	4,02,154	4,39,034	2,66,835	3,10,584	1,65,928	1,54,070	6,081	7,991	737	5,666	8,41,734	9,17,346
कुल देयताएँ/ आस्तियाँ	1,17,28,799	1,27,06,661	64,21,784	73,71,715	12,60,682	13,68,521	1,63,557	2,03,076	4,072	17,681	1,95,78,895	2,16,67,655
	(59.9)	(58.6)	(32.8)	(34.0)	(6.4)	(6.3)	(0.8)	(0.9)	(0.0)	(0.1)	(100.0)	(100.0)
1. आरबीआई में धारित नकदी और शेष	5,39,149	6,22,619	2,90,509	3,93,531	1,10,723	1,43,273	6,921	8,725	196	1,484	9,47,498	11,69,632
2. बैंको के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	5,91,125	6,42,484	2,75,256	3,33,745	1,02,108	1,17,739	12,309	10,212	790	3,273	9,81,588	11,07,452
3. निवेश	34,00,895	35,95,647	15,12,480	16,26,725	4,69,712	5,05,001	30,660	41,661	2,413	9,937	54,16,159	57,78,971
3.1. सरकारी प्रतिभूतियों में (ए+बी) ए) भारत में	27,70,643	29,32,482	12,36,660	13,50,959	3,86,490	3,98,009	27,142	36,683	2,412	9,924	44,23,347	47,28,057
बी) भारत के बाहर	37,292	43,456	20,476	17,735	33,651	49,575	-	-	-	-	91,418	1,10,765
3.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5
3.3. गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में	5,92,949	6,19,704	2,55,345	2,58,031	49,570	57,417	3,517	4,978	1	13	9,01,382	9,40,144
4. ऋण और अग्रिम	63,47,417	70,43,940	39,29,572	45,62,780	4,20,780	4,65,484	1,08,613	1,35,802	0	2	1,08,06,381	1,22,08,009
4.1. खरीदे और भुनाए गए बिल	1,45,894	2,33,191	1,19,295	1,50,703	60,380	64,595	124	585	-	-	3,25,694	4,49,074
4.2. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	24,90,604	26,61,563	11,46,858	13,62,842	1,79,873	2,01,228	8,929	12,582	-	-	38,26,263	42,38,214
4.3. मीयादी ऋण	37,10,919	41,49,187	26,63,419	30,49,235	1,80,527	1,99,661	99,560	1,22,636	0	2	66,54,424	75,20,720
5. अचल आस्तियाँ	1,06,826	1,09,784	39,714	44,456	4,457	4,964	1,676	2,001	222	370	1,52,895	1,61,575
6. अन्य आस्तियाँ	7,43,389	6,92,188	3,74,253	4,10,478	1,52,903	1,32,061	3,378	4,674	452	2,615	12,74,374	12,42,015

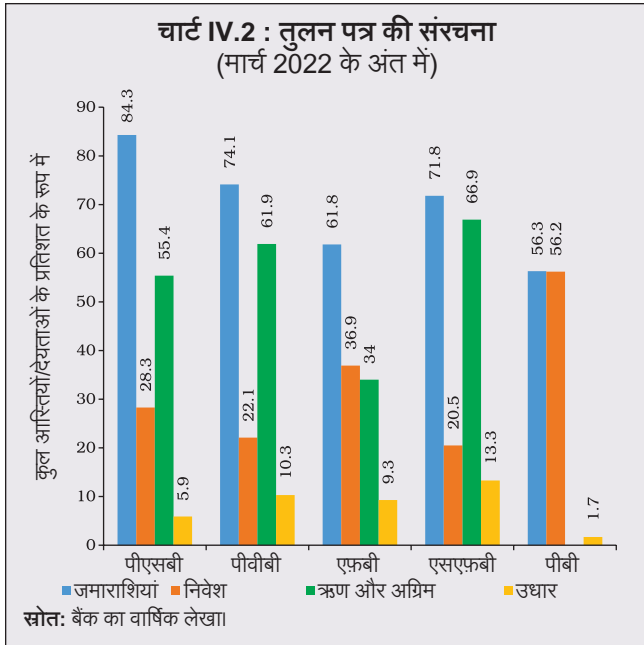
टिप्पणी: 1. शून्य/ नगण्य।

2. संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण घटकों का योग उनके संबंधित योग से भिन्न हो सकता है।

3. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा एकत्र किया जाता है और भारत में बैंकिंग से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों में प्रकाशित किया जाता है। जो <https://www.dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सभी एससीबी में विभिन्न बैंक समूह की कुल आस्तियों/देयताओं का हिस्सा है।

स्रोत : संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।



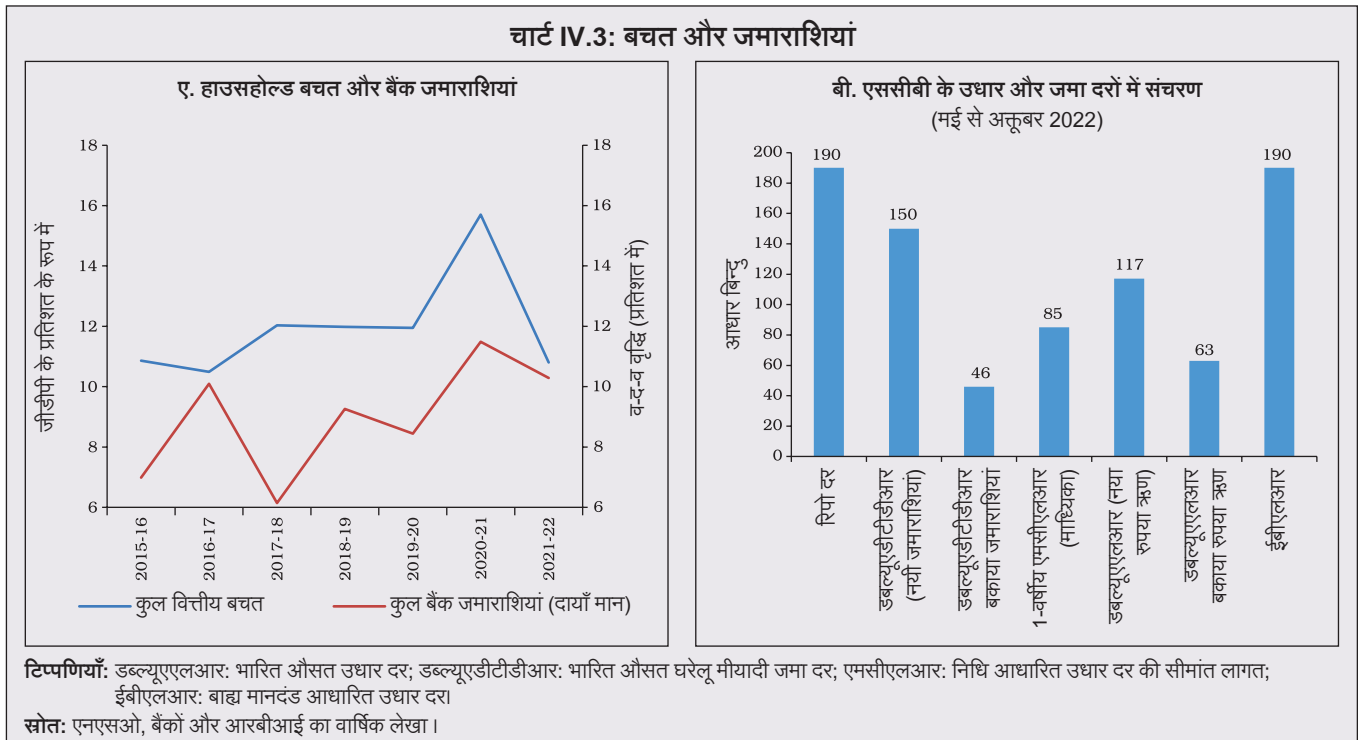
IV.5 बैंक समूहों में तुलन पत्र संरचना पर करीब से नज़र डालने से उनकी परिचालन जटिलताओं पर प्रकाश पड़ता है। कुल देयताओं में जमा राशि के हिस्से के रूप में परिभाषित जमा - वित्त पोषण अनुपात, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में

पीएसबी के लिए अधिक है। इससे पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंक ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उधार का सहारा लेते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि पीवीबी की तुलना में पीएसबी का ऋण-आस्तित्व अनुपात ऐतिहासिक रूप से कम रहा है, इसका निवेश-आस्तित्व अनुपात अधिक रहा है, जो जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में उच्च निवेश को दर्शाता है (चार्ट IV.2)।

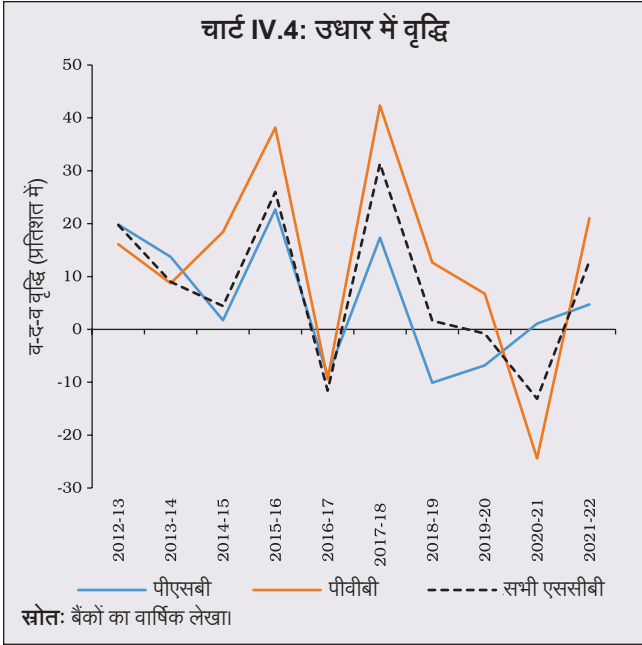
2.1. देयताएं

IV.6 घरेलू वित्तीय बचत दरें 2021-22 में घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गईं, जो कम जमा वृद्धि (चार्ट IV.3ए) में भी परिलक्षित हुई थी। जमा दरों में मई-अक्तूबर 2022 के दौरान रेपो दर में 190 आधार अंक (बीपीएस) के संचयी वृद्धि का संचरण होने पर, जमा वृद्धि दरों को बढ़ावा मिलने की संभावना है (चार्ट IV) 3बी)।

IV.7 2021-22 में एससीबी की उधारी में तेजी आई, क्योंकि जमा वृद्धि में ऋण मांग के साथ संतुलन बनाए नहीं रख सकी (चार्ट IV.4)। यह, उच्च वैधानिक आरक्षित अपेक्षाओं¹ के साथ



चार्ट IV.4: उधार में वृद्धि



जुड़ी हुई है, जिसमें प्रणाली से स्थायी चलनिधि की निकासी हुई, जिसने पीवीबी और विदेशी बैंकों (एफबी) को उधारी के लिए प्रेरित किया।

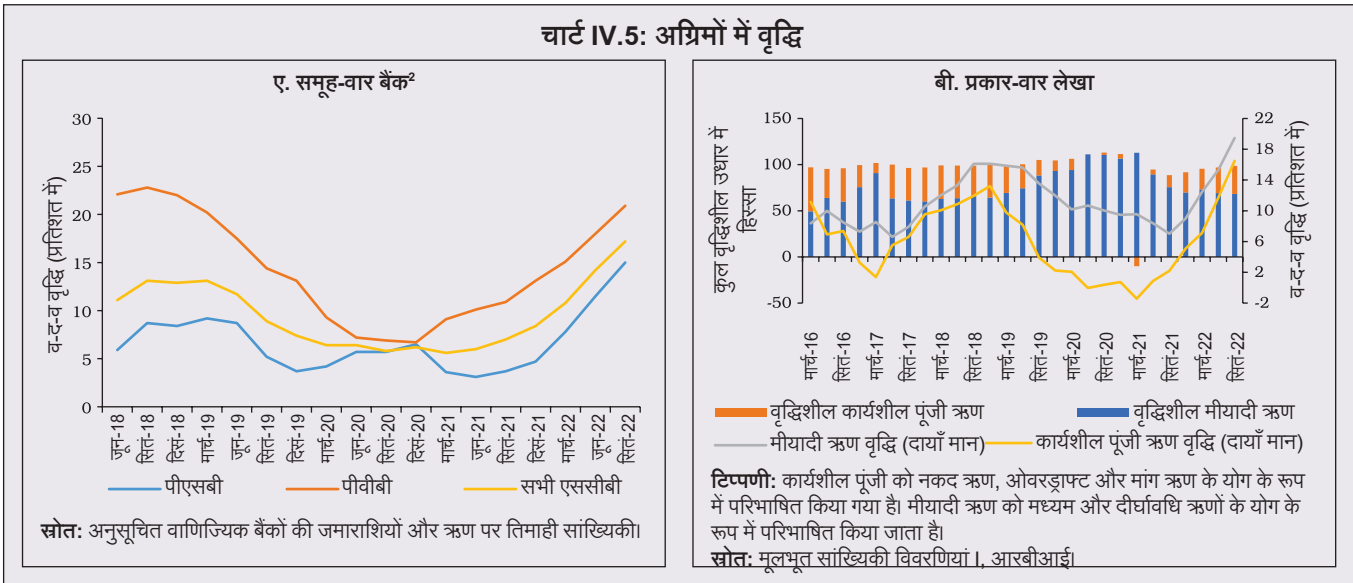
2.2. आस्तियां

IV.8 पीवीबी (चार्ट IV.5ए) के नेतृत्व में सितंबर 2022 की समाप्ति को ऋण वृद्धि दस वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण, जो 2018-19 की चौथी तिमाही से कम हो रहे थे, ने 2021-22 के दौरान स्थिर वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान वृद्धिशील ऋण का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा सावधि उधार के रूप में था, जो 10-तिमाही की उच्च गति से बढ़ा (चार्ट IV.5बी)।

IV.9 ऐतिहासिक रूप से, महानगरीय क्षेत्रों ने वृद्धिशील ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया है। हालांकि, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उच्च ऋण प्रवाह के कारण मार्च 2021 के अंत तक उनकी हिस्सेदारी घटकर 20 प्रतिशत रह गई। इसके बाद, जैसे-जैसे ऋण प्रवाह में पुनः वृद्धि हुई, महानगरीय क्षेत्रों ने अपना हिस्सा फिर से हासिल कर लिया (चार्ट IV.6)।

IV.10 एससीबी का लगभग 80 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में होता है और बैंकों की समग्र जी-सेक

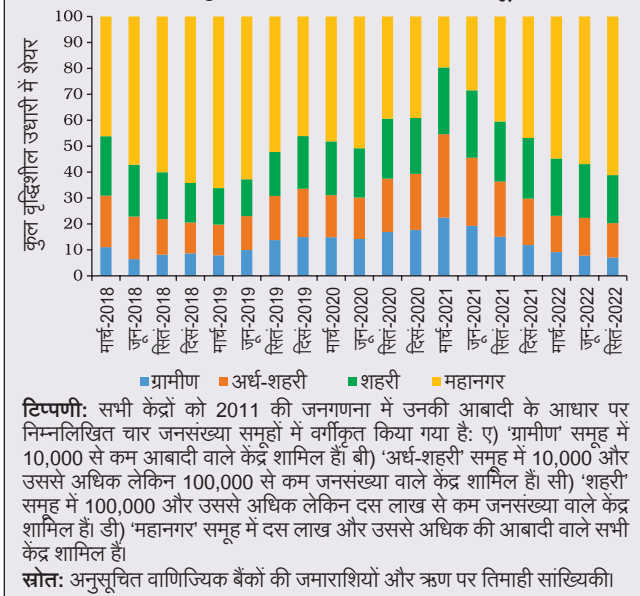
चार्ट IV.5: अग्रिमों में वृद्धि



¹ नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 22 मई, 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बाद, इसे 21 मई, 2022 से एनडीटीएल के 4.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

² आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 21 जनवरी, 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, मार्च 2019 के दौर से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समूह से बाहर रखा गया है और निजी क्षेत्र के बैंक समूह में शामिल किया गया है। 'लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड' (एक निजी क्षेत्र का बैंक) को 27 नवंबर, 2020 से 'डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड' (एक विदेशी बैंक) के साथ समामेलित किया गया था।

चार्ट IV.6: वृद्धिशील ऋण- जनसंख्या समूह-वार



धारिता ऋण मांग की स्थिति, जी-सेक की मांग-आपूर्ति गतिशीलता और ब्याज दर चक्र जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) हेतु पात्र प्रतिभूतियों के लिए बढ़ी हुई एचटीएम सीमाओं के विशेष वितरण ने बैंकों के लिए ऐसी प्रतिभूतियों³ में निवेश करने के लिए अधिक गुंजाइश बन गई थी। इन कारकों के मेल को दर्शाते हुए, सभी बैंक

समूहों में एससीबी के एसआरएल निवेश में वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

IV.11 2021-22 के दौरान चूँकि ऋण वृद्धि में तेजी आई और जमा वृद्धि में गिरावट आई, वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। निवेश में कमी के साथ ही वृद्धिशील निवेश-जमा (आई-डी) अनुपात में गिरावट आई (चार्ट IV.7)। आने वाले समय में उच्च नीतिगत ब्याज दर का जमा दरों तक पूर्ण संचरण करने से ऋण मांग को पूरा करने के लिए जमा प्रवाह में वृद्धि की संभावना है।

2.3. आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल

IV.12 परिपक्वता परिवर्तन बैंकिंग व्यवसाय का सार है, और आस्ति-देयता परिपक्वता असंतुलन अपरिहार्य हैं क्योंकि बैंक अल्पकालिक जमा के बदले दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। हालांकि, 2021-22 के दौरान, परिपक्वता असंतुलन पिछले वर्ष की तुलना में सभी अवधियों में कम रहा, जो आस्ति-देयता प्रबंधन में सुधार को दर्शाता है (चार्ट IV.8)।

IV.13 बैंकों ने, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के, 2021-22 में उस वर्ष कम ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए अल्पकालिक उधारी⁴

सारणी IV.2: एससीबी के निवेश (मार्च के अंत में)

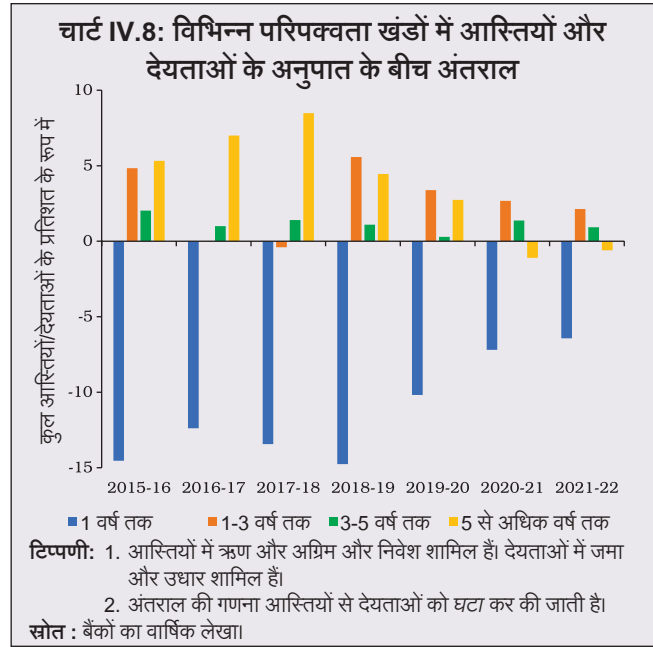
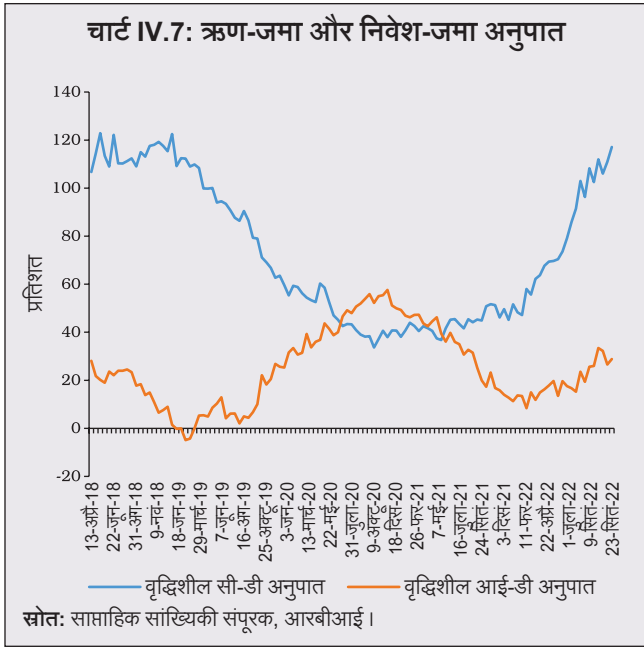
(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल निवेश (ए+बी)	34.09.289	36.03.007	15.21.942	16.32.570	4.49.403	4.77.085	30.709	41.695	54.11.343	57.54.358
ए. एसएलआर निवेश (I+II+III)	26.05.240	27.87.114	12.28.288	13.40.152	3.87.308	4.06.226	27.192	36.711	42.48.027	45.70.203
I. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.06.247	16.58.556	10.22.461	11.00.902	3.84.439	4.03.539	20.484	28.223	30.33.632	31.91.220
II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	9.96.676	11.26.852	2.05.826	2.39.249	2.869	2.687	6.708	8.487	12.12.080	13.77.276
III. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	2.316	1.707	0	0	0	0	0	0	2.316	1.707
बी. गैर-एसएलआर निवेश (I+II)	8.04.049	8.15.893	2.93.654	2.92.419	62.095	70.858	3.517	4.985	11.63.316	11.84.154
I. कर्ज प्रतिभूतियाँ	7.56.313	7.61.390	2.76.043	2.75.903	61.645	70.482	3.498	4.922	10.97.499	11.12.698
II. इक्विटी	47.736	54.503	17.610	16.515	450	376	20	62	65.817	71.456

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई

³ वाणिज्यिक बैंकों को 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच अधिग्रहित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) वाली पात्र प्रतिभूतियों के लिए निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) सीमा की प्रारंभिक विशेष छूट दी गई थी। इस सीमा को अप्रैल 2022 में बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसे जून 2023 के अंत से धीरे-धीरे समाप्त किया जाना है।

⁴ लघु-अवधि को 1 वर्ष तक, जबकि दीर्घ-अवधि को 3 वर्ष से अधिक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।



बढ़ाई। पीवीबी और एफबी का निवेश पोर्टफोलियो अल्पकालिक श्रेणी में केंद्रित है, जो इन बैंकों द्वारा

सक्रिय निवेश जोखिम प्रबंधन का संकेत देता है (सारणी IV.3)।

सारणी IV.3: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

आस्तियाँ/देयताएं	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एसएफबी		पीबी		सभी एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियां												
ए) 1 वर्ष तक	36.2	35.0	34.2	32.3	62.4	62.8	53.6	50.2	13.0	10.3	37.0	35.6
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	21.9	21.9	28.9	30.2	30.8	29.2	42.1	46.0	87.0	89.7	24.7	25.2
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.3	12.7	9.2	9.7	6.7	8.0	1.7	1.6	0.0	0.0	10.3	11.4
डी) 5 वर्ष से अधिक	30.6	30.5	27.7	27.8	0.05	0.05	2.6	2.2	0.0	0.0	28.0	27.9
II. उधार												
ए) 1 वर्ष तक	54.5	53.9	41.4	50.0	83.8	80.5	46.9	37.1	100.0	100.0	50.8	53.9
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	20.9	22.9	34.0	29.2	11.8	16.3	37.3	49.5	0.0	0.0	26.1	25.7
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12.7	14.0	13.9	11.5	1.9	1.6	13.8	9.2	0.0	0.0	12.5	11.8
डी) 5 वर्ष से अधिक	11.9	9.2	10.6	9.3	2.4	1.6	2.1	4.2	0.0	0.0	10.5	8.6
III. ऋण और अग्रिम												
ए) 1 वर्ष तक	24.8	25.2	32.1	30.6	55.8	53.3	41.8	38.2	100.0	100.0	28.8	28.4
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	36.9	35.4	34.2	33.8	22.2	24.3	34.0	35.8	0.0	0.0	35.3	34.4
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14.9	15.1	12.8	13.4	9.1	10.3	11.0	11.1	0.0	0.0	13.9	14.2
डी) 5 वर्ष से अधिक	23.4	24.4	20.9	22.3	12.9	12.1	13.2	14.9	0.0	0.0	22.0	23.0
IV निवेश												
ए) 1 वर्ष तक	23.7	25.2	50.7	48.8	84.9	83.2	58.1	53.8	97.4	98.7	36.8	37.3
बी) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	16.7	16.4	20.7	22.4	10.5	10.8	25.4	25.6	1.9	0.8	17.3	17.6
सी) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	13.2	13.2	6.5	7.8	2.3	2.5	2.9	4.9	0.4	0.1	10.3	10.7
डी) 5 वर्ष से अधिक	46.4	45.2	22.2	20.9	2.4	3.5	13.6	15.7	0.2	0.3	35.6	34.4

टिप्पणी: आंकड़े तुलन पत्र में प्रत्येक घटक में प्रत्येक परिपक्वता बकेट के हिस्से को दर्शाते हैं। पूर्णांकन के कारण घटकों का योग 100 नहीं हो सकता है।

स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

2.4. अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

IV.14 2021-22 के दौरान, भारत के पक्ष में ब्याज दर के अंतर से प्रोत्साहित होकर (परिशिष्ट सारणी IV.2), भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं, विशेष रूप से अनिवासी साधारण (एनआरओ) रूपए खातों और विदेशी मुद्रा उधारियों में काफी वृद्धि हुई। दूसरी ओर, ऋण और जमा तथा ऋण प्रतिभूतियों की धारिता के कारण अंतरराष्ट्रीय आस्ति में वृद्धि हुई थी। अनिवासियों को एक साल पहले की तुलना में ऋण कम हो गया, जबकि निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण और नोस्ट्रो जमा शेष में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.3)। इन कारकों को दर्शाते हुए, भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों देयताओं का अनुपात लगातार तीन वर्षों से बढ़ रहा है (चार्ट IV.9ए)।

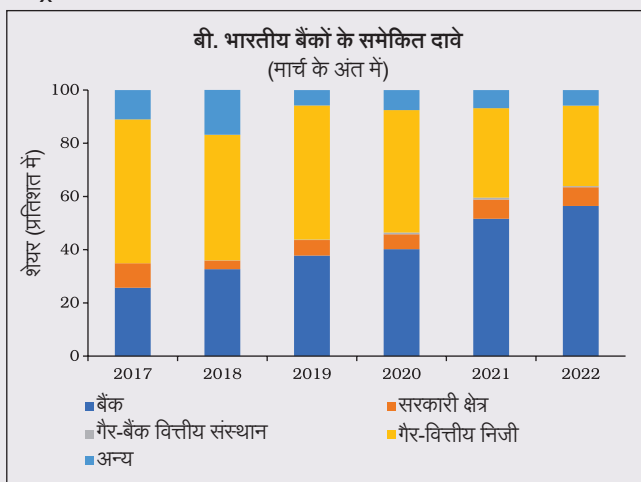
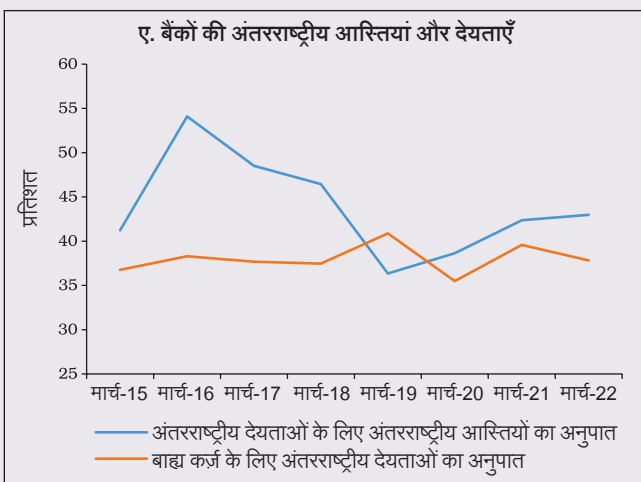
IV.15 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दावों का हिस्सा अर्थात्, विदेशी बैंकों को छोड़कर भारतीय बैंकों की घरेलू और विदेशी शाखाओं द्वारा विदेशों में रखी गई आस्तियां अल्पकालिक परिपक्वता की ओर

स्थानांतरित हो गईं और गैर-वित्तीय निजी संस्थानों से शिफ्ट होकर बैंकों की ओर चली गईं (परिशिष्ट सारणी IV.4 और चार्ट IV.9बी)। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस.) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय दावों की बैंकों की देश संरचना में भौगोलिक परिवर्तन हुए। (परिशिष्ट सारणी IV.5)।

2.5. तुलन-पत्र से इतर परिचालन

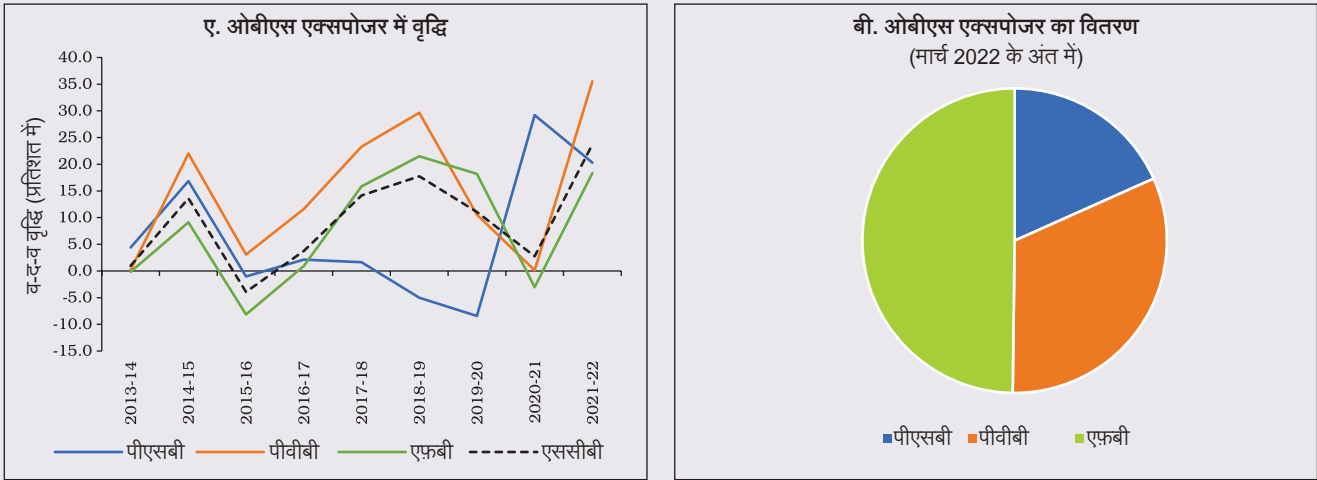
IV.16 अग्रिम विनिमय अनुबंधों, स्वीकृति और समर्थन में वृद्धि के कारण सभी एससीबी के लिए आकस्मिक देयताओं में 11 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि 23 प्रतिशत को पार कर गई (चार्ट IV.10ए)। तुलन पत्र आकार के अनुपात के रूप में, आकस्मिक देयताएं 2020-21 में 119 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 133 प्रतिशत हो गईं (परिशिष्ट सारणी IV.6)। एफबी की आकस्मिक देयताएं उनके तुलन पत्र आकार से 10 गुना अधिक हैं और बैंकिंग प्रणाली के कुल तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर का लगभग आधा हिस्सा हैं (चार्ट IV.10बी)। हालांकि, उनकी गैर-ब्याज आय उतनी नहीं बढ़ी है।

चार्ट IV.9: भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएँ और आस्तियां



स्रोत: बैंकों और डीबीआईई का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.10: बैंकों की तुलनपत्रेतर देयताएँ



स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

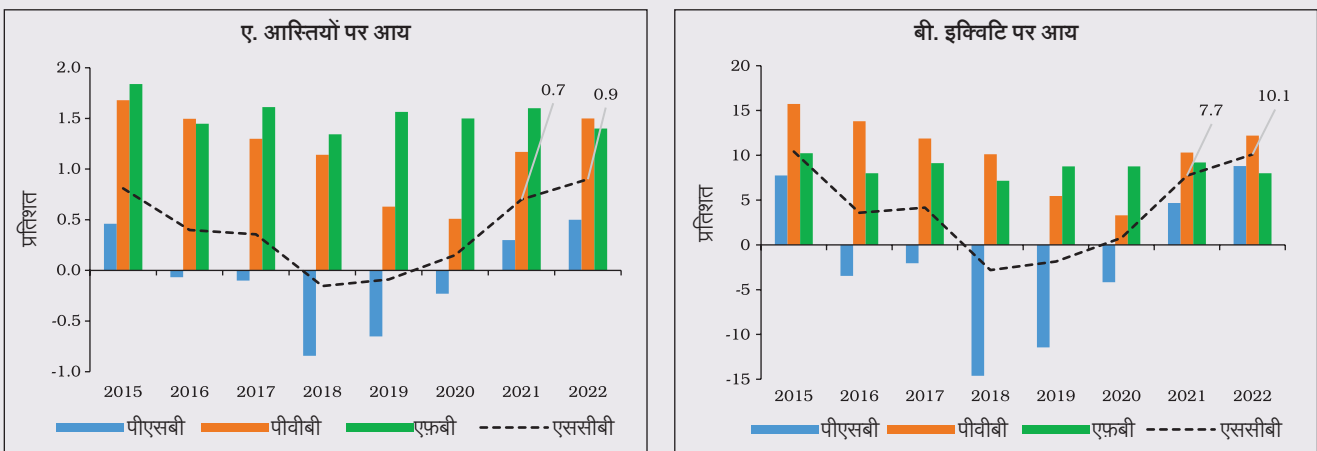
3. वित्तीय प्रदर्शन

IV.17 आस्ति निर्धारण में अधिक पारदर्शिता और मजबूत पूंजी और प्रावधान बफर के कारण बैंकों ने मजबूती के साथ महामारी का सामना किया। पोर्टफोलियो विविधीकरण के साथ-साथ ऋण निगरानी प्रक्रियाओं में वृद्धि ने हानि रोकने में मदद की और उनके तुलन पत्र को सशक्त बनाया। तदनुसार, इक्विटी पर आय और आस्तियों पर आय

(आरओए) के संदर्भ में मापे जाने वाले एससीबी की लाभप्रदता, 2014-15 में आखिरी बार देखे गए स्तरों तक सुधर गया (चार्ट IV.11)।

IV.18 सशक्त बैंक लाभप्रदता मजबूत वित्तीय प्रणाली का एक संकेतक है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि उच्च लाभप्रदता लीवरेज बाधाओं को कम कर सकती है और अधिक जोखिम लेने⁵ का

चार्ट IV.11: लाभप्रदता अनुपात (मार्च अंत में)



स्रोत: बैंकों और डीबीआई का वार्षिक लेखा, आरबीआई।

⁵ जू, तेंगतेंग और हू, कुन और दास, उदयबीर, (2019)। बैंक लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता। आईएमएफ वर्किंग पेपर। 19. 1. 10.5089/9781484390078.001.

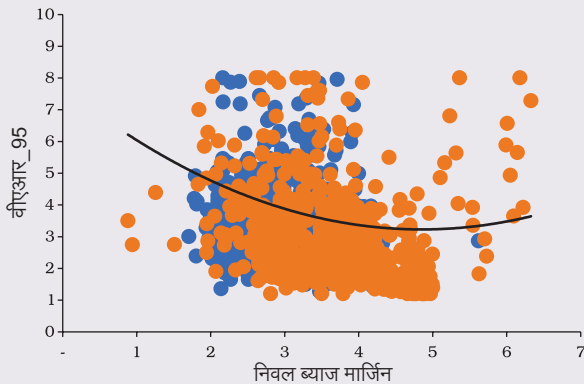
कारण बन सकती है। भारत के लिए अनुभवजन्य अनुमान एक सीमा के अस्तित्व में होने की सूचना देते हैं जिसके पार उच्च बैंक लाभप्रदता वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती

है (बॉक्स IV.1)। मार्च 2022 के अंत में एससीबी का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.9 प्रतिशत था, जो उक्त सीमा से काफी नीचे बना हुआ है।

बॉक्स IV.1: वित्तीय स्थिरता पर बैंक की लाभप्रदता का प्रभाव

शास्त्रों के अनुसार, वित्तीय स्थिरता का पता इक्विटी कीमतों के ऐतिहासिक जोखिम मूल्य (वीएआर) द्वारा मापे गए विशेष प्रकार के जोखिम द्वारा लगाया जाता है (जू, हू और दास, 2019)। इसके लिए 2008-2019⁶ की अवधि के लिए 24 बैंकों के तिमाही स्टॉक विवरणियों के डेटा का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित प्रभाव पैनेल सीमा प्रतिगमन के माध्यम से एनआईएम के उस सीमा मूल्य का आकलन किया जाता है जिसके ऊपर उच्च लाभ वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। परिणाम एनआईएम और वित्तीय स्थिरता के बीच एक गैर-रैखिक संबंध का सुझाव देते हैं (चार्ट 1)। इसका तात्पर्य यह है कि एक सीमा से अधिक एनआईएम का वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एनआईएम का अंतर्जात रूप से निर्धारित सीमा मूल्य लगभग 5 प्रतिशत बैठता है⁷। बैंकों के सीआरएआर, जीएनपीए, कुल आस्तियों के लॉग द्वारा मापे गए आकार, अल्पावधि ब्याज दर (कॉल दर) और जीडीपी को नियंत्रित करने के बाद भी यह परिणाम मजबूत बना हुआ है (सारणी 1)।

चार्ट 1: बैंक की निवल ब्याज मार्जिन और वीएआर_95: 2008-2019



टिप्पणी: नीले रंग के निशान पीएसबी को दर्शाते हैं, और नारंगी रंग के निशान पीवीबी को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना।

संदर्भ :

Claudiu Tiberiu Albuлесcu, Banks' Profitability and Financial Soundness Indicators: A Macro-level Investigation in Emerging Countries, *Procedia Economics and Finance*, Volume 23, 2015, Pages 203-209, ISSN 2212-5671, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00551-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00551-1).

Zicchino, Lea & Tsomocos, Dimitrios & Segoviano, Miguel & Goodhart, Charles & Bracon, Oriol. (2006). Searching for a Metric for Financial Stability. *Financial Markets Group, FMG Special Papers*.

सारणी 1: दो पद्धतियों के साथ पैनेल सीमा प्रतिगमन मॉडल का अनुमान

मॉडल	(1)	(2)
निर्भर चर	वीएआर_एच	वीएआर_95
सीमा	5.0011 (पी मान = 0.00)	5.0011 (पी मान = 0.00)
एनआईएम		
β_1	-0.130* (0.0756)	-0.213*** (0.0811)
β_2	0.153** (0.0729)	0.0568 (0.0782)
नियंत्रण चर		
सीआरएआर	-0.0371 (0.0227)	-0.0667*** (0.0244)
जीएनपीए	0.0275*** (0.00813)	0.0541*** (0.00872)
लॉग कुल आस्तियां	-0.358*** (0.117)	-0.313** (0.125)
एफसी (डमी चर)	1.757*** (0.133)	2.020*** (0.143)
कॉल दर	0.222*** (0.0198)	0.198*** (0.0213)
जीडीपी वृद्धि	-0.0332*** (0.0102)	-0.0276** (0.0109)
स्थिर	6.983*** (1.555)	7.484*** (1.667)
अवलोकन	1.152	1.152
आर-वर्गित	0.430	0.430
बैंकों की संख्या	24	24
प्रक्रियाओं की संख्या	500	500
समस्या>एफ	0	0

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में मानक त्रुटियाँ

2. *** पी <0.01, ** पी <0.05, * पी <0.11

3: एफसी एक संकेत डमी को संदर्भित करता है, जो वर्ष 2008 और 2009 के लिए 1 मान लेता है, और अन्यथा 0।

⁶ 2019 के बाद की अवधि में कई बैंक विलय हुए, जिससे नियमित समय शृंखला डेटा की उपलब्धता बाधित हुई। इसे देखते हुए, विश्लेषण 2008-2019 की अवधि तक सीमित है।

⁷ इष्टतम एनआईएम के लिए 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल (4.9733, 5.2333) है। यह परीक्षण करते हुए कि क्या इस गैर-रैखिक संबंध में एक से अधिक सीमा है, बूटस्ट्रैप पी-मान को महत्वपूर्ण नहीं पाए जाने के कारण दो और अधिक संख्या में सीमाओं की परिकल्पनाओं को निरस्त कर दिया गया था।

IV.19 वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च लाभ में आय में वृद्धि और व्यय में संकुचन का योगदान रहा है (सारणी IV.4)। एससीबी की कुल आय का 84 प्रतिशत ब्याज से प्राप्त आय है, जिसने एक वर्ष पहले अनुभव किए गए संकुचन को उलट दिया। उच्च उधार और निवेश की मात्रा के कारण इन चैनलों से उच्च ब्याज आय प्राप्त हुई, भले ही उस समय ब्याज दरें कम रहीं। ब्याज में कमी और कम प्रावधानों और आकस्मिकताओं के कारण व्यय में कमी हुई।

IV.20 भारत में आमतौर पर, जी-सेक प्रतिफल और बैंकों की गैर-ब्याज आय के बीच एक विपरीत संबंध देखा जाता है (चार्ट IV.12)। वर्ष के दौरान पीएसबी और एफबी की अन्य आय में गिरावट आई, जो आंशिक रूप से उनके निवेश

पोर्टफोलियो पर हुई ट्रेडिंग हानि को दर्शाता है। इसके विपरीत, पीवीबी की अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से कमीशन और ब्रोकरेज आय में वृद्धि से हुई थी, जो गैर-ब्याज आय का 60 प्रतिशत से अधिक है।

IV.21 दुनिया भर में जारी समकालिक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का बैंक लाभप्रदता के विभिन्न घटकों जैसे निवल ब्याज आय, गैर-ब्याज आय और ऋण हानि प्रावधानों पर असममित प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज दर में वृद्धि से निवल ब्याज आय में वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर, चूंकि बैंकों को प्रतिफल बढ़ने की स्थिति में अपने राजकोषीय निवेश पर ट्रेडिंग हानि उठानी पड़ती है, इसलिए उनकी गैर-ब्याज आय में कमी हो सकती है। इन हानियों के साथ-साथ एनपीए के लिए प्रावधान

सारणी IV.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय में रुझान

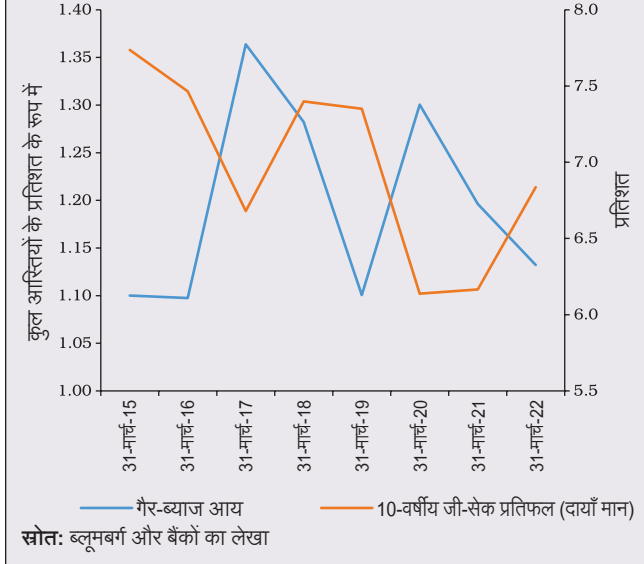
(राशि ₹ करोड़ में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक		लघु वित्त बैंक		भुगतान बैंक		सभी एससीबी	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1. आय	8,30,345	8,31,900	5,42,035	5,72,397	80,356	79,498	22,418	25,060	1,004	4,952	14,76,159	15,13,806
	(-0.5)	(0.2)	(-0.8)	(5.6)	(-3.4)	(-1.1)	(16.6)	(11.8)	(1733.5)	(393.2)	(-0.5)	(2.6)
ए) ब्याज आय	7,07,201	7,09,132	4,51,439	4,70,943	63,688	65,837	19,523	22,120	101	446	12,41,953	12,68,479
	(-1.3)	(0.3)	(0.5)	(4.3)	(-4.5)	(3.4)	(15.2)	(13.3)	(120.1)	(343.3)	(-0.6)	(2.1)
बी) अन्य आय	1,23,144	1,22,768	90,596	1,01,454	16,669	13,660	2,894	2,940	903	4,505	2,34,206	2,45,327
	(4.3)	(-0.3)	(-6.9)	(12.0)	(0.7)	(-18.0)	(27.4)	(1.6)	(9931.3)	(398.7)	(-0.03)	(4.7)
2. व्यय	7,98,527	7,65,360	4,72,559	4,76,174	61,391	61,113	20,380	24,087	1,304	5,041	13,54,161	13,31,774
	(-7.2)	(-4.2)	(-10.4)	(0.8)	(-8.4)	(-0.5)	(18.1)	(18.2)	(235.4)	(286.6)	(-8.0)	(-1.7)
ए) खर्च किया गया ब्याज	4,31,627	4,11,181	2,32,370	2,24,235	21,560	21,482	9,122	9,513	55	156	6,94,735	6,66,566
	(-7.8)	(-4.7)	(-9.9)	(-3.5)	(-25.2)	(-0.4)	(15.1)	(4.3)	(307.7)	(181.4)	(-8.9)	(-4.1)
बी) परिचालन व्यय	2,03,855	2,20,091	1,30,451	1,56,613	22,334	24,969	7,549	9,816	1,251	4,882	3,65,440	4,16,371
	(5.8)	(8.0)	(3.0)	(20.1)	(3.5)	(11.8)	(5.6)	(30.0)	(156.6)	(290.3)	(4.8)	(13.9)
जिनमें से: वेतन बिल	1,24,612	1,32,747	50,280	58,851	7,891	9,178	4,304	5,305	398	788	1,87,485	2,06,870
	(7.6)	(6.5)	(6.2)	(17.0)	(0.2)	(16.3)	(12.9)	(23.3)	(50.6)	(98.1)	(7.0)	(10.3)
सी) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,63,045	1,34,088	1,09,737	95,326	17,498	14,662	3,709	4,758	-2	3	2,93,987	2,48,837
	(-18.3)	(-17.8)	(-23.0)	(-13.1)	(5.1)	(-16.2)	(70.8)	(28.3)			(-18.5)	(-15.4)
3. परिचालन लाभ	1,94,863	2,00,628	1,79,214	1,91,549	36,463	33,047	5,747	5,732	-302	-87	4,15,985	4,30,869
	(12.3)	(3.0)	(10.9)	(6.9)	(11.1)	(-9.4)	(38.8)	(-0.3)			(11.9)	(3.6)
4. निवल लाभ	31,818	66,540	69,477	96,223	18,965	18,385	2,038	974	-300	-90	1,21,998	1,82,032
	-	(109.1)	(263.5)	(38.5)	(17.2)	(-3.1)	(3.5)	(-52.2)			(1018.1)	(49.2)
5. स्प्रेड (शून्य)	2,75,574	2,97,950	2,19,069	2,46,708	42,128	44,356	10,401	12,608	45	290	5,47,218	6,01,912
	(11.0)	(8.1)	(14.7)	(12.6)	(11.3)	(5.3)	(15.3)	(21.2)	(40.7)	(541.7)	(12.6)	(10.0)
6. निवल ब्याज सीमा	2.45	2.44	3.58	3.58	3.30	3.37	7.02	6.88	1.58	2.67	2.91	2.92

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत भिन्नताओं को दर्शाते हैं।
 2. प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
 3. एनआईएम को औसत आस्तित्व के प्रतिशत में एनआईआई के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा।

चार्ट IV.12: एससीबी का जी-सेक प्रतिफल और गैर-ब्याज आय



बढ़ाने से लाभप्रदता और कम हो सकती है। बैंकों की लाभप्रदता पर मौद्रिक नीति का निवल प्रभाव इस प्रकार एक अनुभवजन्य समस्या है (बॉक्स IV.2)।

IV.22 ब्याज व्यय के कारण एससीबी के कुल व्यय में संकुचन हुआ, जिसमें कम जमा दरों के कारण गिरावट आई। चूंकि जमा राशि एफबी के तुलन पत्र का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, इसलिए कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उनका ब्याज व्यय अन्य दो बैंक समूहों की तुलना में कम है (चार्ट IV.13 ए)। दूसरी ओर, लागत-आय अनुपात, जो परिचालन आय के लिए परिचालन व्यय का अनुपात है, पीएसबी के लिए उनके उच्च वेतन व्यय के कारण सबसे अधिक था (चार्ट IV.13 बी)।

IV.23 चूंकि बैंकों को महामारी के दौरान प्रदत्त अधिस्थगन के कारण निर्गत ऋणों पर उच्च प्रावधान बनाए रखने की

बॉक्स IV.2: बैंक की लाभप्रदता पर मौद्रिक नीति का प्रभाव

2010-2021 की अवधि के लिए ब्रिक्स देशों के 234 बैंकों पर एक वार्षिक डेटासेट के साथ विभिन्न समष्टि-आर्थिक कारकों जैसे कि अल्पावधिक ब्याज दरें, प्रतिफल, जीडीपी और मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति और बैंक लाभप्रदता के बीच संबंध का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया था⁸। गुडहार्ट (2019) के अनुरूप, अल्पावधिक ब्याज दरों को ओवरनाइट सूचकांक स्वेप (ओआईएस)⁹ द्वारा अनुमानित किया गया था। प्रतिफल वक्र का झुकाव—जिसकी गणना 10-वर्ष और दो-वर्षीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के बीच के अंतर के रूप में की जाती है, इसका उपयोग ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के बारे में अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

एक निश्चित प्रभाव पैनाल प्रतिगमन के परिणाम बैंकों के आरओए और अल्पावधिक ब्याज दरों के बीच अवतल संबंध का सुझाव देते हैं। इसी तरह का संबंध आरओए और प्रतिफल वक्र के स्लोप के बीच भी देखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक सीमा तक, गैर-ब्याज आय और प्रावधानों पर नीतिगत दरों में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव निवल ब्याज आय पर सकारात्मक प्रभाव से अधिक है। बैंक-विशिष्ट कारक भी लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते पाए जाते हैं। एक उच्च कुल आस्तियों के लिए इक्विटी अनुपात और एक बड़ा आस्तित्व आकार उच्च लाभप्रदता से जुड़ा हुआ था। बैंक लाभप्रदता पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का प्रभाव सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है (सारणी 1)।

पार-देशीय साक्ष्य बताते हैं कि, बैंकों के आरओए अल्पावधि दरों के साथ प्रतिफल वक्र के स्लोप के संबंध में गैर-रैखिक हैं।

सारणी 1: प्रतिगमन परिणाम

चर	निर्भर चर: आस्तियों पर प्रतिलाभ		
	(1)	(2)	(3)
निर्भर चर (-1)	0.244*** (0.0599)	0.235*** (0.0609)	0.148** (0.0598)
ओआईएस	0.168*** (0.0402)	0.108** (0.0438)	0.158** (0.0692)
ओआईएस ²	-0.00705** (0.00301)	-0.00415 (0.00304)	-0.00539 (0.00396)
प्रतिफल वक्र स्लोप	0.168*** (0.0571)	0.255*** (0.0663)	0.307*** (0.0816)
प्रतिफल वक्र स्लोप ²	-0.0642*** (0.0135)	-0.0753*** (0.0127)	-0.0816*** (0.0139)
कुल आस्तियों के लिए इक्विटी			0.110*** (0.0220)
आय के लिए लागत अनुपात			-0.00103 (0.00120)
कुल आस्तियों का लॉग			0.256* (0.140)
जीडीपी वृद्धि		0.0266*** (0.00805)	0.0207** (0.00912)
मुद्रास्फीति		0.0378 (0.0249)	0.0399 (0.0309)
स्थिर	0.127 (0.131)	0.0202 (0.118)	-3.757** (1.778)
अवलोकन	2.986	2.986	2.014
आर-वर्गित	0.411	0.414	0.452

कोष्ठक में मजबूत मानक त्रुटियां दी गई हैं।

*** पी < 0.01, ** पी < 0.05, * पी < 0.1

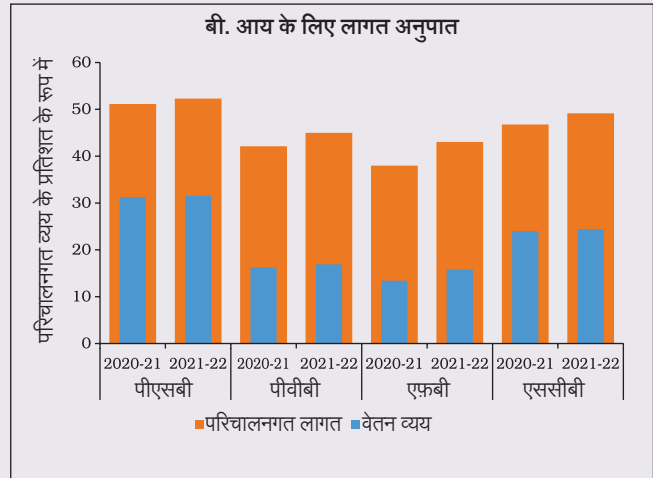
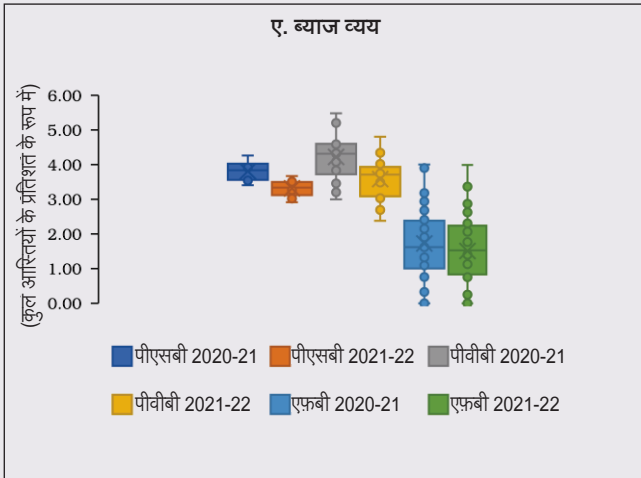
संदर्भ:

Goodhart, C. A., & Kabiri, A. (2019). *Monetary Policy and Bank Profitability in a Low Interest Rate Environment: A Follow-up and a Rejoinder*. Centre for Economic Policy Research.

⁸ बैंकिंग आंकड़ा बैंकर डेटाबेस से लिया गया है, जबकि वित्तीय और समष्टि-आर्थिक आंकड़े ब्लूमबर्ग और सीईआईसी से लिए गए हैं।

⁹ ब्राजील को छोड़कर तीन महीने के ओआईएस को संदर्भित करता है, जहां यह एक साल के ओआईएस से संबंधित है।

चार्ट IV.13: एससीबी का व्यय



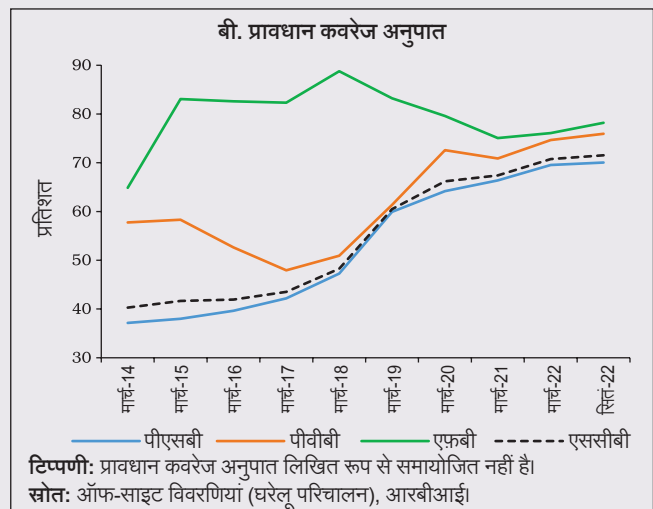
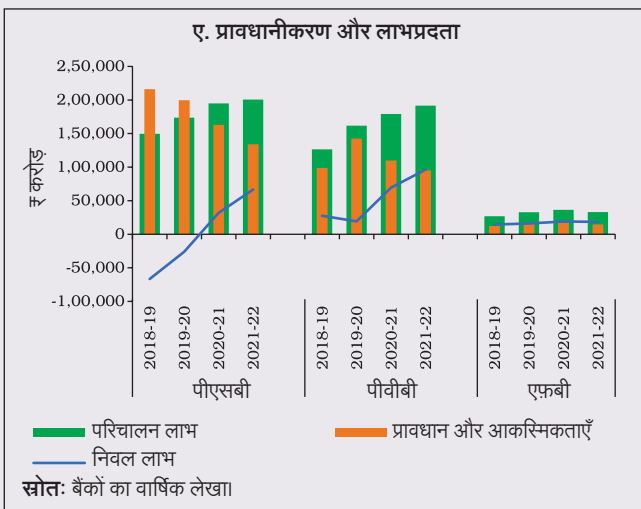
स्रोत: संबन्धित बैंकों का वार्षिक लेखा।

आवश्यकता थी, इसलिए 2019-20 और 2020-21 में उनका निवल लाभ बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2021-22 के दौरान, उन प्रावधानों को कम करने से बैंकों के निवल लाभ में वृद्धि हुई (चार्ट IV.14ए)। इसके अलावा, जैसे-जैसे जीएनपीए में गिरावट आई, प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई (चार्ट IV.14 बी)।

IV.24 चूंकि निधि पर आय में कमी निधि की लागत में कमी की तुलना में थोड़ी अधिक थी, इसलिए स्प्रेड में मामूली

गिरावट आई। कुल जमा में चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमा का हिस्सा बढ़ने से जमा की लागत कम हो गई। मार्च 2022 के अंत में एससीबी के बकाया अस्थिर दर वाले रुपये ऋण का 44 प्रतिशत हिस्सा बाह्य बेंचमार्क संबद्ध उधार दर (ईबीएलआर) पर था। पीएसबी और पीवीबी के लिए तुलनात्मक स्थिति क्रमशः 33 प्रतिशत और 62 प्रतिशत थी। मौजूदा अस्थिर दर वाले ऋण का उस समय की प्रचलित कम दरों पर पुनर्मूल्यांकन और कम दरों पर वृद्धिशील उधार

चार्ट IV.14: लाभप्रदता पर प्रावधानीकरण का प्रभाव



टिप्पणी: प्रावधान कवरेज अनुपात लिखित रूप से समायोजित नहीं है।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

सारणी IV.5: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

बैंक समूह/वार	वर्ष	जमाराशियों की लागत	उधार की लागत	निधियों की लागत	अग्रिमों पर प्रतिलाभ	निवेशों पर प्रतिलाभ	निधियों पर प्रतिलाभ	स्प्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5)
पीएसबी	2020-21	4.2	4.3	4.2	7.5	6.6	7.2	3.0
	2021-22	3.7	4.2	3.7	6.9	6.1	6.6	2.9
पीवीबी	2020-21	4.3	5.6	4.5	9.1	6.2	8.3	3.9
	2021-22	3.7	5.2	3.9	8.5	5.8	7.7	3.9
एफबी	2020-21	2.4	3.3	2.5	7.1	6.0	6.5	4.0
	2021-22	2.1	3.6	2.3	7.0	5.7	6.3	4.0
एसएफबी	2020-21	6.8	8.8	7.3	17.1	6.8	14.9	7.6
	2021-22	5.9	7.1	6.1	15.8	5.9	13.6	7.4
पीबी	2020-21	3.0	5.3	3.1	9.3	4.0	4.0	0.9
	2021-22	2.4	2.8	2.4	5.2	5.1	5.1	2.7
एससीबी	2020-21	4.2	4.9	4.2	8.1	6.4	7.6	3.4
	2021-22	3.6	4.6	3.7	7.6	6.0	7.0	3.3

टिप्पणी : 1. जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर दिया गया ब्याज /वर्तमान और पिछले वर्षों की जमाराशियों का औसत
 2. उधार की लागत = (व्यय किया गया ब्याज - जमा पर ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्षों के उधार का औसत
 3. निधियों की लागत = (खर्च किया गया ब्याज) / वर्तमान और पिछले वर्षों का औसत (जमा + उधार)
 4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के अग्रिमों का औसत
 5. निवेश पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्षों के निवेश का औसत
 6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिम पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज)/ वर्तमान और पिछले वर्षों का औसत (अग्रिम + निवेश)

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र से की गई गणना।

दिये जाने के कारण अग्रिमों पर आय में कमी आई है (सारणी IV.5)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

IV.25 2021-22 के दौरान, एससीबी की पूंजी की स्थिति, आस्ति गुणवत्ता वर्ष और लीवरेज अनुपात में सुधार हुआ तथा चलनिधि की स्थिति मजबूत बनी रही। रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत आने वाले बैंकों की

संख्या मार्च 2021 के अंत में तीन से घटकर मार्च 2022 के अंत में एक रह गई। सितंबर 2022 के अंत में पीसीए ढांचे के तहत कोई बैंक नहीं था।

4.1. पूंजी पर्याप्तता

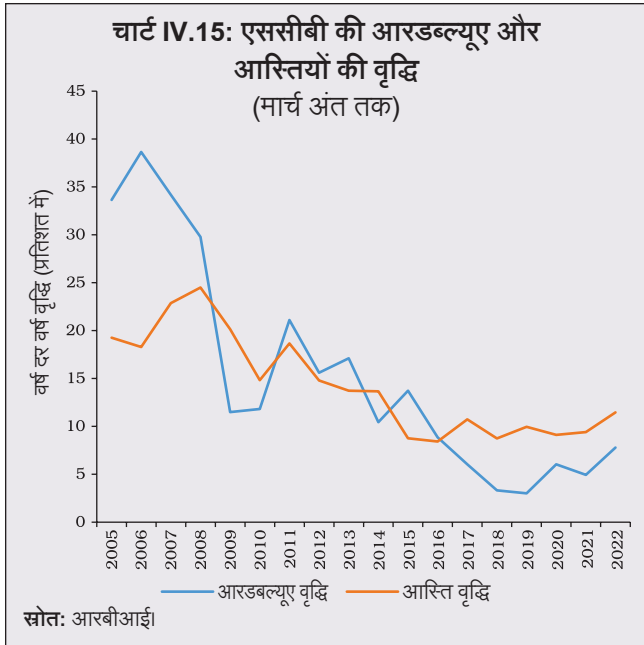
IV.26 आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) अवधि के पश्चात एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) क्रमिक रूप से बढ़ रहा है (सारणी IV.6)। जोखिम-

सारणी IV.6: एससीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता (मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी		एससीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1. पूंजीगत निधियां	7,93,971	8,93,870	7,72,389	8,80,664	2,04,433	2,19,844	17,90,330	20,15,443
i) टियर I पूंजी	6,49,082	7,35,753	7,01,622	8,06,457	1,86,369	2,01,196	15,54,796	17,62,613
ii) टियर II पूंजी	1,44,889	1,58,117	70,767	74,207	18,064	18,648	2,35,535	2,52,830
2. जोखिम भारित आस्तियां	56,56,060	60,84,930	41,92,303	46,92,169	10,49,878	11,09,568	1,08,98,241	1,18,86,667
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	14.0	14.7	18.4	18.8	19.5	19.8	16.3	16.8
जिनमें से: टियर I	11.7	12.7	16.9	17.1	17.7	18.2	14.1	15.7
टियर II	2.5	2.7	1.7	1.3	1.6	1.6	2.2	1.8

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, आरबीआई।



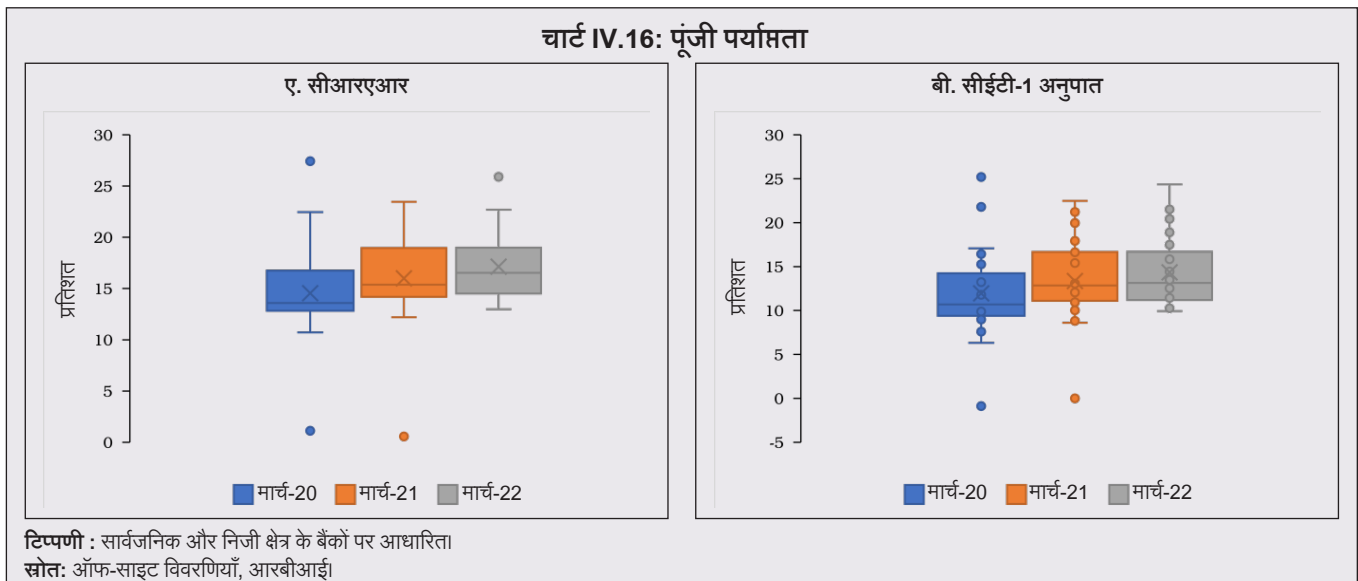
भारत आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के बावजूद, 2021-22 के दौरान इस वृद्धि ने गति बनाए रखी। 2016 के बाद से, आरडब्ल्यूए में वृद्धि समग्र आस्ति वृद्धि की तुलना में कम रही है, जो सुरक्षित आस्तियों की ओर एक कदम को दर्शाती है (चार्ट IV.15)। पूंजीगत निधियों में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि बैंकों की टियर -1 पूंजी में वृद्धि से हुई थी, जो पूंजी बफर की मजबूती का संकेत है। सितंबर 2022 के अंत में एससीबी का सीआरएआर 16 प्रतिशत था।

IV.27 अक्टूबर 2021 में, अंतिम शृंखला के सक्रिय होने के साथ, बैंकों द्वारा बनाए जाने वाले कुल पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, जिससे कुल न्यूनतम पूंजी आवश्यकता बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गई। मार्च 2022 के अंत में, सभी बैंकों ने इस नियामकीय न्यूनतम सीमा के साथ-साथ 8 प्रतिशत की सीईटी -1 अनुपात अपेक्षा को भी पूरा किया (चार्ट IV.16)।

IV.28 निजी आबंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा संसाधन जुटाना, जो 2020-21 में तेज हो गया था, 2021-22 के दौरान धीमा हो गया। हालांकि 2021-22 में पीवीबी के लिए निर्गमों की संख्या तीन गुणी हो गई, लेकिन जुटाई गई कुल राशि में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 में निजी तौर पर शेयर आबंटन के माध्यम से पीवीबी द्वारा जुटाए गए अधिकांश संसाधन बॉण्ड/ डिबेंचर के माध्यम से थे, जबकि 2020-21 के दौरान, यह पूरी तरह से इक्विटी जारी करने के माध्यम से था। (सारणी IV.7)।

4.2. लीवरेज और चलनिधि

IV.29 कुल एक्सपोजर के लिए टियर -1 पूंजी के अनुपात के रूप में गणना किया जाने वाला लीवरेज अनुपात (एलआर), जोखिम-भारित पूंजी आवश्यकताओं के लिए अंतिम न्यूनतम सीमा के रूप में कार्य करता है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण



सारणी IV.7: निजी आबंटन के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (नवंबर 2022 तक)	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
पीएसबी	20	29,573	36	58,697	29	50,719	13	27,234
पीवीबी	8	23,121	4	33,878	12	35,682	3	5,194
विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	1	125

टिप्पणी: 1. इसमें कर्ज का निजी आबंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत आबंटन शामिल है। 2022-23 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. -: शून्य/नगण्य।
स्रोत : बीएसई, एनएसई, व्यापारी बैंक और प्राइम डेटाबेस।

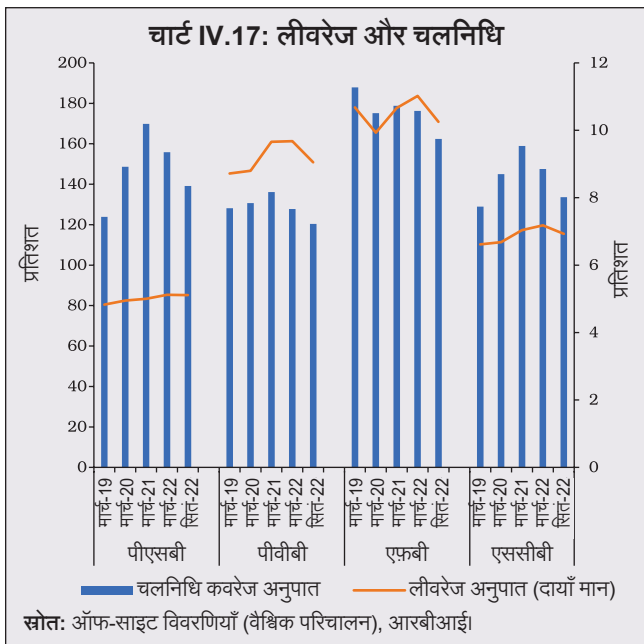
घरेलू बैंकों और अन्य बैंकों के लिए इसे क्रमशः न्यूनतम 4 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता है। मार्च 2022 के अंत में, सभी बैंक समूहों ने निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया। पीवीबी और एफबी ने एलआर को आवश्यक स्तरों से बहुत ऊपर बनाए रखा।

IV.30 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में कहा गया है कि बैंकों को दबाव वाली परिस्थितियों में 30 दिनों के निवल नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखना चाहिए। हालांकि सभी बैंक समूहों ने मार्च 2022 के अंत में 100 प्रतिशत एलसीआर की बेसल आवश्यकता को पूरा किया, लेकिन यह अनुपात एक साल पहले की तुलना में कम था (चार्ट IV.17)।

IV.31 निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) -- आवश्यक स्थिर वित्त पोषण के लिए उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण का अनुपात -- एक स्थायी वित्त संरचना का एक उपाय है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए एनएसएफआर का कार्यान्वयन 01 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी हो गया था। इसके साथ, बैंकों को एनएसएफआर को न्यूनतम 100 प्रतिशत पर बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे मार्च 2022 के अंत में सभी बैंक समूहों द्वारा पूरा किया गया था (सारणी IV.8)।

4.3. अनर्जक आस्तियां

IV.32 एनपीए, वसूली लागत को प्रभावित करने के अलावा, बढ़ते प्रावधान के माध्यम से बैंकों की लाभप्रदता, और उनकी पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एससीबी का जीएनपीए अनुपात 2017-18 के अपने सर्वाधिक स्तर से क्रमिक रूप से घटकर सितंबर 2022 के अंत में 5 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह गिरावट निम्न हानि के साथ-साथ वसूली और बट्टे खाते में डाले



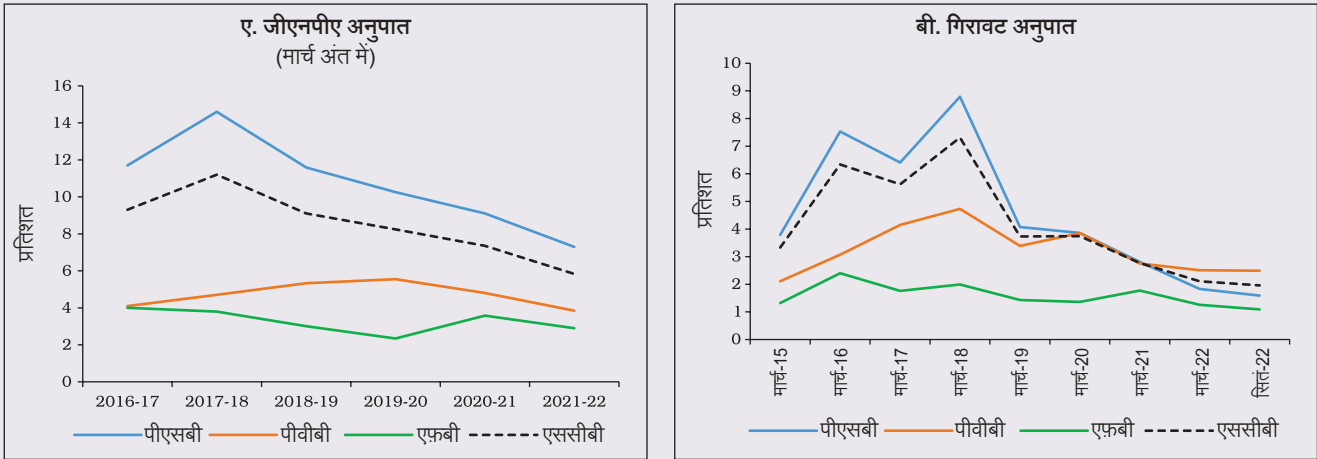
सारणी IV.8: निवल स्थिर निधीकरण अनुपात (मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	उपलब्ध स्थिर निधीकरण	आवश्यक स्थिर निधीकरण	एनएसएफआर (प्रतिशत)
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	93,46,181	69,40,125	134.7
निजी क्षेत्र बैंक	51,12,372	39,01,260	131.0
विदेशी बैंक समूह	5,71,172	4,15,495	137.5
लघु वित्त बैंक समूह-अनुसूचित	1,39,917	1,10,157	127.0
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,51,69,642	1,13,67,038	133.5

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, आरबीआई।

चार्ट IV.18: बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

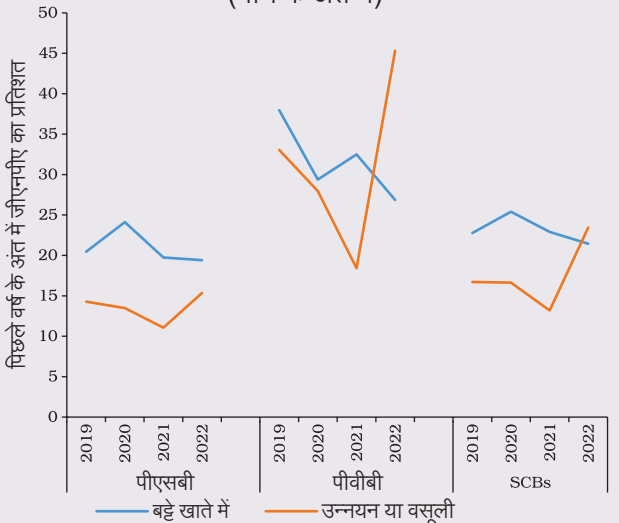


टिप्पणी: जीएनपीए अनुपात की गणना बैंकों के वार्षिक लेखे और ऑफ-साइट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) का उपयोग करके की जाती है।
स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन)।

जाने के पश्चात बकाया जीएनपीए में कमी के कारण हुई थी (चार्ट IV.18)।

IV.33 वर्ष 2021-22 में, एनपीए में कमी मुख्य रूप से पीएसबी के मामले में बड़े खाते में डाले गए ऋणों द्वारा दिये गए योगदान के कारण था, जबकि पीवीबी के लिए आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋणों का उन्नयन प्राथमिक संवाहक था (चार्ट IV.19)।

चार्ट IV.19: जीएनपीए में कमी (मार्च के अंत में)



स्रोत: बैंकों का वार्षिक लेखा।

IV.34 बैंकों के वैश्विक परिचालन के लिए, सभी बैंक समूहों के लिए आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हाल के वर्षों में संचित उच्च प्रावधानों के साथ कम जीएनपीए ने निवल एनपीए में गिरावट में योगदान दिया (सारणी IV.9)।

IV.35 जहाँ तक बैंकों के घरेलू परिचालन का संबंध है, 2021-22 के दौरान कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों का अनुपात बढ़ गया और एफबी को छोड़कर, सभी बैंक समूहों के लिए जीएनपीए में समग्र कमी देखी गई (सारणी IV.10)।

IV.36 बड़े उधार खातों अर्थात 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों में 2021-22 के कुल अग्रिमों का 47.8 प्रतिशत हिस्सा था, जो 2020-21 के 48.4 प्रतिशत से कम था। कुल एनपीए में उनकी हिस्सेदारी 2020-21 के 66.4 प्रतिशत से घटकर 63.4 प्रतिशत रह गई। विशेष उल्लेख खाता-0 (एसएमए-0) अनुपात, जो 0-30 दिनों से लंबित ऋण खातों का अनुपात है, मार्च 2022 के अंत में दोनों बैंक समूहों (पीएसबी और पीवीबी) के लिए समग्र रूप से तथा बड़े उधार खातों के दृष्टिकोण से बढ़ा, जो उधारकर्ताओं के बीच अस्थायी दबाव की ओर इशारा करता है

सारणी IV.9: अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पीएसबी	पीवीबी	एफबी	एसएफबी	सभी एससीबी
कुल एनपीए					
2020-21 के लिए अंतिम शेष	6,16,616	1,97,508	15,044	5,971	8,35,138
2021-22 के लिए प्रारंभिक शेष	6,16,616	1,97,508	15,044	5,971	8,35,138
वर्ष 2021-22 के दौरान योग	1,39,905	1,25,834	8,320	9,381	2,83,441
वर्ष 2021-22 के दौरान कमी (i+ii+iii)	2,14,347	1,42,559	9,578	8,441	3,74,926
i. वसूली	56,959	34,139	2,722	1,758	95,579
ii. उन्नयन	37,675	55,333	3,390	3,785	1,00,184
iii. बड़े खाते में	1,19,713	53,087	3,466	2,898	1,79,163
2021-22 के लिए अंतिम शेष	5,42,174	1,80,782	13,786	6,911	7,43,653
कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल एनपीए*					
2020-21	9.1	4.8	3.6	5.4	7.3
2021-22	7.3	3.8	2.9	4.9	5.8
निवल एनपीए					
2020-21 के लिए अंतिम शेष	1,96,451	55,377	3,241	2,981	2,58,050
2021-22 के लिए अंतिम शेष	1,54,745	43,733	3,023	2,725	2,04,226
निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए					
2020-21	3.1	1.4	0.8	2.7	2.4
2021-22	2.2	1.0	0.6	2.0	1.7

टिप्पणी: 1. #: इसमें विवेकपूर्ण और वास्तविक बड़े खाते शामिल हैं।

2. *: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखों से कुल एनपीए और ऑफ-साइट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से कुल अग्रिम लेकर गणना की जाती है।

स्रोत: संबंधित बैंकों का वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

(चार्ट IV.20)। एसएमए -1 और एसएमए -2, जो लंबे अवधि वाले बास्केट के लिए आसन्न दबाव का संकेत देते हैं, मार्च 2016 के अंत के बाद से सभी खाते अपने निम्नतम स्तर तक गिर गए।

IV.37 कोविड 19 की प्रतिक्रिया में, रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ दो पुनर्चना योजनाओं की घोषणा की। अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने समाधान ढांचा 1.0 की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित दबाव का

सारणी IV.10: बैंक समूह द्वारा ऋण आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मार्च अंत	मानक आस्तियां		उप-मानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
पीएसबी	2021	55,87,450	90.6	1,03,744	1.7	3,51,014	5.7	1,22,217	2.0
	2022	61,96,768	92.4	75,843	1.1	3,29,264	4.9	1,02,400	1.5
पीवीबी	2021	37,57,240	95.3	65,363	1.7	90,228	2.3	31,350	0.8
	2022	43,63,690	96.3	41,251	0.9	77,394	1.7	50,619	1.1
एफबी	2021	4,10,418	97.6	3,648	0.9	5,566	1.3	986	0.2
	2022	4,62,299	97.1	3,649	0.8	7,953	1.7	2,184	0.5
एसएफबी**	2021	1,05,619	94.6	4,965	4.4	841	0.8	165	0.1
	2022	1,33,093	95.0	5,039	3.6	1,908	1.4	39	0.0
सभी एससीबी	2021	98,60,726	92.7	1,77,720	1.7	4,47,648	4.2	1,54,717	1.5
	2022	1,11,55,849	94.1	1,25,782	1.1	4,16,519	3.5	1,55,243	1.3

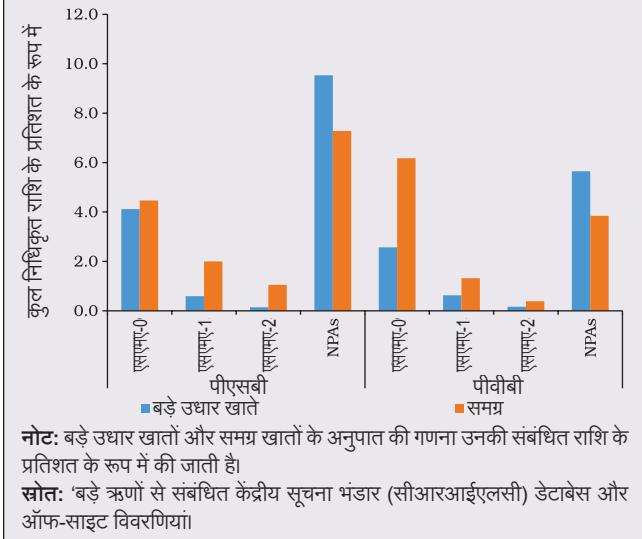
टिप्पणी: 1. पूर्णांकित करने के कारण घटक मदों का योग कुल से भिन्न हो सकता है।

2. *: कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।

3. **: अनुसूचित एसएफबी को संदर्भित करता है।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

चार्ट IV.20: बड़े उधार खातों में दबाव की तुलना में समग्र दबाव (मार्च 2022 के अंत में)



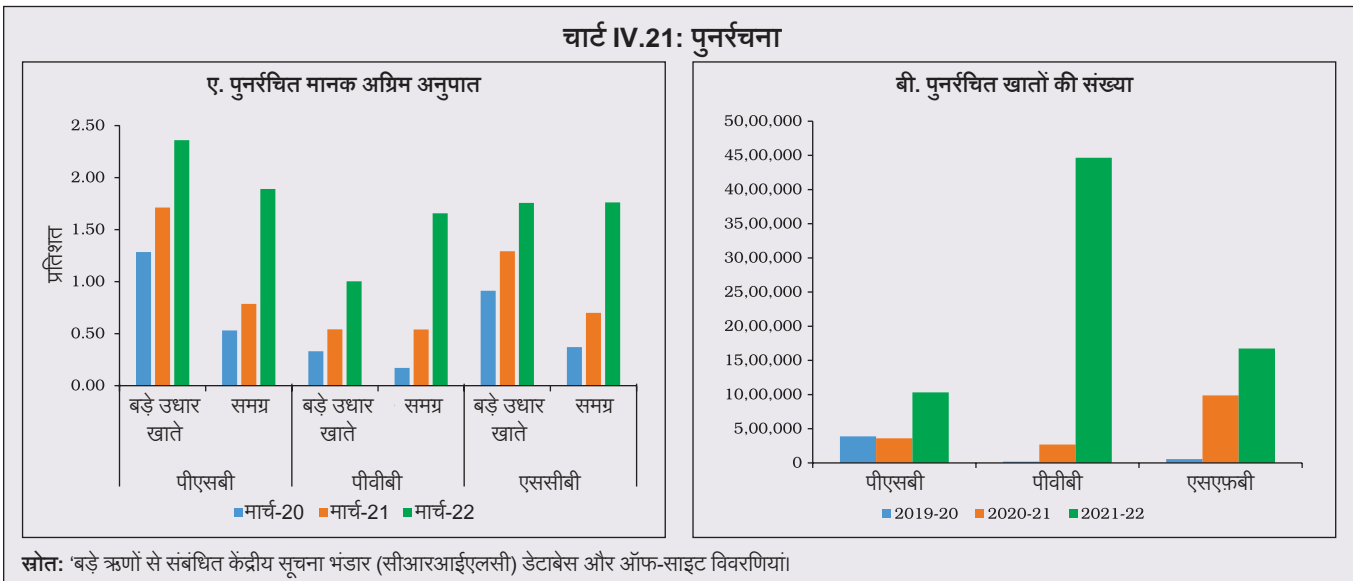
सामना करने वाले कॉर्पोरेट एक्सपोजर और व्यक्तिगत ऋणों पर था। इस ढांचे को आरंभ करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 की समय सीमा थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समाधान के लिए एक योजना पहले से ही 2019 से लागू थी। मई 2021 में घोषित और बाद में जून 2021 में संशोधित समाधान ढांचा 2.0 का उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों

के लिए था, जिसे आरंभ करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 थी।

IV.38 इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात के माध्यम से किया जा सकता है, जो कुल सकल ऋण और अग्रिमों में आरएसए का हिस्सा है। 2020-21 के दौरान, आरएसए अनुपात सभी उधारकर्ताओं के लिए 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ा, जबकि बड़े उधारकर्ताओं के लिए तुलनात्मक वृद्धि 0.4 प्रतिशत अंक थी। इसके विपरीत, 2021-22 के दौरान, अनुपात में सभी उधारकर्ताओं के लिए 1.1 प्रतिशत अंक और बड़े उधारकर्ताओं के लिए 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई (चार्ट IV.21ए)। 2021-22 में सभी उधारकर्ताओं के आरएसए अनुपात में वृद्धि का उच्च क्रम यह संकेत देता है कि रिजर्व बैंक के समाधान ढांचे 2.0 का उद्देश्य, अर्थात् कोविड से संबंधित दबाव से निपटने में खुदरा ऋण और एमएसएमई की सहायता करना काफी हद तक सफल रहा।

IV.39 दोनों समाधान ढांचे 1.0 और 2.0 के माध्यम से पीवीबी द्वारा पुनर्चित खातों की संख्या कई गुना, हालांकि कम आधार पर, बढ़ी। इसके विपरीत, पीएसबी ने समाधान ढांचे 1.0 के तहत कम खातों का पुनर्चना किया था, लेकिन उन्होंने

चार्ट IV.21: पुनर्चना



भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2021-22

समाधान ढांचा 2.0 (चार्ट IV.21बी) में गति पकड़ी। पीवीबी की तुलना में पीएसबी का अंतर व्यवहार बड़े उधार खातों में दबाव की विरासत को प्रतिबिंबित कर सकता है।

4.4. वसूलियाँ

IV.40 बैंक के पास कई चैनल हैं जिनके माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान एक वर्ष के रोक के बाद नए दिवाला मामलों को स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए 2021-22 के दौरान आईबीसी के तहत स्वीकृत मामलों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि लोक अदालतों और सरफेसी अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों की संख्या में क्रमशः 336 प्रतिशत और 335 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि इसमें शामिल राशि के मामले में आईबीसी तंत्र अग्रणी था (सारणी IV.11)। अंतरिम वर्षों में सुस्ती को धता बताते हुए सरफेसी और डीआरटी, आईबीसी तंत्र के तुलनीय वसूली दर दे रहे हैं। अप्रैल 2021 में एमएसएमई के लिए शुरू की गई प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया अभी तक जोर नहीं पकड़ पाई है और चैनल में अब तक (सितंबर 2022 तक) केवल दो मामलों को स्वीकार किया गया है।

IV.41 आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री उनके लिए आस्ति समाधान का एक अन्य तरीका है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एआरसी को बिक्री धीरे-धीरे कम हो गई है, और 2021-22 में, पिछले वर्ष के जीएनपीए का केवल 3.2 प्रतिशत एआरसी को बेचा गया था (चार्ट IV.22ए)। बही मूल्य की तुलना में अधिग्रहण लागत का अनुपात मामूली रूप से बढ़ा, जो बिक्री करने वाले बैंकों के लिए थोड़ी अधिक वसूली दर को दर्शाता है (चार्ट IV.22बी)।

IV.42 हालांकि रिज़र्व बैंक बढ़ी हुई प्रावधानीकरण के माध्यम से बैंकों को अतिरिक्त प्रतिभूति रसीदें (एसआर) रखने से हतोत्साहित कर रहा है, लेकिन कुल जारी एसआर में बैंकों द्वारा लिए गए एसआर का हिस्सा 2021-22 में बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, एआरसी की हिस्सेदारी भी एक वर्ष पहले के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 18.1 प्रतिशत हो गई। एआरसी द्वारा जारी एसआर का मोचन, जो इस प्रक्रिया के माध्यम से वसूली का एक संकेतक है, वर्ष के दौरान बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल बकाया एसआर में गिरावट आई (सारणी IV.12)।

सारणी IV.11: विभिन्न चैनलों के माध्यम से एससीबी के एनपीए की वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली माध्यम	2020-21				2021-22 (P)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (4) कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में	संदर्भित मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूली गई राशि*	कॉलम (8) कॉलम (7) के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक अदालतें	19,49,249	28,084	1,119	4	85,06,648	1,19,005	2,777	2.3
डीआरटी	28,182	2,25,361	8,113	3.6	29,487	47,165	12,114	25.7
सरफेसी एक्ट	57,331	67,510	27,686	41	2,49,475	1,21,642	27,349	22.5
आईबीसी @#	536	1,35,319	27,311	20.2	885	1,99,250	47,421	23.8
कुल	20,35,298	4,56,274	64,229	14	87,86,495	4,87,062	89,661	18.4

टिप्पणी: 1. पी: अंतिम।

2. *: निर्दिष्ट वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि के संदर्भ में जो निर्दिष्ट वर्ष के दौरान, साथ ही पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के विषय में हो सकता है।

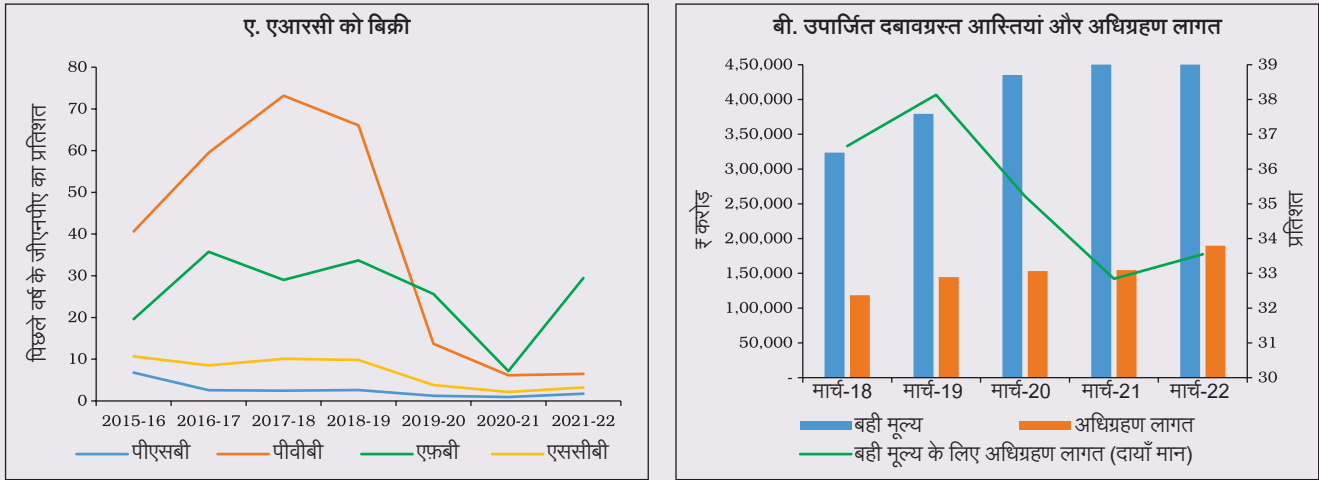
3. डीआरटी: कर्ज वसूली न्यायाधिकरण।

4. @: कॉलम सं. 2 और 6 में दिये गए डेटा आईबीसी के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले हैं।

5. #: कॉलम सं. 3, 4 और 5 में दिये गए डेटा 121 मामलों और कॉलम सं. 7, 8 और 9 में 143 मामलों से संबंधित हैं। जबकि प्रस्तावित योजना क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुमोदित की गई थी।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां, आरबीआई और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

चार्ट IV.22: एआरसी को दबावग्रस्त आस्ति की बिक्री



स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण और ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

4.5. बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी

IV.43 बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है; क्योंकि वे प्रणाली के संबंध में ग्राहकों के विश्वास को

सारणी IV.12: एआरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22
रिपोर्टिंग एआरसी की संख्या	28	24	28
1. उपाजित आस्तियों का बही मूल्य	4,35,122	4,71,204	5,65,683
2. एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद	1,53,239	1,33,755	1,22,130
3. प्रतिभूति रसीदें जिनके द्वारा सदस्यता ली गई है			
(ए) बैंक	1,02,005	87,897	83,190
(बी) एससी/आरसी	30,167	23,359	22,105
(सी) एफआईआई	10,367	10,156	4,548
(डी) अन्य (योग्य संस्थागत खरीदार)	10,700	12,343	12,288
4. पूरी तरह से भुनाई गई प्रतिभूति रसीदों की राशि	18,213	23,131	23,396
5. बकाया प्रतिभूति रसीदें	1,09,168	85,298	69,219

स्रोत: एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण

भी खतरे में डालने के साथ-साथ प्रतिष्ठा, परिचालन और व्यावसायिक जोखिम के स्रोत हैं। 2021-22 के दौरान, धोखाधड़ी¹⁰ की औसत राशि में काफी कमी आई, जिसका अर्थ है कि छोटी -राशि वाले धोखाधड़ी भी अब रिपोर्ट की जा रही है (सारणी IV.13)।

IV.44 धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर, 2019-20 से पहले अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी सबसे बड़ी श्रेणी थी। हालांकि, इसके बाद बड़ी संख्या में धोखाधड़ी का तरीका कार्ड या इंटरनेट आधारित लेनदेन में बदल गया। इसके अतिरिक्त, नकद धोखाधड़ी भी बढ़ रही है (सारणी IV.14)।

IV.45 पीवीबी द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 2021-22 में लगातार दूसरे वर्ष पीएसबी द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों से अधिक थी। इसमें शामिल राशि के संदर्भ में, हालांकि, पीएसबी का हिस्सा 2021-22 में 66.7 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 59.4 प्रतिशत था (चार्ट IV.23)।

¹⁰ धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है जो धोखाधड़ी की संख्या से विभाजित किया गया है।

सारणी IV.13: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2021-22 (अप्रैल-सितंबर)		2022-23 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	4,607	1,81,865	3,496	1,36,429	3,838	58,303	1,800	35,034	2006	18,746
तुलनपत्रेतर	34	2,445	23	535	21	1077	10	612	5	283
विदेशी मुद्रा लेनदेन	8	54	4	129	7	7	1	0	10	3
कार्ड/इंटरनेट	2,677	129	2,545	119	3,596	155	1532	60	2321	87
जमाराशियां	530	616	504	434	471	493	208	362	270	135
अंतर-शाखा खाते	2	0	2	0	3	2	0	0	2	0
नकद	371	63	329	39	649	93	245	51	589	81
चेक/डीडी, आदि	201	39	163	85	201	158	107	149	73	12
समाशोधन खाते, आदि	22	7	14	4	16	1	9	1	11	2
अन्य	250	173	278	54	300	100	157	47	119	136
कुल	8,702	1,85,391	7,358	1,37,828	9,102	60,389	4,069	36,316	5,406	19,485

टिप्पणियाँ:

1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. एक वर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी उस वर्ष के पहले की भी हो सकती है।
4. इसमें निहित राशि रिपोर्ट के अनुसार है और नुकसान की राशि को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर होने वाला नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, ऋण खातों में निहित पूरी राशि को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है।

स्रोत : आरबीआई

4.6. प्रवर्तन कार्रवाई

IV.46 2021-22 के दौरान, विनियमित संस्थाओं (आरई) पर मौद्रिक दंड लगाने के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ एक्सपोजर और आईआरएसी मानदंडों का अनुपालन न

करना, धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा साइबर सुरक्षा ढांचे के दिशानिर्देशों का उल्लंघन शामिल था। वर्ष के दौरान, पीवीबी के लिए प्रति मामला औसत जुर्माना सबसे अधिक था और सहकारी बैंकों के लिए सबसे कम था (सारणी IV.15)।

सारणी IV.14: घटना की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी

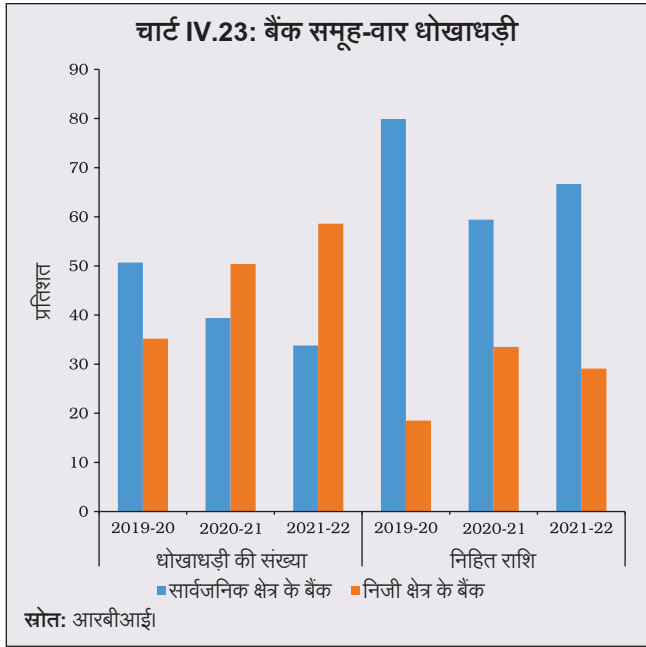
(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2019-20 से पहले		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (अप्रैल-सितंबर)	
	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	निहित राशि
अग्रिम	9,230	3,41,768	1,947	32,386	1,477	14,973	1112	6,042	181	174
तुलनपत्रेतर	66	3,860	8	423	8	31	1	26	0	0
विदेशी मुद्रा लेनदेन	3	47	8	135	4	2	9	8	5	2
कार्ड/इंटरनेट	766	55	2,717	144	2,435	124	3849	120	1372	46
जमाराशियां	508	651	495	402	387	524	328	82	57	20
अंतर-शाखा खाते	3	0	2	0	3	2	1	0	0	0
नकद	99	48	392	38	457	58	745	82	245	49
चेक/डीडी, आदि	90	29	205	70	156	164	160	25	27	6
समाशोधन खाते, आदि	19	7	16	2	9	3	14	2	5	0
अन्य	331	115	178	163	255	117	160	60	23	8
कुल	11,115	3,46,580	5,968	33,763	5,191	15,998	6379	6,447	1915	305

टिप्पणियाँ:

1. ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है।
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. 'घटित होने की तिथि' पर आधारित डेटा कुछ समय के लिए बदल सकता है क्योंकि धोखाधड़ी की सूचना देर से दी जाती है लेकिन जो पहले घटित हो चुकी होती है वह जुड़ जाती है।
4. सारणी में दिया गया डेटा 2019-20 से 30 सितंबर, 2022 तक रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित है।
5. निहित राशि रिपोर्ट के आधार पर है और इसमें हानि शामिल नहीं है, वसूली के आधार पर, हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, ऋण खातों में निहित पूरी राशि को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता है।

स्रोत : आरबीआई



सारणी IV.15: प्रवर्तन कार्रवाइयाँ

विनियमित संस्थाएं	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक		अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक	
	जुर्माना लगाने के मामले	कुल जुर्माना (₹ करोड़)	जुर्माना लगाने के मामले	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4	9.50	13	17.55
निजी क्षेत्र के बैंक	3	5.92	16	29.39
सहकारी बैंक	43	3.89	145	12.10
विदेशी बैंक	3	8.00	4	4.25
भुगतान बैंक	1	1.00	-	-
लघु वित्त बैंक	-	-	1	1.00
एनबीएफसी	7	3.05	10	1.03
कुल	61	31.36	189	65.32

स्रोत: आरबीआई

5. क्षेत्रवार बैंक ऋण : वितरण तथा एनपीए

IV.47 वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं तथा खुदरा ऋणों, विशेष रूप से आवास ऋणों के कारण ऋण संवृद्धि बढ़ गई।

पिछले वर्ष में हुए संकुचन के बाद से सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार आया। यह सुधार व्यापक आधार वाला था जिसमें वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ-साथ संपर्क-सघन घटक सम्मिलित थे (सारणी IV.16)।

सारणी IV.16: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन

(राशि ₹ करोड़ में)

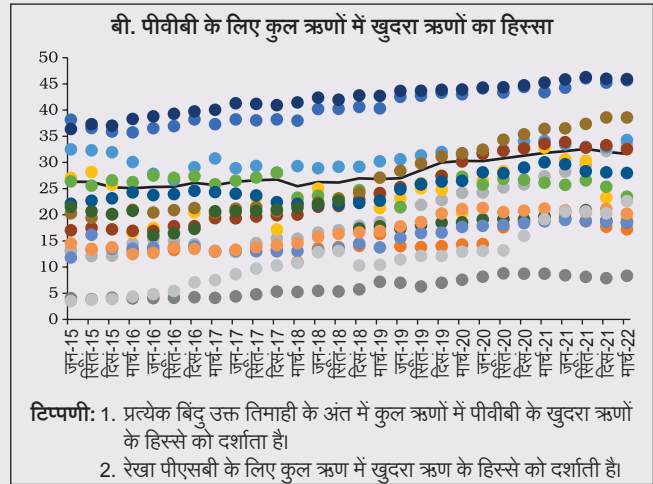
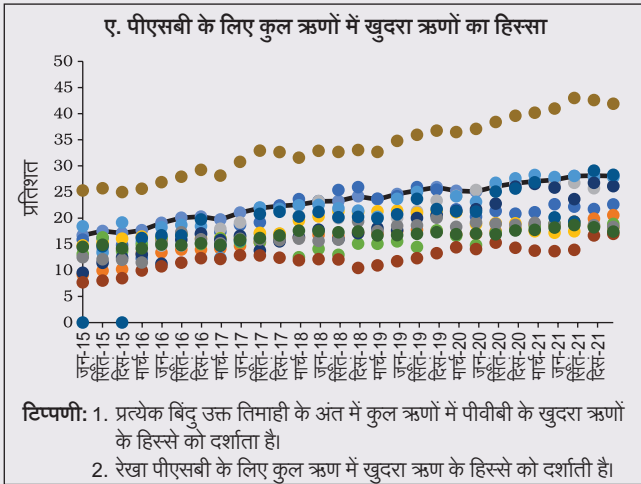
क्रम मद् सं.	अंत में बकाया			प्रतिशत भिन्नता (व-व-व)		
	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	2019-20	2020-21	2021-22
1 कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	12,39,575	13,84,815	15,16,303	1.8	11.7	9.5
2 उद्योग, जिनमें से	32,52,801	32,53,636	35,08,744	-1.2	0.0	7.8
2.1 सूक्ष्म और लघु उद्योग	4,37,658	4,72,529	6,14,037	-0.5	8.0	29.9
2.2 मध्यम	1,12,367	1,87,599	2,63,959	-9.3	67.0	40.7
2.3 बड़ा	26,11,377	24,76,702	24,88,228	0.0	-5.2	0.5
3 सेवाएं, जिनमें से	27,54,823	27,45,324	31,48,321	5.9	-0.3	14.7
3.1 व्यापार	6,28,142	7,14,210	7,76,737	8.8	13.7	8.8
3.2 वाणिज्यिक अचल आस्तियां	2,66,357	2,52,696	2,90,623	9.6	-5.1	15.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	60,039	62,722	69,846	6.8	4.5	11.4
3.4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24,404	23,742	24,993	9.8	-2.7	5.3
3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	7,36,447	7,98,241	9,27,520	17.4	8.4	16.2
4 खुदरा ऋण, जिनमें से	26,59,249	29,86,457	33,94,028	15.4	12.3	13.6
4.1 आवास ऋण	13,96,444	15,61,913	17,54,298	15.9	11.8	12.3
4.2 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	11,154	21,569	37,349	21.3	93.4	73.2
4.3 क्रेडिट कार्ड प्राप्य	1,32,076	1,38,560	1,63,626	18.6	4.9	18.1
4.4 ऑटो ऋण	2,89,366	3,29,522	3,79,139	7.3	13.9	15.1
4.5 शिक्षा ऋण	79,056	78,823	84,677	3.7	-0.3	7.4
4.6 सावधि जमा के एवज में अग्रिम (एफसीएनआर (बी), आदि सहित)	80,753	74,013	78,965	4.7	-8.3	6.7
4.7 व्यक्तियों को शेयरों, बांडों आदि की जमानत पर अग्रिम	5,619	5,619	16,259	-39.8	0.0	189.4
4.8 अन्य खुदरा ऋण	6,64,781	7,76,437	8,79,716	21.5	16.8	13.3
5 अन्य गैर-खाद्य ऋण	1,38,439	2,09,869	2,27,268	126.9	51.6	8.3
6 गैर-खाद्य ऋण (1- 5)	1,00,44,887	1,05,80,100	1,17,94,665	6.0	5.3	11.5
7 सकल बैंक ऋण	1,00,98,420	1,06,40,808	1,18,53,392	6.0	5.4	11.4

टिप्पणियाँ: 1. बैंकों के कवरेज में अंतर के कारण सारणी में दिए गए आंकड़े आरबीआई द्वारा हर महीने 'बैंक क्रेडिट के क्षेत्रीय विनियोजन' में जारी आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं।

2. प्रतिशत बदलाव मार्च से मार्च के लिए हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन) आरबीआई।

चार्ट IV.24: खुदरा ऋण



स्रोत: ऑसमॉसा

IV.48 उद्योग में ऋण 8 वर्षों में सबसे उच्च दर बढ़ गया। वृद्धिशील संदर्भ में, वर्ष के दौरान ऋण का 21 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र को गया, जबकि 2020-21 में यह 0.2 प्रतिशत था।

5.1 खुदरा ऋण

IV.49 हाल के वर्षों में, यह प्रतीत होता है कि भारतीय बैंकों ने 'एक समान व्यवहार' दिखाते हुए उधार देने में प्राथमिकता को औद्योगिक क्षेत्र से हटाकर खुदरा ऋणों के लिए कर दी है

(चार्ट IV.24 ए तथा बी)। यह गिरावट सभी बैंकों में दृष्टिगोचर हो रही थी।

IV.50 अनुभवजन्य प्रमाण यह दर्शाते हैं कि खुदरा ऋणों में संकेन्द्रण का निर्माण प्रणालीगत जोखिम का कारण बन सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी प्रणालीगत जोखिम को अपने नीतिगत साधनों के माध्यम से संभालने के लिए सुसज्जित है (बॉक्स IV.3)।

बॉक्स IV.3: बैंक समूहीकरण और प्रणालीगत जोखिम

“ एक समूह के रूप में प्रणालीगत “ एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है, जिसमें ऐसी संस्थाएं जो व्यक्तिगत आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, किन्तु वे बाजार के नेतृत्वकर्ता के समान व्यवहार करती हैं और इसके परिणामस्वरूप, सामान्य जोखिमों के संपर्क में आती हैं। यह बैंकों के प्रदर्शन के उच्च सह-गति के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम को बढ़ा सकता है, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से अपने स्वचलित बैंक जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

सशर्त जोखिम मूल्य (सीओवीएआर) को प्रणालीगत जोखिम के लिए प्रतिनिधि के रूप में अनुमान लगाने के लिए, (एड्रियन और ब्रूनर्मियर, 2016), 2015-

2022¹¹ के बीच सभी सूचीबद्ध बैंकों (15 पीवीबी और 12 पीएसबी) के दैनिक शेयर बाजार विवरणी का उपयोग किया गया था। तिमाही सीओवीएआर मापांक कुछ बैंक-विशिष्ट और समष्टि-आर्थिक नियंत्रण चरों के साथ खुदरा क्षेत्र के ऋणों के हिस्से के विलंबित मानों पर वापस आ गया था (हिराकाटा एवं अन्य, 2017)। परिणाम प्रणालीगत जोखिम पर खुदरा क्षेत्र के ऋणों में बैंक समूहीकरण के सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव का संकेत देते हैं (सारणी 1)। पीएसबी और पीवीबी द्वारा उत्पन्न जोखिम के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि बैंक समूह उमी का गुणांक 0 है। इसके अतिरिक्त, दबावग्रस्त आस्तियों और बैंक के आकार में वृद्धि के साथ प्रणालीगत जोखिम बढ़ता है,

(जारी...)

¹¹ विशिष्ट समय अवधि को बैंक-वार क्षेत्रीय ऋण के लिए आंकड़े उपलब्धता के अनुसार चुना गया था। साथ ही, इस अवधि के दौरान विलय एवं अधिग्रहण के लिए आंकड़े को समायोजित किया गया है।

सारणी 1: प्रणालीगत जोखिम पर खुदरा क्षेत्र के ऋणों में समूहीकरण का प्रभाव

	Δसीओवीएआर (95)	Δसीओवीएआर (99)	Δसीओवीएआर (90)
खुदरा क्षेत्र के ऋणों का हिस्सा	.0052*** (.0019)	.0037 (.0031)	.0034** (.0014)
कुल आस्तियों का लॉग	.1592*** (.0352)	.295*** (.0573)	.1087*** (.0256)
कुल आस्तियों में जमाराशियां	.0035 (.0031)	.0026 (.0051)	.0005 (.0023)
दबावग्रस्त अग्रिम	.0473*** (.0173)	.0415 (.0281)	.0265** (.0125)
कुल ऋणों के लिए एनपीए प्रावधान	-.0079** (.0035)	-.0022 (.0057)	-.0038 (.0025)
नाममात्र जीडीपी वृद्धि	-.0117*** (.0012)	-.0184*** (.0019)	-.0083*** (.0009)
स्थिर	-1.197** (.4707)	-2.8125*** (.7674)	-.9427*** (.3423)
बैंक समूह डमी	.0000	.0000	.0000
अवलोकन	756	756	756
आर-वर्गित	.2046	.1871	.1848

टिप्पणी: 1. *** पी<.01, ** पी<.05, *पी<.1
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
3. सभी सहचर को 95वें प्रतिशतक पर विसोराइज किया गया है।
स्रोत: लेखक की गणना।

जबकि उच्च एनपीए प्रावधान अनुपात और उच्च जीडीपी वृद्धि कम प्रणालीगत जोखिम से जुड़े हैं। परिणाम सीओवीएआर के विभिन्न उपायों के अनुरूप हैं।

संदर्भ :

Adrian, Tobias, and Markus K. Brunnermeier. "CoVaR." The American Economic Review, vol. 106, no. 7, 2016, pp. 1705–41. JSTOR, available at <http://www.jstor.org/stable/43861110>. Accessed 28 Nov. 2022.

Hirakata, Naohisa, Yosuke Kido and Jie Liang Thum. "Empirical Evidence on "Systemic as a Herd" (2017): The Case of Japanese Regional Banks", Bank of Japan Working Paper Series, No.17-E-1, 2017, available at https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2017/data/wp17e01.pdf.

IV.51 2021-22 की पहली छमाही के दौरान, कम और घटते जीएनपीए अनुपात (चार्ट IV.25बी) के बावजूद पीवीबी (चार्ट IV.25ए) के नेतृत्व में आवास क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हुई।

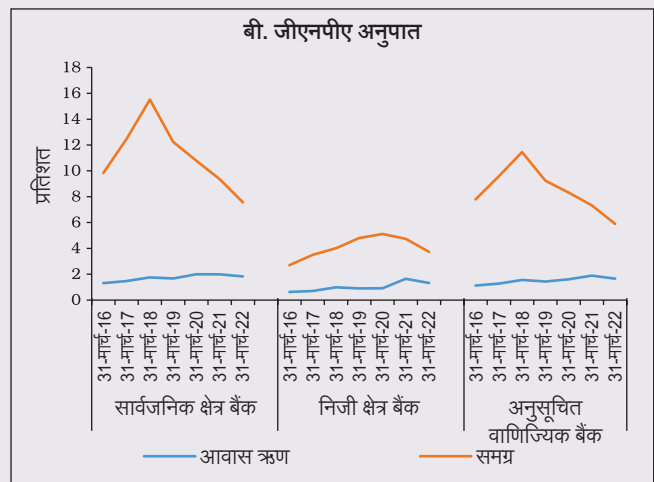
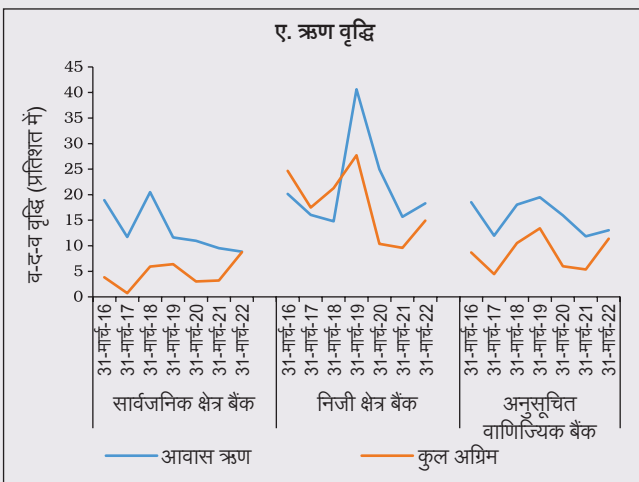
IV.52 इस क्षेत्र में उच्च एनपीए की पृष्ठभूमि पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शिक्षा ऋण में मार्च 2016 से मंदी आई है। कुल खुदरा ऋण में शिक्षा ऋण की हिस्सेदारी कम हो गई है। वर्ष 2021-22 में, इस क्षेत्र को जारी ऋण में सुधार आया है, हालांकि

इसका आधार कम था। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, ऋण संवृद्धि घटते जा रहे जीएनपीए अनुपात को दर्शाती है (चार्ट IV.26)।

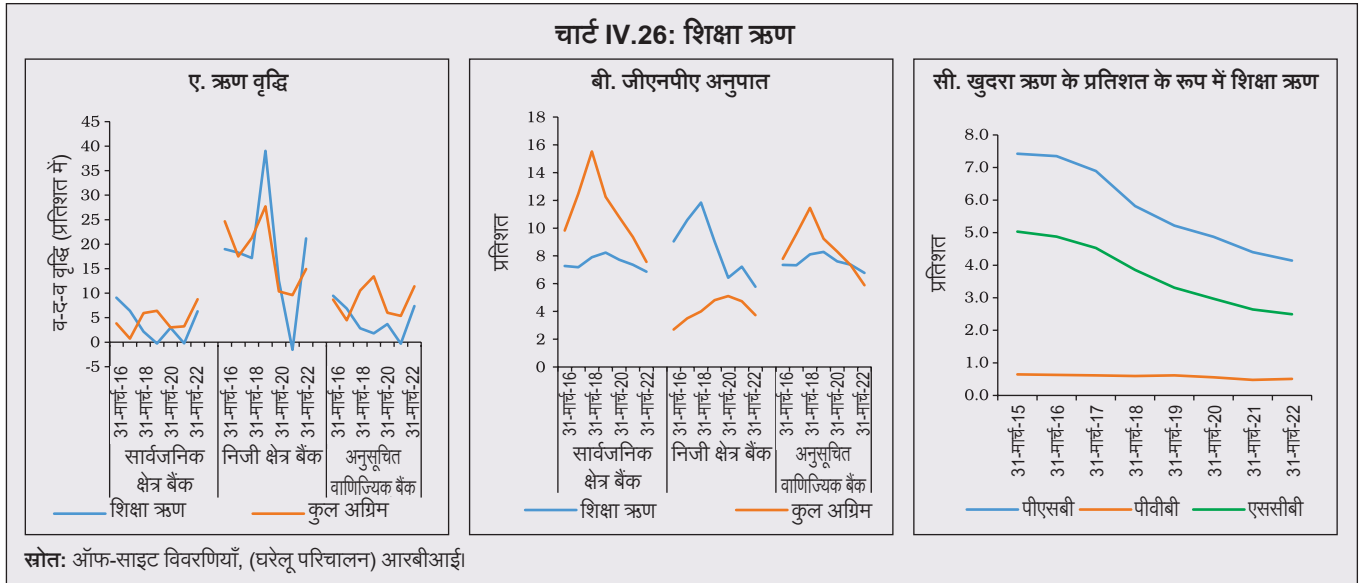
5.2 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

IV.53 कोविड महामारी के बाद की अवधि में, उद्योग क्षेत्र में एमएसएमई को ऋण संवृद्धि बड़े उद्योगों में हुई ऋण संवृद्धि की तुलना में भी साल-दर-साल आधार पर स्पष्ट रूप से उच्चतर थी

चार्ट IV.25: आवास ऋण



स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन) आरबीआई।



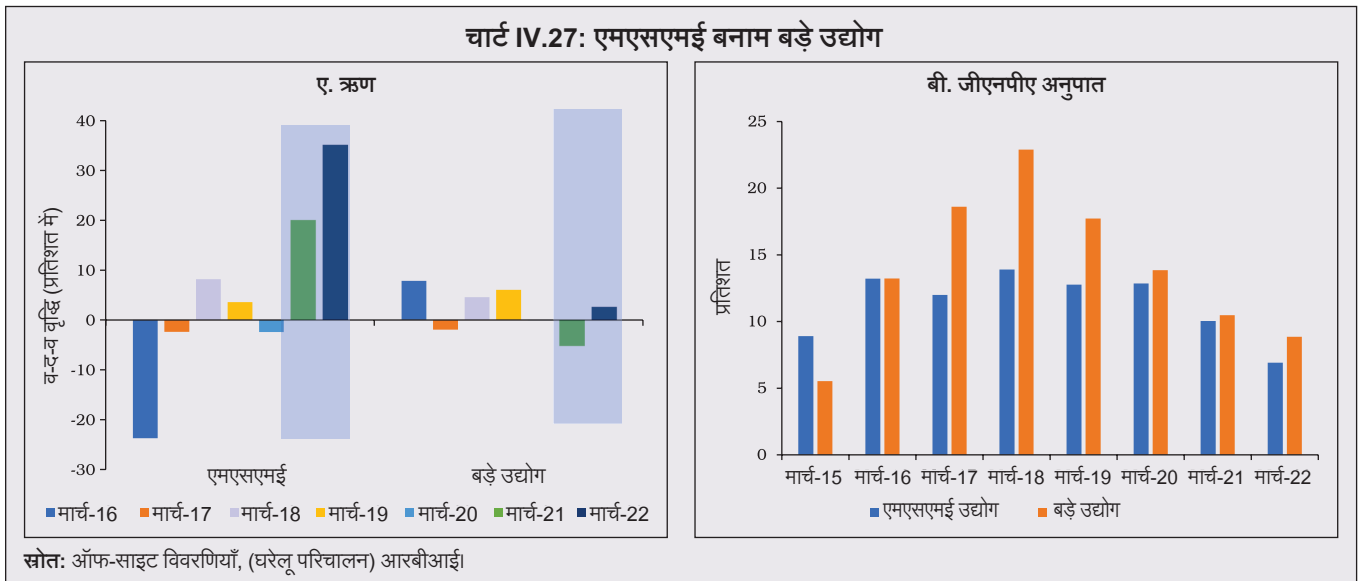
(चार्ट IV.27 ए)। आपात कालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) द्वारा दिये गए प्रोत्साहनों, साथ ही न्यूनतर जीएनपीए अनुपात, एमएसएमई को ऋण में वृद्धि करने में सहायक रहे हैं (चार्ट IV.27 बी)। इसके साथ ही, जुलाई 2021 से एमएसएमई श्रेणी में थोक तथा खुदरा व्यापार शामिल होने से एमएसएमई क्षेत्र को जारी समग्र ऋण में वृद्धि हुई।

IV.54 वर्ष 2018-19 से, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को दी गई ऋण संवृद्धि सार्वजनिक बैंकों द्वारा दी गई संवृद्धि से

बहुत अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 में भी बकाया ऋण में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है (सारणी IV.17)।

5.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.55 वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के बकाया उधार में 12.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सभी बैंक समूह अपने समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए हैं, जबकि विदेशी बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों ने भी सभी



सारणी IV.17: एससीबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	मदें	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
पीएसबी	खातों की संख्या	112.97 (1.76)	110.82 (-1.90)	150.77 (36.05)	149.70 (-0.71)
	बकाया राशि	8,80,032.90 (1.79)	8,93,314.83 (1.51)	9,08,659.06 (1.72)	9,55,860.38 (5.19)
पीवीबी	खातों की संख्या	205.31 (38.42)	270.62 (31.81)	266.81 (-1.41)	112.86 (-57.70)
	बकाया राशि	5,63,678.47 (37.23)	6,46,988.27 (14.78)	7,92,041.95 (22.42)	9,69,844.22 (22.45)
एफबी	खातों की संख्या	2.40 (9.14)	2.74 (14.17)	2.60 (-5.11)	2.11 (-18.84)
	बकाया राशि	66,939.14 (36.94)	73,279.06 (9.47)	83,223.79 (13.57)	85,352.38 (2.56)
सभी एससीबी	खातों की संख्या	320.68 (22.61)	384.18 (19.80)	420.19 (9.37)	264.67 (-37.01)
	बकाया राशि	15,10,650.52 (14.08)	16,13,582.17 (6.81)	17,83,924.80 (10.56)	20,11,056.98 (12.73)

टिप्पणियाँ: 1. * - खातों की संख्या में कमी आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित नई एमएसएमई परिभाषा के तहत उद्यम पोर्टल पर नई अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकता को दर्शाती है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) दर दर्शाते हैं।
स्रोत: वित्तीय समावेश और विकास विभाग, आरबीआई

क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में चूक गए। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंकों ने केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए

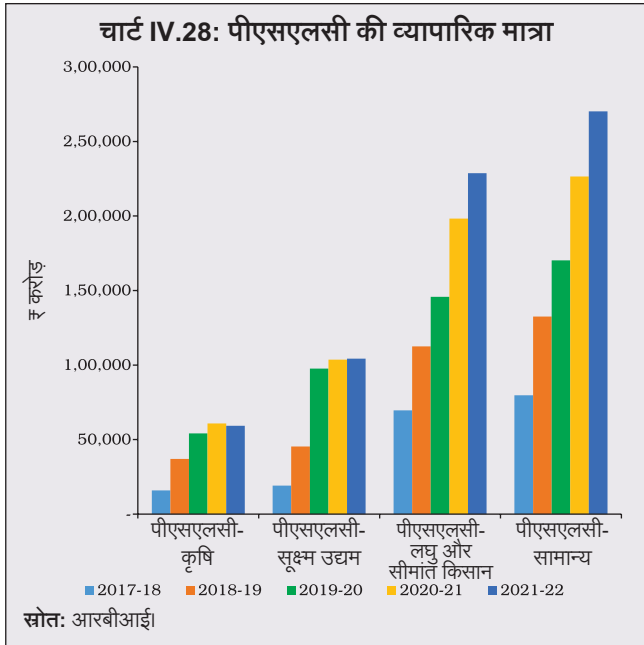
अपने लक्ष्य पूरे किये (सारणी IV.18)। 2020-21 में केवल 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने के बाद, परिचालित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत बकाया राशि 2021-22 के

सारणी IV.18: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (31 मार्च 2022 तक)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	लक्ष्य/उप-लक्ष्य (एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत)	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक		निजी क्षेत्र बैंक		विदेशी बैंक ^		लघु वित्त बैंक		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
		बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम जिसमें से	40/75*	2649179.95	42.90	1685805.56	43.71	208106.50	42.65	73505.52	85.08	4616597.54	43.52
सकल कृषि	18.00	1182377.52	19.15	622339.14	16.14	48876.88	19.27	21361.96	24.73	1874955.50	18.07
छोटे और सीमांत किसान	9.00	648227.14	10.50	286829.08	7.44	26336.73	10.38	17274.46	20.00	978667.40	9.43
गैर-सहकारी एकल किसान#	12.73	924640.55	14.97	415711.15	10.78	33116.26	13.05	27619.46	31.97	1401087.42	13.51
सूक्ष्म उद्यम	7.50	442596.73	7.17	318688.90	8.26	20524.93	8.09	23813.65	27.56	805624.21	7.77
कमजोर वर्ग	11.00	827895.58	13.41	386742.30	10.03	30411.53	11.99	38345.20	44.38	1283394.62	12.37

टिप्पणियाँ: 1. बकाया राशि और उपलब्धि प्रतिशत वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों के लिए बैंकों की औसत उपलब्धि पर आधारित है।
2. *: लघु वित्त बैंकों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य 75 प्रतिशत था।
3. #: गैर-सहकारी किसानों के लिए लक्ष्य पिछले तीन वर्षों की उपलब्धि के प्रणाली-व्यापी औसत पर आधारित है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागू प्रणाली व्यापी औसत आंकड़ा 12.73 प्रतिशत था।
4. ^: 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, केवल 40 प्रतिशत का कुल पीएसएल लक्ष्य लागू है।
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।



दौरान 24.5 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र – विशेष रूप से कर्नाटक का योगदान प्रमुख रहा (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

IV.56 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की कुल कारोबार मात्रा में 12.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2021-22 में 6,62,389 करोड़ रुपये थी। चार पीएसएलसी श्रेणियों में, पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान (एसएफ / एमएफ) में सबसे अधिक व्यापार देखा गया। (चार्ट IV.28)।

IV.57 2021-22 में पीएसएलसी-ए को छोड़कर पीएसएलसी की सभी श्रेणियों के लिए भारत औसत प्रीमियम (डब्ल्यूएपी) में वृद्धि हुई, जिसमें पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ का प्रीमियम सबसे अधिक था, (सारणी IV.19)।

IV.58 यद्यपि वर्ष 2020-21 में कुल ऋणों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों की हिस्सेदारी में 35.3 प्रतिशत से वर्ष 2021-22 में 35.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, कुल

सारणी IV.19: पीएसएलसी की विभिन्न श्रेणियों पर भारत औसत प्रीमियम

पीएसएलसी श्रेणी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	(प्रतिशत)	
					2021-22 (अप्रै-सित)	2022-23 (अप्रै-सित)
पीएसएलसी-कृषि	0.79	1.17	1.55	1.37	2.00	0.88
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	0.57	0.44	0.88	0.95	2.03	0.60
पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान	1.15	1.58	1.74	2.01	2.38	1.97
पीएसएलसी-सामान्य	0.31	0.35	0.46	0.6	0.85	0.22

स्रोत: आरबीआई

जीएनपीए में उनकी हिस्सेदारी में कृषि क्षेत्र में ऋण न चुकाने के कारण 40.4 प्रतिशत से 43.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि, लघु वित्त बैंक अपने 76 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करते हैं, जो इस पोर्टफोलियो के एनपीए का 88 प्रतिशत है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कारण से असमान रूप से एनपीए की हिस्सेदारी कम हुई है (सारणी IV.20)।

5.4. संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

IV.59 मार्च 2022 के अंत में संवेदनशील क्षेत्रों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये ऋण में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी स्थावर सम्पदा क्षेत्र की थी। कोविड अवधि के दौरान, मंदी के बाद जैसे ही स्थावर सम्पदा बाजार गतिविधि ने गति पकड़ी, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस क्षेत्र के लिए ऋण दिये जाने से इसमें वृद्धि होने लगी (चार्ट IV.29 ए)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी बाजार को प्रदत्त ऋण में वर्ष 2017-18 से गिरावट रही किन्तु इस वर्ष के दौरान इसमें वृद्धि हुई, जो आंशिक रूप से वृद्धिशील इक्विटी बाजार को दर्शाता है (चार्ट IV.29 बी तथा परिशिष्ट सारणी IV.8)।

सारणी IV.20: बैंकों के क्षेत्र-वार जीएनपीए
(मार्च अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह	प्राथमिकता क्षेत्र		जिनमें						गैर-प्राथमिकता क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		लघु और सूक्ष्म उद्यम		अन्य					
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पीएसबी												
2021	2,57,858	44.69	1,14,911	19.92	1,01,786	17.64	41,161	7.13	3,19,116	55.31	5,76,974	100.00
2022	2,43,283	47.94	1,10,649	21.80	96,231	18.96	36,403	7.17	2,64,225	52.06	5,07,508	100.00
पीवीबी												
2021	50,557	27.04	18,900	10.11	23,473	12.56	8,184	4.38	1,36,384	72.96	1,86,941	100.00
2022	48,588	28.71	20,863	12.33	17,799	10.52	9,926	5.86	1,20,676	71.29	1,69,264	100.00
एफबी												
2021	1,802	17.67	329	3.23	1,194	11.70	279	2.74	8,397	82.33	10,199	100.00
2022	2,555	18.53	481	3.49	1,638	11.88	436	3.16	11,231	81.47	13,786	100.00
एसएफबी												
2021	4,974	83.31	1,510	25.28	2,049	34.32	1,415	23.70	996	16.69	5,971	100.00
2022	6,111	87.48	1,999	28.62	2,024	28.98	2,087	29.88	874	12.52	6,985	100.00
सभी एससीबी												
2021	3,15,192	40.40	1,35,650	17.39	1,28,502	16.47	51,039	6.54	4,64,893	59.60	7,80,085	100.00
2022	3,00,537	43.09	1,33,993	19.21	1,17,692	16.87	48,852	7.00	3,97,006	56.91	6,97,543	100.00

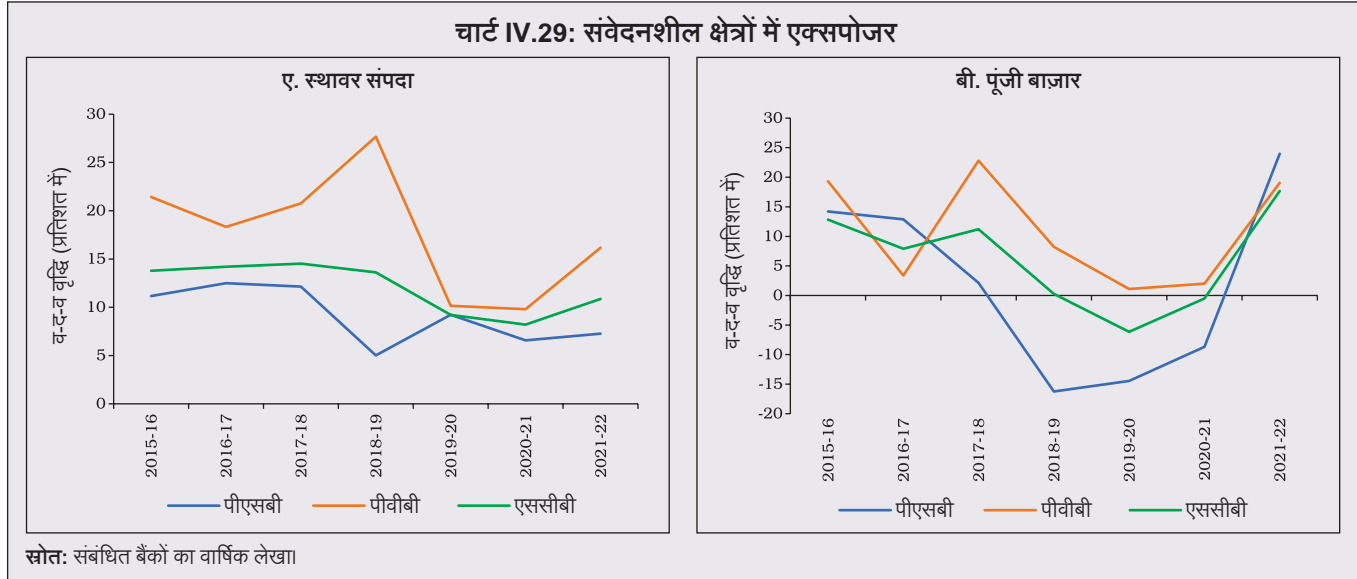
टिप्पणियाँ: 1. प्रतिशत: कुल एनपीए का प्रतिशत
2. पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल योग से भिन्न हो।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

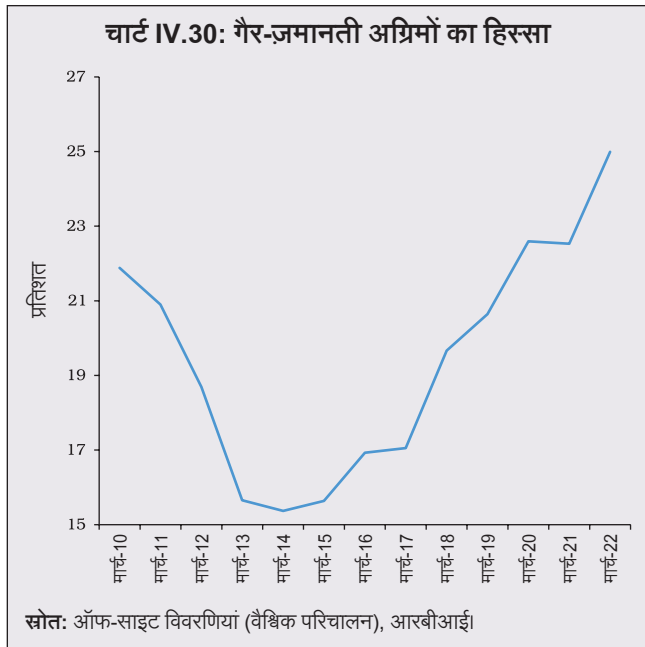
5.5 गैर-जमानती ऋण/उधार

IV.60 गैर-जमानती ऋण – अर्थात बिना संपार्श्विक का ऋण – बैंकों के लिए उच्चतर ऋण जोखिम पैदा करता है,

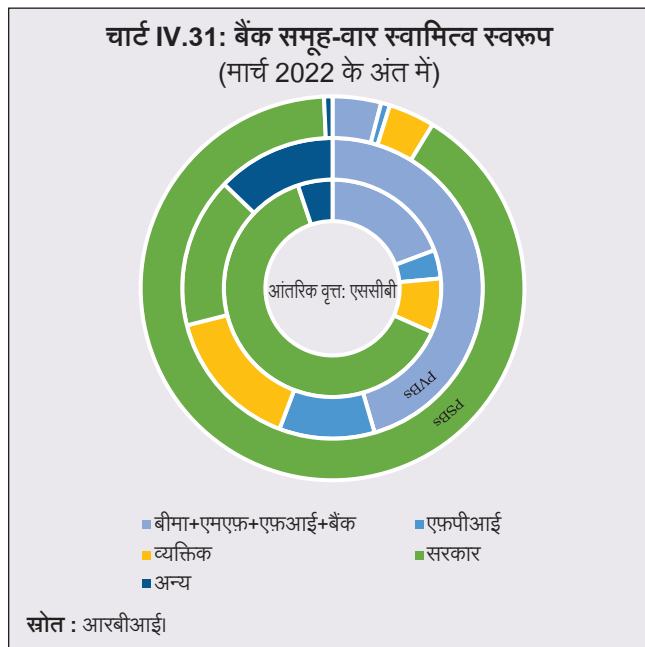
जिसके लिए बड़े प्रावधान तथा जोखिम भार होते हैं। वर्ष 2015 से कुल ऋण में गैर-जमानती ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इस तरह के ऋणों से बैंकों को

चार्ट IV.29: संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर





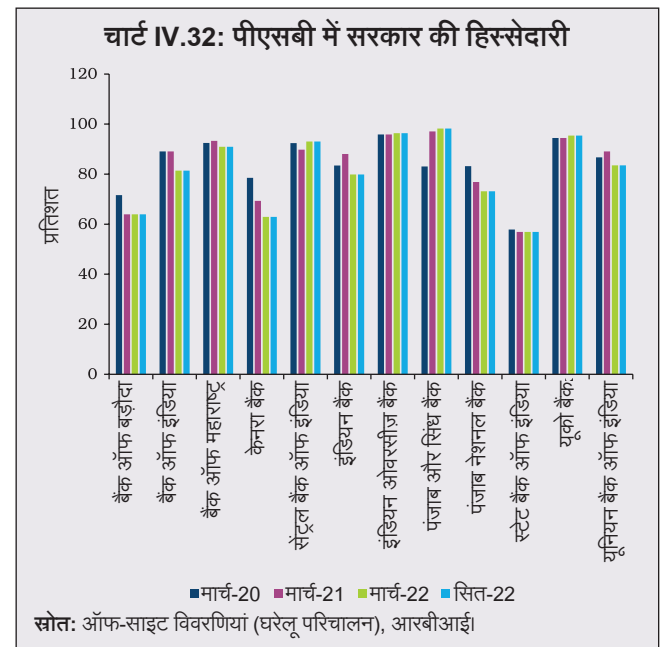
उच्चतर ब्याज आय अर्जन होता है (चार्ट IV.30)



6. वाणिज्यिक बैंकों में स्वामित्व का स्वरूप¹²

IV.61 पीएसबी और पीवीबी के स्वामित्व का स्वरूप को उनके परिचालन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण विशिष्ट कारक के रूप में प्रलेखित किया गया है (चव्हाण और गम्बाकोर्टा, 2016)¹³। पीवीबी के पास अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक विविध स्वामित्व है (चार्ट IV.31)।

IV.62 बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नई इक्विटी जारी करने के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता कम हो गई (चार्ट IV.32)। स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक और, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अनिवासी शेयरधारिता 74 प्रतिशत की सीमाओं के भीतर थी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 20 प्रतिशत थी। (परिशिष्ट सारणी IV.9)



¹² स्रोत: शेयरधारिता का आंकड़ा 31 मार्च, 2022 तक एनएसई की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है।

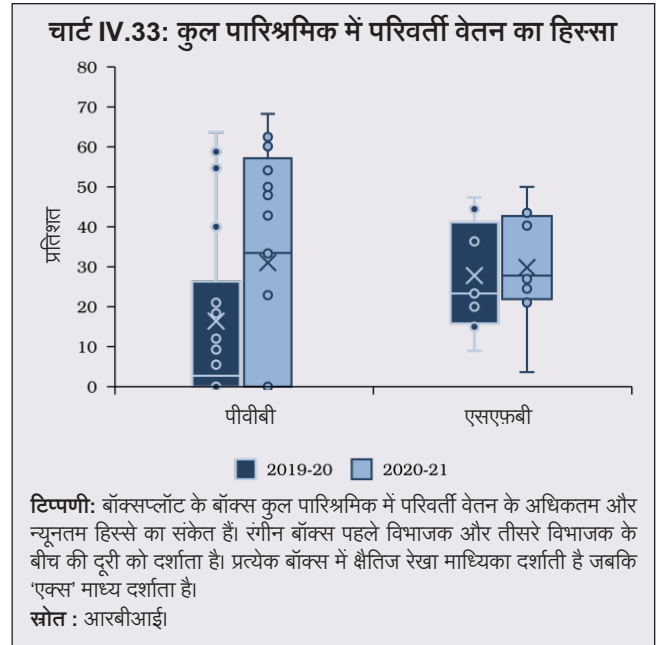
¹³ चव्हाण, पल्लवी और गम्बाकोर्टा, लियोनार्डो (2016)। बैंक उधार और ऋण की गुणवत्ता: भारत का मामला। बीआईएस बैंकिंग पेपर।

7. कॉरपोरेट अभिशासन

IV.63 कॉरपोरेट अभिशासन में, विशेष रूप से बड़े वित्तीय संस्थानों में, विफलताएँ तथा कमजोरियाँ एक महत्वपूर्ण कारक थे जिनके फलस्वरूप वैश्विक वित्तीय संकट आया। जोखिमों तथा दीर्घावधि परिणामों की पर्याप्त रूप से पहचान किए बिना अल्पावधि लाभ बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को अक्सर फायदा पहुंचाया गया। क्षतिपूर्ति, इस प्रकार विनियामकीय सुधारों के केंद्र में रहा है।

7.1 कार्यकारी क्षतिपूर्ति

IV.64 मुआवजे के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों¹⁴ में कुल वेतन का लक्ष्य परिवर्तनीय वेतन (वीपी) घटक 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच और लक्ष्य वीपी का नकद घटक 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत¹⁵ के बीच होना आवश्यक है। संयोग से, पीवीबी के लिए वास्तविक वीपी¹⁶ मार्च 2020 के अंत में कुल पारिश्रमिक (टीआर) के 16 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 31 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, एसएफबी के लिए, यह इसी अवधि के दौरान लगभग 25 प्रतिशत पर स्थिर रहा है (चार्ट IV)। पीवीबी के लिए, वीपी के नकद घटक का हिस्सा मार्च 2020 के अंत में 31 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 के अंत में 22 प्रतिशत और एसएफबी के लिए इसी अवधि के दौरान 65 प्रतिशत से घटकर 59 प्रतिशत हो गया। दिशानिर्देशों में यह भी आवश्यक है कि कुल परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 60 प्रतिशत अनिवार्य रूप से स्थगन व्यवस्था के तहत होना चाहिए। इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप, एमडी और सीईओ के प्रदर्शन से जुड़े वेतन का स्थगित घटक पीवीबी के लिए 41 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत और एसएफबी के लिए 22 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया।



IV.65 औसत कर्मचारी वेतन की तुलना में बैंक के एमडी और सीईओ को दिया जाने वाला पारिश्रमिक बैंक समूहों में भिन्न होता है। मार्च 2021 के अंत में, पीवीबी के लिए, औसतन, सीईओ ने औसत कर्मचारी पारिश्रमिक का 73 गुना अर्जित किया, जबकि एसएफबी में, सीईओ ने औसत कर्मचारी से 76 गुना अर्जित किया। यह किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बहुत अधिक है; जबकि औसतन, सीईओ ने औसत कर्मचारी पारिश्रमिक से 2.2 गुना अधिक आय अर्जित की है (चार्ट IV.34)।

7.2 बोर्डों का गठन

IV.66 निष्पक्ष निर्णय लेने तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। कॉरपोरेट अभिशासन पर 26 अप्रैल, 2021¹⁷ को रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनिवार्य है कि बोर्ड की बैठकों में

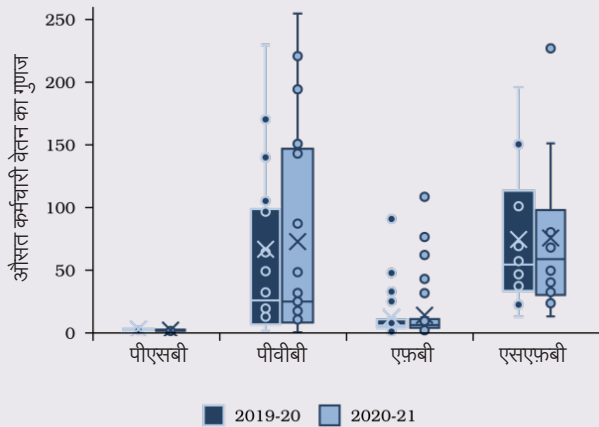
¹⁴ पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सामग्री जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के मुआवजे पर 4 नवंबर, 2019 को जारी दिशा-निर्देश 01 अप्रैल, 2020 से या उसके बाद शुरू होने वाले वेतन चक्रों के लिए प्रभावी हो गए।

¹⁵ यदि परिवर्तनीय वेतन निश्चित वेतन का 200 प्रतिशत तक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत और यदि परिवर्तनीय वेतन 200 प्रतिशत से अधिक है, तो परिवर्तनीय वेतन का न्यूनतम 67 प्रतिशत गैर-नकद साधनों के माध्यम से होना चाहिए।

¹⁶ यहां उपयोग किया जाने वाला वीपी बैंक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि है।

¹⁷ बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन।

चार्ट IV.34: सीईओ वेतन बनाम औसत कर्मचारी वेतन



टिप्पणी: बॉक्सप्लॉट के विस्कर कुल पारिश्रमिक में परिवर्तनीय वेतन के अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का संकेत हैं। रंगीन बॉक्स पहले क्वांटाइल और तीसरे क्वांटाइल के बीच की दूरी को दर्शाता है। प्रत्येक बॉक्स में क्षैतिज रेखा माध्यिका दर्शाती है जबकि 'एक्स' माध्य दर्शाता है। बॉक्स के बाहर के बिंदु आउटलायर दर्शाते हैं।

स्रोत : आरबीआई

उपस्थित कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2021 के अंत में 59 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2022 के अंत में 63 प्रतिशत कर दी गई। इसी प्रकार, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में स्वतंत्र निदेशकों का अनुपात भी बढ़ा है (सारणी IV.21)।

IV.67 रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बोर्ड द्वारा गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) की अधिक संख्या के साथ एक आरएमसीबी का गठन करना अपेक्षित है। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का एक सदस्य होगा यदि उसके पास अपेक्षित

सारणी IV.21: बोर्ड की विभिन्न समितियों पर स्वतंत्र निदेशक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत में शेयर)

	आरएमसीबी		एनआरसी		बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
पीवीबी	58	65	76	80	79	76
एसएफबी	69	74	77	83	80	83

स्रोत : आरबीआई

जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता है। निजी क्षेत्र के बैंकों का अनुपात, जहां अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है, मार्च 2021 के अंत में 29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 के अंत में 39 प्रतिशत हो गया। लघु वित्त बैंकों में, इसी अवधि के दौरान यह अनुपात 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया। मार्च 2021 के अंत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लगभग 10 प्रतिशत की आरएमसीबी में कोई प्रबंधन उपस्थिति¹⁸ नहीं थी तथा मार्च 2022 के अंत में हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि, लघु वित्त बैंकों के लिए 30 प्रतिशत से 33 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी।

8. भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन तथा भारतीय बैंकों का विदेशों में परिचालन

IV.68 वर्ष 2021-22 के दौरान, देश में कार्यरत विदेशी बैंकों (एफबी) की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ; हालांकि, शाखाओं की संख्या में कमी आयी (सारणी IV.22)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी विदेशी उपस्थिति में कमी की ताकि अपने परिचालनों को युक्तिसंगत बना सकें तथा कम लाभदायक परिचालनों को बंद करके लागत प्रभाव क्षमता को सुधार सकें। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों ने, हालांकि वर्ष के दौरान और अधिक प्रतिनिधि कार्यालयों को खोलकर अपनी विदेशी उपस्थिति में वृद्धि की है (परिशिष्ट सारणी IV.10)

सारणी IV.22: भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

मार्च	शाखाओं के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक		प्रतिनिधि कार्यालयों वाले विदेशी बैंक
	बैंकों की संख्या	शाखाएं	
मार्च-17	44	295	39
मार्च-18	45	286	40
मार्च-19	45#	299*	37
मार्च-20	46#	308*	37
मार्च-21	45#	874*	36
मार्च-22	45#	861*	34

टिप्पणियाँ : 1. #: दो विदेशी बैंक शामिल हैं, अर्थात् एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) मोड के माध्यम से काम कर रहे हैं।
2. *: एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की शाखाएं शामिल हैं (मार्च 2021 तक समाहित इकाई यानी लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाओं सहित) जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) मोड के माध्यम से काम कर रही हैं।

स्रोत : आरबीआई

¹⁸ एमडी और सीईओ सहित पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की उपस्थिति।

9. भुगतान प्रणालियाँ तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

IV.69 विश्व भर में विभिन्न नवोन्मेषी भुगतान प्रणालियों तथा लिखतों के आने से भुगतान का दायरा तेज गति से बढ़ता जा रहा है। कई भुगतान प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों, उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भुगतान उत्पादों तथा सेवाओं की उपलब्धता होने तथा खुदरा भुगतान खंड में भुगतान के नए माध्यमों की शुरुआत तथा स्वीकृति होने के साथ भारतीय भुगतान प्रणाली विश्व में अग्रणी बनकर उभरी है।

IV.70 भारत की भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए 2019 में एक परीक्षण शुरू किया गया था ताकि इसकी शक्तियों और कमियों का पता लगाया जा सके और 2022 में अनुवर्ती परीक्षण किया गया था। नवीनतम आकलन से पता चला है कि कुछ चुनौतियों के बावजूद, कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय भुगतान प्रणालियों की वृद्धि सुदृढ़ बनी हुई है। 20 अन्य अधिकार क्षेत्रों की तुलना में 40 संकेतकों में से 16 में भारत को 'अग्रणी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पिछले परीक्षण के बाद से भारत ने बिल भुगतान के लिए उपलब्ध डिजिटल भुगतान विकल्पों, सीमा पार प्रेषण के लिए उपलब्ध चैनलों और चेक उपयोग में कमी, बड़े मूल्य के भुगतान प्रणालियों, तीव्र भुगतान

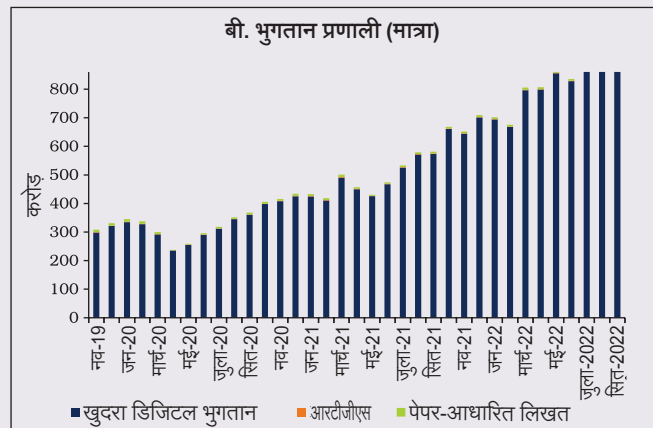
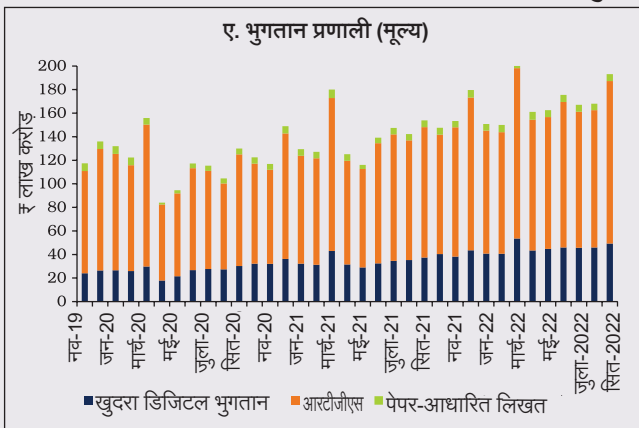
प्रणालियों में प्रगति का प्रदर्शन किया है। इस परीक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्वीकृति बुनियादी ढांचे यानी एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों में सुधार की गुंजाइश है। स्वीकृति बुनियादी ढांचे को समृद्ध करने और अंतर को पाटने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना 2021 में लागू की गई थी।

9.1 डिजिटल भुगतान

IV.71 पिछले कुछ वर्षों में भुगतान के डिजिटल माध्यमों में तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, परंपरागत कागज-आधारित लिखत जैसे कि चेक तथा डिमांड ड्राफ्ट की हिस्सेदारी भुगतानों की मात्रा तथा मूल्य दोनों में नगण्य हो गई है। (चार्ट IV.35)

IV.72 कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन और सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध, जीडीपी में तेज संकुचन के साथ, 2020-21 में भुगतान साधनों के मूल्य और मात्रा दोनों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुल भुगतान की मात्रा में 2020-21 में 26.6 प्रतिशत से 2021-22 के दौरान 63.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें कुल भुगतान का 99 प्रतिशत डिजिटल मोड के माध्यम से किया गया। आर्थिक गतिविधि में तेजी को दर्शाते

चार्ट IV.35 : भुगतान प्रणालियों के घटक



टिप्पणियाँ : खुदरा डिजिटल भुगतान में एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, एनएसीएच, बीएचआईएम आधार भुगतान, ईपीएस निधि अंतरण, एनईटीसी, कार्ड भुगतान और प्रिपेड भुगतान लिखत शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई

सारणी IV.23: भुगतान प्रणाली संकेतक

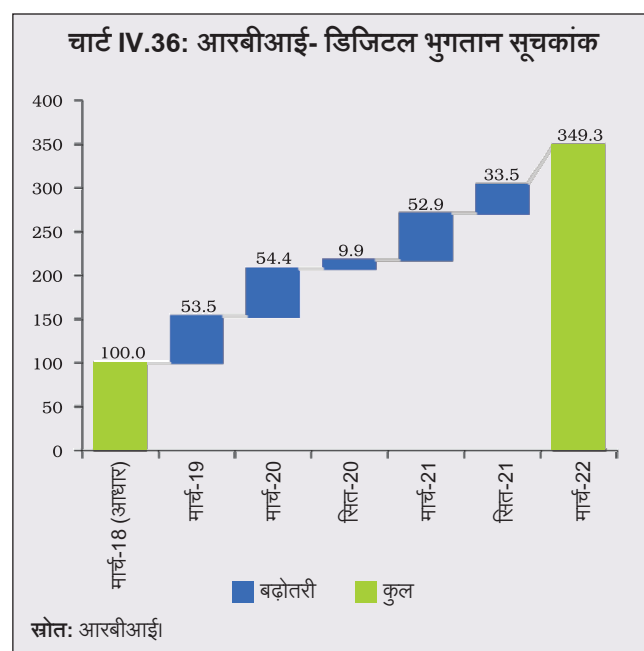
मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1. वृहत मूल्य ऋण अंतरण- आरटीजीएस	1,507	1,592	2,078	13,11,56,475	10,55,99,849	12,86,57,516
2. ऋण अंतरण	2,06,297	3,17,868	5,77,935	2,85,56,593	3,35,04,226	4,27,28,006
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण)	10	11	10	469	623	575
2.2 एपीबीएस	16,747	14,373	12,573	99,048	1,11,001	1,33,345
2.3 ईसीएस करोड़	18.3	0	0	5,146	0	0
2.4 आईएमपीएस	25,792	32,783	46,625	23,37,541	29,41,500	41,71,037
2.5 एनएसीएच	11,100	16,465	18,758	10,37,079	12,16,535	12,81,685
2.6 एनईएफटी	27,445	30,928	40,407	2,29,45,580	2,51,30,910	2,87,25,463
2.7 यूपीआई	1,25,186	2,23,307	4,59,561	21,31,730	41,03,658	84,15,900
3. नामे अंतरण और प्रत्यक्ष नामे	6,027	10,457	12,189	6,05,939	8,65,520	10,34,444
3.1 भीम आधार पे	91	161	228	1,303	2,580	6,113
3.2 ईसीएस डीआर	1.14	0	0	38,607	0	0
3.3 एनएसीएच	5,842	9,646	10,755	6,04,397	8,62,027	10,26,641
3.4 एनईटीसी	93	650	1,207	200	913	1,689
4. कार्ड भुगतान	72,384	57,787	61,783	14,34,813	12,91,799	17,01,851
4.1 क्रेडिट कार्ड	21,773	17,641	22,399	7,30,894	6,30,414	9,71,638
4.2 डेबिट कार्ड	50,611	40,146	39,384	7,03,920	6,61,385	7,30,213
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	53,941	49,366	65,783	2,14,860	1,97,095	2,79,416
6. कागज़-आधारित लिखत	10,414	6,704	6,999	78,24,822	56,27,108	66,50,333
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	3,40,155	4,37,068	7,19,768	16,19,68,681	14,14,58,488	17,44,01,233
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	3,49,063	4,42,180	7,24,689	3,86,37,028	4,14,85,747	5,23,94,049
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	3,50,570	4,43,772	7,26,767	16,97,93,503	14,70,85,596	18,10,51,565

स्रोत : आरबीआई

हुए, मूल्य के दृष्टिकोण से, कुल भुगतान में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.23)। लगभग सभी डिजिटल साधनों ने मार्च 2020 के अंत में देखे गए स्तरों को पार कर लिया है, हालांकि, आरटीजीएस लेनदेन अभी भी पीछे हैं।

IV.73 रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में सम्मिश्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) की शुरुआत की ताकि देश में भुगतानों के डिजिटलीकरण के विस्तार का प्रभावी रूप से पता लगाया जा सके। यह सूचकांक पाँच मुख्य मापदंडों – भुगतान सक्षमकर्ताओं; भुगतान बुनियादी संरचना – मांग कारकों; भुगतान बुनियादी संरचना – आपूर्ति कारकों; भुगतान प्रदर्शन तथा उपभोक्ता केन्द्रीयता पर आधारित है; तथा इसको आधार मानकर मार्च 2018 से अर्ध-वार्षिक रूप से गणना की जाती है। आरबीआई-डीपीआई अंक ने बड़ी वृद्धि को दर्शाया है जो यह दर्शाती है कि हाल के वर्षों में देश में विभिन्न डिजिटल भुगतानों के माध्यमों की तेजी से स्वीकृति तथा पहुँच हुई है। सूचकांक

पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2022 में 29.1 प्रतिशत बढ़ा है (चार्ट IV.36)।



IV.74 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत बिल पे लिमिटेड द्वारा संचालित बिल भुगतानों का एक अंतर प्रचालनीय प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए दिशानिर्देश वर्ष 2014 में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए थे। बीबीपीएस के उपयोगकर्ताओं को मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था तथा निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। शुरुआत में बीबीपीएस के कार्यक्षेत्र तथा कवरेज में बिल बनाने वाले अर्थात् डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), विद्युत, गैस, टेलिकॉम तथा पानी की पाँच श्रेणियाँ शामिल की गई थी। इसके दायरे का बाद में विस्तार किया गया था ताकि स्वैच्छिक आधार पर पात्र सहभागियों के रूप में, बार-बार बिलों की उगाही के लिए बिल बनाने वालों की सभी श्रेणियों को शामिल किया जा सके। बीबीपीएस प्रणाली में सितंबर 2019 में 168 बिल बनाने वाले थे तथा ₹1900 करोड़ के मूल्य के लिए 1.10 करोड़ लेन-देनों को पूरा किया था, जबकि नवंबर 2022 में 20,519 बिल बनाने वालों के साथ 16,585 करोड़ के मूल्य के लिए 9.49 करोड़ लेन-देनों को पूरा किया गया।

IV.75 नवम्बर 2022 की समाप्ति के समय में, भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के रूप में 43 बैंक

तथा 10 गैर-बैंक सहभागिता करते हैं। मई 2022 में, गैर-बैंक बीबीपीओयू के लिए न्यूनतम निवल मालियत अपेक्षा को ₹ 100 करोड़ से ₹ 25 करोड़ तक कम कर दिया गया ताकि उनकी सहभागिता बढ़ायी जा सके तथा ग्राहक निधियां संभालने वाले तथा भुगतान प्रणालियों में उसी प्रकार की जोखिम प्रोफाइल के अन्य गैर-बैंक सहभागियों के साथ उनकी निवल मालियत आवश्यकता को एक समान किया जा सके।

9.2 एटीएम

IV.76 मार्च 2022 के अंत में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित कुल एटीएम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 63 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत रही। निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ व्हाईट लेबल एटीएम ने ऑन-साइट और ऑफ-साइट एटीएम वृद्धि को बढ़ावा दिया (सारणी IV.24 तथा परिशिष्ट सारणी IV.11)।

IV.77 मार्च 2022 के अंत में, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की हिस्सेदारी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से कम रही। जहां पीएसबी के एटीएम अधिक समान रूप से वितरित किए जाते हैं, अन्य बैंक समूहों के एटीएम शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में अधिक लगाए जाते हैं (सारणी IV.25)।

सारणी IV.24 : एटीएम की संख्या (मार्च अंत में)

क्र. सं.	बैंक समूह	ऑन साइट एटीएम		ऑफ-साइट एटीएम		एटीएम की कुल संख्या	
		2021	2022	2021	2022	2021 (3+5)	2022 (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	पीएसबी	78,007	78,540	59,106	59,516	1,37,113	1,38,056
II	पीवीबी	35,282	38,254	38,087	37,289	73,369	75,543
III	एफबी	236	716	614	1,081	850	1,797
IV	एसएफबी*	2,079	2,237	52	25	2,131	2,262
V	पीबी#	1	1	111	70	112	71
VI	डबल्यूएलए	0	0	25,013	31,499	25,013	31,499
VII	सभी एससीबी (I से IV)	1,15,605	1,19,748	97,970	97,981	2,13,575	2,17,729
VIII	कुल (VI+VII)	1,15,605	1,19,748	1,22,983	1,29,480	2,38,588	2,49,228

टिप्पणी: 1. *: मार्च 2021 के अंत में 10 और मार्च 2022 के अंत में 12 अनुसूचित एसएफबी।

2. #: 6 अनुसूचित पीबी मार्च 2021 और मार्च 2022 के अंत में।

स्रोत : आरबीआई।

**सारणी IV.25: एटीएम का भौगोलिक वितरण:
बैंक समूह-वार @
(मार्च 2022 के अंत में)**

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
I. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	29,252 (21.19)	39,812 (28.84)	35,103 (25.43)	33,889 (24.55)	1,38,056 (100)
II. निजी क्षेत्र बैंक	6,415 (8.49)	19,328 (25.58)	18,897 (25.01)	30,903 (40.90)	75,543 (100)
III. विदेशी बैंक	136 (7.57)	373 (20.76)	450 (25.04)	838 (46.63)	1,797 (100)
IV. लघु वित्त बैंक*	217 (9.59)	740 (32.71)	722 (31.92)	583 (25.77)	2,262 (100)
V. भुगतान बैंक #	9 (12.68)	14 (19.72)	27 (38.03)	21 (29.58)	71 (100)
सभी एससीबी (I से V)	36,029 (16.55)	60,267 (27.68)	55,199 (25.35)	66,234 (30.42)	2,17,729 (100)
सभी एससीबी (व-द-व वृद्धि)	4.39	2.83	-7.59	9.50	1.94
डबल्यूएलए	16,410 (52.09)	10,234 (32.48)	3,150 (10.00)	1,705 (5.41)	31,499 (100)
डबल्यूएलए (व-द-व वृद्धि)	24.44	25.38	37.19	24.63	25.93

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के अंतर्गत कुल एटीएम का प्रतिशत में हिस्सा दर्शाते हैं।
2. *: मार्च 2021 के अंत में 10 और मार्च 2022 के अंत में 12 अनुसूचित एसएफबी।
3. #: 6 अनुसूचित पीबी मार्च 2021 और मार्च 2022 के अंत में।
4. @: डेटा में एटीएम और नकद पुनर्चक्रण मशीनों (सीआरएम) की संख्या शामिल है।
स्रोत : आरबीआई

10. उपभोक्ता संरक्षण

IV.78 रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी आरई के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की जा रही हैं। 12 नवंबर 2021 से प्रभावी, रिज़र्व बैंक के लोकपाल फ्रेमवर्क की "एक राष्ट्र एक लोकपाल" दृष्टिकोण के साथ पुनर्संरचना की गई और अधिकार क्षेत्रों की सीमाओं से परे ग्राहक शिकायतों का निशुल्क केंद्रीकृत निवारण प्रदान करता है। यह केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) और संपर्क केंद्र (सीसी) द्वारा समर्थित है।

IV.79 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक के लोकपालों द्वारा 4,18,184 शिकायतें प्राप्त की गईं, इसमें वर्ष दर वर्ष 9.4¹⁹ प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 98 प्रतिशत शिकायतों का निवारण/निपटारा किया गया। आरई के विरुद्ध शिकायतें जो आरबी-आईओएस के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन पर रिज़र्व बैंक के 30 कार्यालयों में स्थित ग्राहक शिक्षण एवं संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) द्वारा कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान सीईपीसी में 45,106 शिकायतें प्राप्त की गई थीं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार सीईपीसी की 98.5 प्रतिशत निपटान दर²⁰ रही।

IV.80 सीआरपीसी तथा सीसी सहित आरबी-आईओएस के कार्य की प्रभावशीलता का पता लगाने हेतु रिज़र्व बैंक ने दूरभाष साक्षात्कारों के माध्यम से पूरे भारत में एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में देश के 4,000 से अधिक उत्तर देने वालों ने भाग लिया। दोनों प्रणालियों अर्थात् पूर्व लोकपाल योजनाओं में से एक तथा वर्तमान आरबी-आईओएस दोनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने वाले 60 प्रतिशत उत्तर देने वाले यह महसूस करते हैं कि आरबीआई ओएस के अंतर्गत समग्र प्रक्रिया में इस योजना के शुरू होने के पहले छह महीनों में सुधार आया है।

IV.81 लोकपाल ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन आने से आरबीआईओ में कार्रवाई की जा रही शिकायतों के प्रापण और निपटान में वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्ति की तुलना नहीं हो सकती है। हालांकि, एटीएम/डेबिट कार्डों, मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उचित व्यवहार संहिता का पालन न करने तथा क्रेडिट कार्डों से संबन्धित शिकायतें वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक थीं तथा कुल शिकायतों में इनकी हिस्सेदारी 51.5 प्रतिशत थी (सारणी IV.26)

¹⁹ 2020-21 में 3,82,292 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें बैंकिंग लोकपाल योजना, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना के तहत प्राप्त शिकायतें शामिल हैं।

²⁰ निपटान दर की गणना इस प्रकार की जाती है: [(वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें) ÷ (पहले की शिकायतें + वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें)]।

सारणी IV.26: आरबीआईओ में शिकायतों की प्रकृति

श्रेणियाँ	2019-20	2020-21	2021-22#
एटीएम/डेबिट कार्ड	69,205	60,203	41,375
मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	39,627	44,385	40,597
उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	40,124	33,898	37,880
क्रेडिट कार्ड	26,616	40,721	34,828
ऋण और अग्रिम	14,731	20,218	30,734
प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता	22,758	35,999	22,031
जमा खाते	10,188	8,580	16,707
बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना	17,268	20,949	14,516
पेंशन भुगतान	6,884	4,966	6,179
बीसीएसबीआई कोड का पालन न करना	11,758	14,490	4,816
प्रेषण	4,130	3,394	3,235
डीएसए और रिकवरी एजेंट	1,474	2,440	1,604
पैरा-बैंकिंग	1,134	1,236	1,480
नोट और सिक्के	551	332	296
बीओ योजना के दायरे से बाहर	9,412	10,250	7,363
अन्य	30,844	39,686	40,855
कुल	3,06,704	3,41,747	3,04,496*

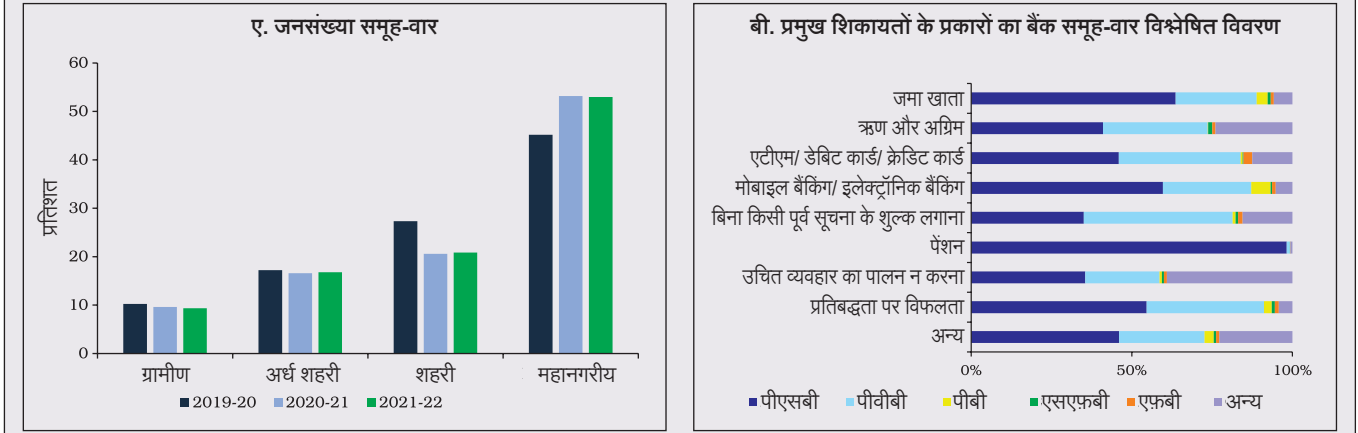
टिप्पणियाँ : 1. वर्ष संबंधित वर्ष के अप्रैल से मार्च तक संबंधित है;
 2. #: आरबीआईओ को सौंपी गई शिकायतों में से;
 3. *: सीआरपीसी द्वारा निपटाई जाने वाली 1,13,688 शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत : आरबीआई।

IV.82 वर्ष 2021-22 के दौरान शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों से आयी शिकायतों की हिस्सेदारी प्राप्त हुई कुल शिकायतों की 73.8 प्रतिशत थी, जो यह दर्शाता है कि रिज़र्व बैंक की

शिकायत निवारण व्यवस्थाओं के संबंध में इन क्षेत्रों में अधिक जागरूकता आयी है (चार्ट IV.37 ए)। निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध बिना पूर्व नोटिस के शुल्क लगाने संबंधी 46 प्रतिशत शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध पेंशन से संबन्धित 98.2 प्रतिशत शिकायतें दर्ज की गईं – पेंशनरों के लिए परंपरागत प्राथमिकता (चार्ट IV.37 बी तथा परिशिष्ट सारणी IV.12)।

IV.83 जमा बीमा प्रणाली की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने में, इस प्रकार लोगों का विश्वास कायम रहता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदान किए गए जमा बीमा में स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक कवर किए गए हैं। 80 प्रतिशत की अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में मार्च 2022 के अंत में भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा ₹ 5 लाख के साथ, कुल खातों का 97.9 प्रतिशत पूर्ण रूप से सुरक्षित था। राशि के अनुसार, 20 से 30 प्रतिशत की अंतरराष्ट्रीय

चार्ट IV.37: शिकायतों का वितरण



टिप्पणी: 1. आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं।
 2. 2021-22 के दौरान 162,126 शिकायतों यानी 53 प्रतिशत शिकायतों के लिए जनसंख्या समूह पर डेटा उपलब्ध नहीं था। इसलिए, उपलब्ध डेटा से अनुपात को बनाए रखते हुए उपलब्ध डेटा को सभी शिकायतों के लिए बहिर्वेशित किया गया है।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

सारणी IV.27: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमा राशि
(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	कुल निर्धारणीय जमा (एडी)*	कुल बीमाकृत जमा (आईडी)*	एडी के प्रति-शत के रूप में आईडी
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	92,53,975	50,05,209	54.1
निजी क्षेत्र के बैंक**	39	49,66,447	19,20,359	38.7
विदेशी बैंक	45	8,00,107	86,728	10.8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,92,966	4,08,744	82.9
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	981	750	76.4
सहकारी बैंक	1,899	10,35,154	6,88,642	66.5
कुल	2,040	1,65,49,630	81,10,431	49.0

टिप्पणियाँ: 1. *: सितंबर 2021 के जमा आधार के आधार पर यानी संदर्भ तिथि से छह महीने पहले।
2. **: निजी क्षेत्र के बैंकों के डेटा में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक शामिल हैं।
स्रोत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम।

बेंचमार्क²¹ की तुलना में निर्धारणीय जमा का 49.0 प्रतिशत बीमा द्वारा कवर किया गया था (सारणी IV.27)।

IV.84 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष के अंतरण के माध्यम से अर्थात् प्रत्येक वर्ष करों का भुगतान करने के बाद व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान तथा संबन्धित व्यय) घटाकर अतिरिक्त आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम को शामिल करते हुए, निवेशों से ब्याज आय तथा विफल बैंकों की आस्तियों से प्राप्त नकदी वसूली) द्वारा अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। परिसमापन/समामेलन में लिये गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करने के लिए यह निधि उपलब्ध है तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 1,46,842 करोड़ थी, जिससे 1.81 प्रतिशत का आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)²² प्राप्त हुआ।

IV.85 वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत निगम द्वारा ₹ 8,516.6 करोड़²³ के संकलित दावों का निपटान किया गया। इसमें डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के खंड

17(1) के अंतर्गत 15 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में राशि ₹ 1,225.0 करोड़ के मुख्य दावे तथा पूरक दावे सम्मिलित हैं तथा पूर्व पंजाब तथा महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (पीएमसीबीएल) के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए यूनैटी लघु वित्त बैंक (यूएसएफबी) को राशि ₹ 3791.6 करोड़ दिये गए। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इसमें सभी समावेशी दिशानिर्देश (आईडी) के अंतर्गत 22 शहरी सहकारी बैंकों की ₹ 3457.4 करोड़ की राशि के दावे भी शामिल हैं।

IV.86 वर्ष 2021-22 के दौरान, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया जिसके कारण आईडी के अंतर्गत रखे गए बैंकों के लिए जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि का भुगतान किया जा सका। डीआईसीजीसी को अब यह अधिकार प्राप्त है कि वह 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक ₹5 लाख तक की राशि इन बैंकों के जमाकर्ताओं को चुकता करें। बीमाकृत बैंक से अपेक्षित है कि वह आईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर अपने दावे प्रस्तुत करें, उसके बाद डीआईसीजीसी से अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करवाएँ तथा अगले 15 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को भुगतान करें। बीमाकृत बैंक या डीआईसीजीसी के लिए संविधि द्वारा समय बढ़ाने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, 45 दिनों के सांविधिक समय-सीमा के भीतर कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं के दावे की सूची प्रस्तुत न करने के दृष्टांत देखे गए हैं, जिससे ऐसे बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करने में डीआईसीजीसी को बाध्य होना पड़ा।

11. वित्तीय समावेश

IV.87 वित्तीय समावेश आर्थिक विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति प्रयास है। एक ओर जहां कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल तथा

²¹ आईडीआई (2013), प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए उन्नत मार्गदर्शन: जमा बीमा कवरेज, मार्गदर्शन पत्र, मार्च, www.iadi.org पर उपलब्ध है।

²² बीमा निधि और बीमित जमा राशि का अनुपात।

²³ निगम की त्वरित दावा निपटान नीति के तहत तीन सहकारी बैंकों के मामले में ₹42.6 करोड़ की राशि के लिए निपटाए गए मुख्य दावों को शामिल किया गया।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन से इन प्रयासों को एक कार्यनीतिक बल प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) 2019-24 इसके विज्ञान और मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करती है ताकि इसकी पहुँच बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो और निरंतर प्रगति बनी रहे। इस अति महत्वपूर्ण लक्ष्य द्वारा किफ़ायती रूप से औपचारिक वित्तीय सेवाओं को प्राप्त किया जा सकेगा और साथ ही वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

IV.88 जनवरी 2020 में, रिज़र्व बैंक ने यह लक्ष्य बनाया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर गांव और 500 परिवारों के छोटे गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट स्थापित किया जाएगा। 30 सितंबर 2022 की स्थिति अनुसार, इस लक्ष्य को 26 राज्यों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में प्राप्त कर लिया गया है। देश में पहचाने गए गाँवों तथा छोटे गाँवों की कवरेज 99.97 प्रतिशत पहुँच गई तथा केवल 2 राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में और 1 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् लद्दाख में 40 गाँवों को कवर करना शेष है।

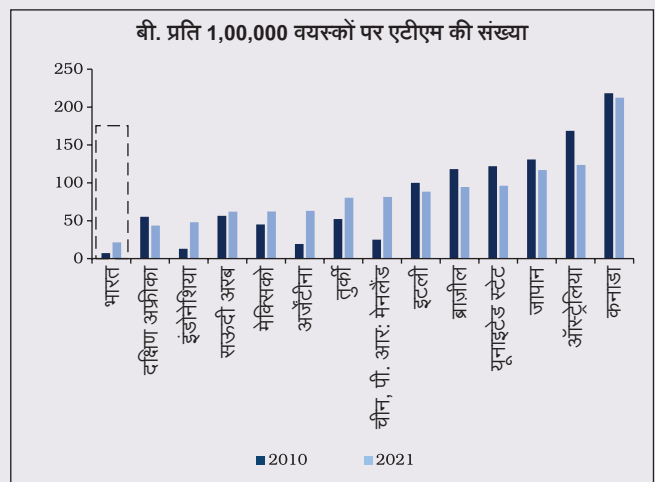
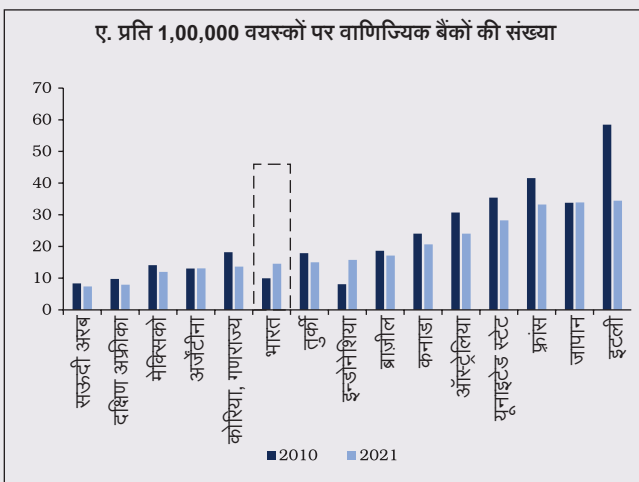
IV.89 आईएमएफ का नवीनतम वित्तीय पहुँच सर्वेक्षण (एफएएस) दर्शाता है कि तेज गति से डिजिटलीकरण के बावजूद

पिछले दशक में भारत में बैंक शाखाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, डिजिटलीकरण के कारण पूरे विश्व में बैंक शाखाएँ कम हो गई हैं (चार्ट IV.38 ए)।

IV.90 यद्यपि स्थापित एटीएम की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है (चार्ट IV.38 बी)। पीओएस टर्मिनलों तथा आधार समर्थित भुगतान प्रणालियों (ईपीएस) का उपयोग करने वाले माइक्रो-एटीएम जैसी सुविधाएँ इस कमी को पूरा करने में सहायक हैं।

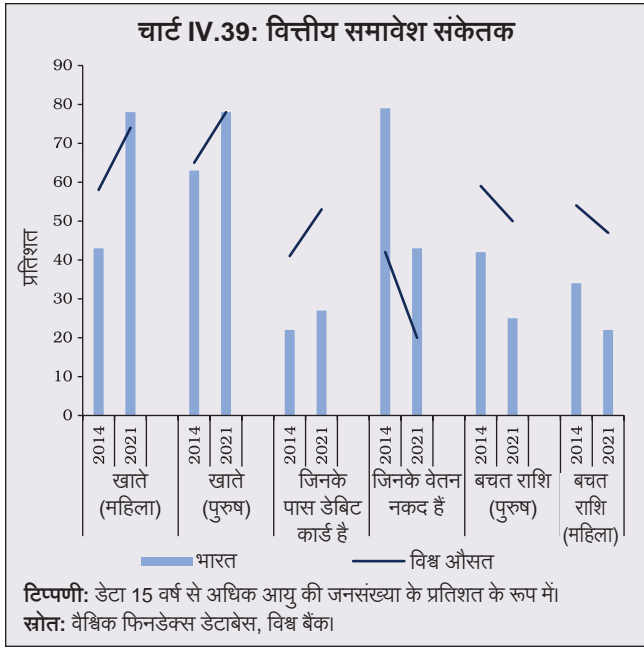
IV.91 विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस के अनुसार, वैश्विक औसत की तुलना में 78 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (15 वर्ष या अधिक आयु की जनसंख्या) के पास वर्ष 2021 में बैंक खाता था। वर्ष 2021 में, विश्व में खाते स्वामित्व में जेंडर गैप²⁴ वर्ष 2014 में 7 प्रतिशत बिन्दु से 4 प्रतिशत बिन्दु तक गिरा, भारत में यह जेंडर गैप समाप्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ, भारत में नकद में वेतन प्राप्त कर रही वयस्क जनसंख्या का अनुपात अभी भी 43 प्रतिशत पर उच्चतर है जबकि विकासशील देशों का यह

चार्ट IV.38: जी-20 देशों में वित्तीय समावेश में प्रगति



स्रोत: वित्तीय पहुँच सर्वेक्षण, आईएमएफ।

²⁴ जेंडर गैप का संबंध बैंक खाता रखने वाले पुरुषों के प्रतिशत में से बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत घटाने से है।



औसत 26 प्रतिशत है तथा विश्व औसत 20 प्रतिशत है (चार्ट IV.39)।

IV.92 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) नवोन्मेषी उपायों तथा लोगों की भागीदारी के माध्यम से देश में वित्तीय शिक्षण प्रयासों में सहयोग देते हैं। 01 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार, 1,112 सीएफएल स्थापित किए गए हैं तथा दिसंबर 2022 तक और 500 केन्द्रों को स्थापित करने की योजना है।

IV.93 इसके अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) द्वारा वित्तीय शिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 1,07,564 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 14-18 फरवरी 2022 के दौरान "डिजिटल अपनाएं, सुरक्षित रहें" थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया।

11.1 वित्तीय समावेश योजनाएं

IV.94 बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वित्तीय समावेश योजनाओं (एफआईपी) को लागू करें ताकि सतत रूप से वित्तीय समावेश के स्तर में वृद्धि करने की एक प्रणालीबद्ध पद्धति सुनिश्चित की जा सके। एफआईपी में विभिन्न मापदण्डों जैसे बैंकिंग आउटलेटों की संख्या (शाखाएँ तथा कारोबारी प्रतिनिधि

(बीसी)], बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीएस), इन खातों में प्राप्त की गई ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) तथा कारोबारी प्रतिनिधि – सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) माध्यम से की गई लेन-देन पर बैंकों की उपलब्धियां शामिल होती हैं।

IV.95 बीसी मॉडल पुरानी पारंपरिक शाखाओं की तुलना में तेज दर तथा कम लागत पर अंतिम छोर तक जाने तथा जमीनी स्तर पर पहुँचने की समस्या का निवारण करने में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वर्ष 2021-22 में गाँवों में कुल बैंकिंग आउटलेटों में से 97.5 प्रतिशत बीसी आउटलेट्स हैं जबकि शाखाएँ कम हो गई हैं। बीसी-आईसीटी मॉडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रियता हासिल की है जैसा कि इसके बढ़ते उपयोग से स्पष्ट है (सारणी IV.28)।

IV.96 नियत-स्थान कारोबारी प्रतिनिधि (एफबीसी) का राज्यवार वितरण, हालांकि, असमान रहता है - 50 प्रतिशत से अधिक एफबीसी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्थित हैं (चार्ट IV.40)। मार्च 2018 के बाद से, एफबीसी की कुल संख्या में पीबी का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें पीवीबी की उपस्थिति नगण्य है (चार्ट IV.41)।

11.2. वित्तीय समावेश सूचकांक

IV.97 रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेश के प्रसार का विवरण ज्ञात करने के लिए एक समग्र वित्तीय समावेश सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) तैयार किया है। इसके तीन उप-सूचकांक हैं, अर्थात् एफआई-एक्सेस, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता। सूचकांक में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ सरकार और क्षेत्रीय नियामकों से एकत्रित पेंशन क्षेत्र पर सूक्ष्मतम डेटा शामिल है। एफआई सूचकांक का मान मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए 56.4 था, जिसमें सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि हुई थी।

सारणी IV.28: वित्तीय समावेश योजना में प्रगति
(मार्च के अंत में)

क्र.सं.	विवरण	2010	2015	2020	2021	2022*
1	गांवों में बैंकिंग आउटलेट- शाखाएं	33,378	49,571	54,561	55,112	53,287
2	गांवों में बैंकिंग आउटलेट>2000-बीसी	8,390	90,877	149,106	850,406	18,92,462 ^
3	गांवों में बैंकिंग आउटलेट<2000-बीसी	25,784	408,713	392,069	340,019	3,26,008
4	गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट – बीसी	34,174	499,590	541,175	1,190,425	22,18,470 ^
5	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – अन्य मोड	142	4,552	3,481	2,542	2,479
6	गांवों में बैंकिंग आउटलेट – कुल	67,694	553,713	599,217	1,248,079	22,74,236 ^
7	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	96,847	635,046	426,745	12,95,307 ^
8	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,103	2,616	2659	2,661
9	बीएसबीडीए - शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	36,498	95,831	118,392	1,20,464
10	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	1,878	3,388	3,796	4,015
11	बीएसबीडीए - बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	7,457	72,581	87,623	1,07,415
12	बीएसबीडीए - कुल (संख्या लाख में)	735	3,981	6,004	6455	6,677
13	बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	5,500	43,955	1,68,412	2,06,015	2,27,879
14	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा प्राप्त (संख्या लाख में)	2	76	64	60	68
15	बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ (राशि करोड़ में)	10	1,991	529	534	731
16	केसीसी - कुल (संख्या लाख में)	240	426	475	466	473
17	केसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	4,38,229	6,39,069	6,72,624	7,10,715
18	जीसीसी - कुल (संख्या लाख में)	10	92	202	202	96
19	जीसीसी - कुल (राशि करोड़ में)	3,500	131,160	1,94,048	1,55,826	1,70,203
20	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में) #	270	4,770	32,318	30,551	28,533
21	आईसीटी-ए/सीएस-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में) #	700	85,980	8,70,643	8,49,771	9,05,252

टिप्पणी: 1. *: अनंतिम

2. #: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन।

3. ^: कुछ निजी क्षेत्र बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा में कुछ महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।

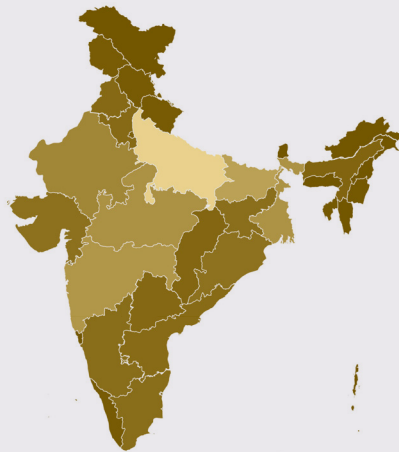
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणी।

11.3. प्रधानमंत्री जन धन योजना

IV.98 प्रमुख वित्तीय समावेश कार्यक्रम पीएमजेडीवाई का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से बुनियादी

बचत बैंक खातों की उपलब्धता, आवश्यकता-आधारित ऋण, धनप्रेषण, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक

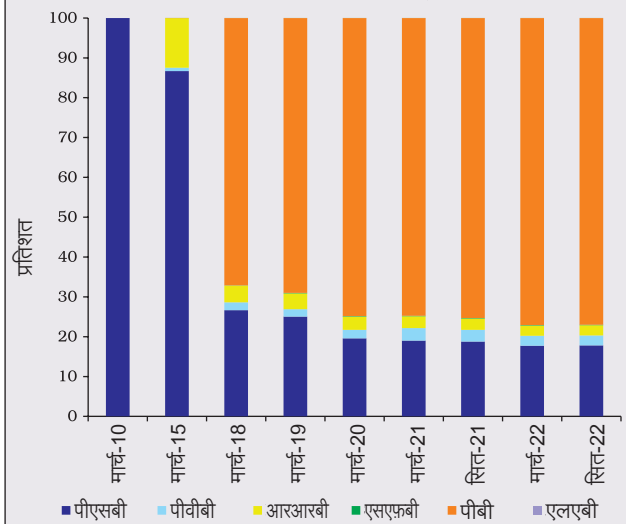
चार्ट IV.40: एफबीसी का राज्यवार वितरण



टिप्पणियाँ : हल्के रंग एफबीसी की अधिक संख्या से संबंधित हैं।

स्रोत : बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई)।

चार्ट IV.41: एफबीसी का बैंक समूह-वार वितरण

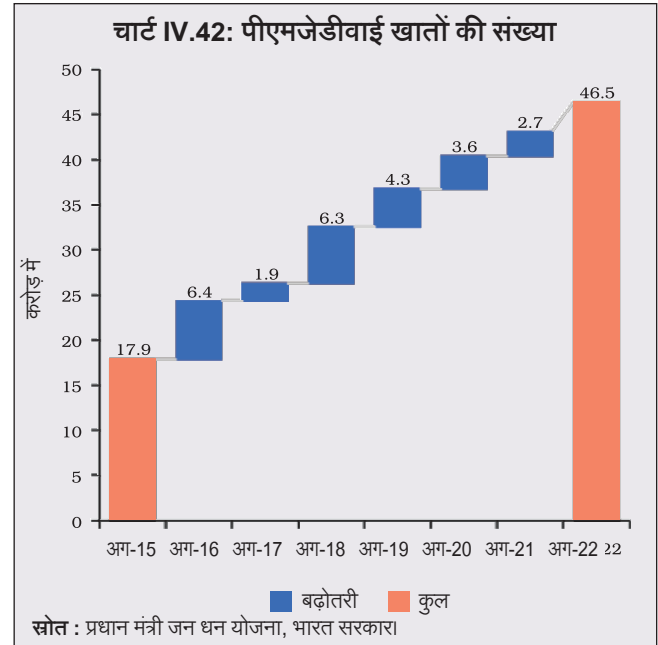


स्रोत : बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) और आरबीआई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2021-22

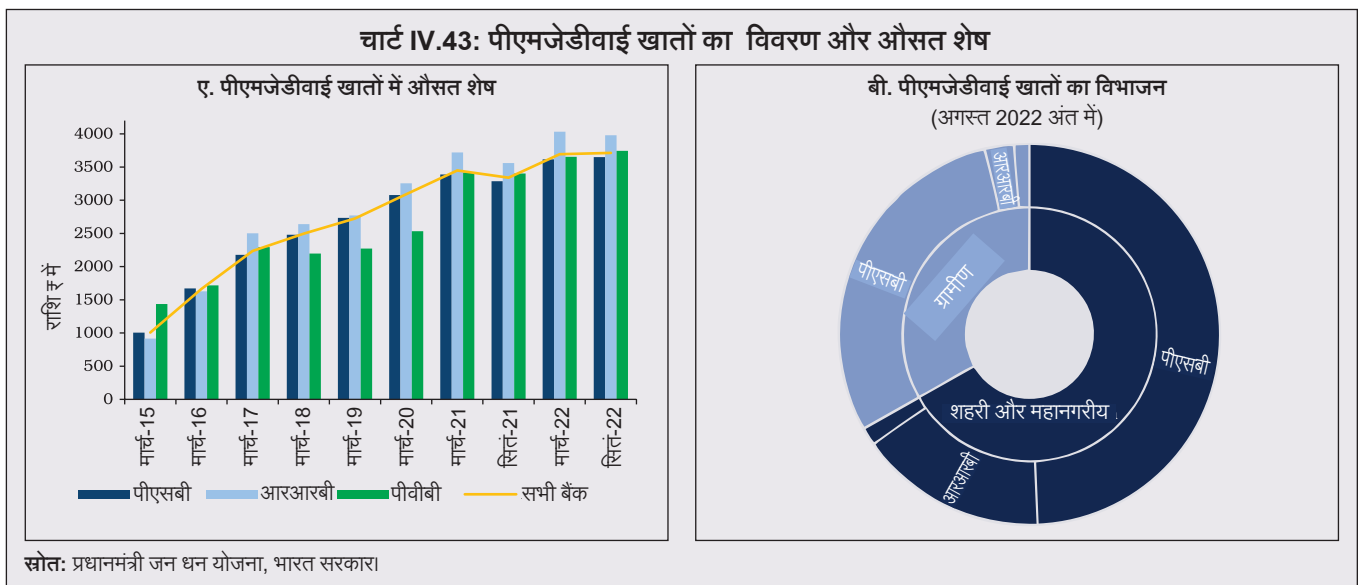
पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक वर्षों में उच्च विकास चरण के बाद, हाल के वर्षों में नए पीएमजेडीवाई खातों की अभिवृद्धि की दर धीमी हो गई है। यह एक संकेत है कि कार्यक्रम वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के अपने इच्छित उद्देश्य के करीब है (चार्ट IV.42)।

IV.99 अपने परिचालन के आठ वर्षों में, पीएमजेडीवाई के तहत कुल जमा शेष राशि में वृद्धि हुई है, प्रति खाता औसत जमा भी बढ़ गया है (चार्ट IV.43ए)। अगस्त 2022 के अंत में, 56 प्रतिशत खाता धारक महिलाएं हैं और 67 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में थे (चार्ट IV.43बी)। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजेडीवाई खाते को निष्क्रिय माना जाता है यदि इसमें दो साल तक ग्राहक-प्रेरित लेनदेन नहीं होता है। अगस्त 2022 तक, कुल 46.25 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 81.2 प्रतिशत सक्रिय थे, जो 2017²⁵ में 76 प्रतिशत थे। केवल 8.2 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते शून्य जमा शेष खाते थे।



11.4. एससीबी द्वारा नए बैंक शाखाएं

IV.100 लगातार दो वर्षों तक गिरावट के बाद, एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाओं में 2021-22 के दौरान 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टियर 4, टियर 5 और टियर 6 केंद्रों में



²⁵ स्रोत: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854909>

सारणी IV.29: एससीबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं का स्तर-वार विश्लेषित-विवरण

केंद्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
स्तर 1	2,194 (47.4)	2,279 (52.4)	1,541 (49.9)	1,543 (47.7)
स्तर 2	519 (11.2)	367 (8.4)	279 (9.0)	235 (7.3)
स्तर 3	712 (15.4)	570 (13.1)	481 (15.6)	426 (13.2)
स्तर 4	363 (7.8)	355 (8.1)	262 (8.5)	293 (9.1)
स्तर 5	373 (8.1)	282 (6.5)	178 (5.7)	226 (7.0)
स्तर 6	465 (10.1)	500 (11.5)	348 (11.3)	509 (15.7)
कुल	4,626 (100.0)	4,353 (100.0)	3,089 (100.0)	3,232 (100.0)

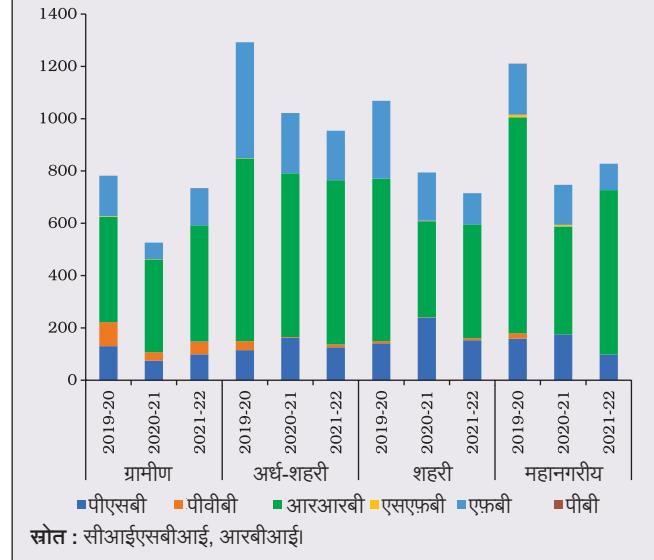
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में खोली गई शाखाओं के अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. केंद्रों का स्तर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है: 'स्तर 1' में 1,00,000 और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 2' में 50,000 से 99,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 3' में 20,000 से 49,999 तक की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 4' में 10,000 से 19,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, 'स्तर 5' में 5,000 से 9,999 की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, और 'स्तर 6' में 5000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल हैं।
3. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालय' शामिल नहीं हैं।
4. सभी जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
5. 2018-19 से आगे के आंकड़ों की तुलना के लिए, 1 सितंबर 2022 तक के सभी अनुसूचित बैंकों को लिया गया है।

स्रोत: सीआईएसबीआई, आरबीआई। सीआईएसबीआई के डेटा हमेशा बदलते रहते हैं और बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

खोली गई नई शाखाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। हालांकि नई शाखाओं में टियर 2 और टियर 3 केंद्रों की हिस्सेदारी एक साल पहले की तुलना में 2021-22 में घट गई, लेकिन वर्ष के दौरान खोली गई नई शाखाओं में से आधे से अधिक टियर 1 और टियर 3 केंद्रों में थीं (सारणी IV.29)।

IV.101 वर्ष 2021-22 के दौरान, पीवीबी द्वारा खोली गई नई शाखाओं में पिछले वर्ष में 30.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि पीवीबी ने सभी जनसंख्या समूहों में नई शाखाएं खोलीं, लेकिन महानगरीय क्षेत्रों में वृद्धि सबसे तेज थी। दूसरी ओर, पीएसबी ने 2021-22 में कम नई शाखाएं खोलीं। हालांकि, पीएसबी द्वारा नई खोली गई बैंक शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2020-21 में 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 20.8 प्रतिशत हो गई,

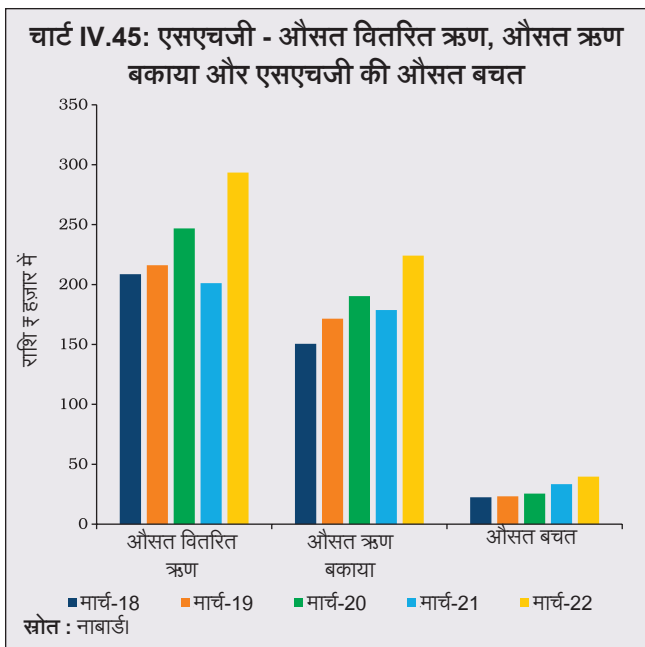
चार्ट IV.44: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई खोली गई बैंक शाखाओं का विभाजन



जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्रों का संयुक्त हिस्सा इसी अवधि में 63.6 प्रतिशत से घटकर 52.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.44)।

11.5. सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

IV.102 स्वयं सहायता समूह - बैंक संबद्ध कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी), जिसका उद्देश्य गरीबों को औपचारिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना है, दुनिया के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त आंदोलन के रूप में उभरा है। 2021-22 के दौरान, लगभग 34 लाख स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों से ऋण लिया। वर्ष के दौरान वितरित ऋण के औसत आकार के साथ-साथ बकाया ऋण के आकार में मार्च 2021 के अंत में गिरावट आई थी, जो कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों को दर्शाता है। यह मार्च 2022 के अंत तक फिर से सक्रिय हुआ और मार्च 2019 के अंत के स्तर (चार्ट IV.45) को पार कर गया। दक्षिणी क्षेत्र (36 प्रतिशत) में 2021-22 के दौरान बचत से जुड़े एसएचजी का सबसे अधिक हिस्सा था, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र (27.4 प्रतिशत) और पश्चिमी क्षेत्र (11.4 प्रतिशत) था (परिशिष्ट सारणी IV.13)। एसएचजी का एनपीए अनुपात 2020-21 में 4.73 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 3.80 प्रतिशत हो गया।



IV.103 संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) पट्टेदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों और छोटे/सीमांत किसानों और अन्य गरीब व्यक्तियों के रूप में भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप का एक साधन है। बैंकों द्वारा जेएलजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने 2017 में एक व्यवसाय मॉडल पेश किया, जिसके तहत बैंक (पीएसबी, आरआरबी और सहकारी बैंक) एमओयू में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर जेएलजी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करते हैं। बैंकों द्वारा जेएलजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने 2017 में एक व्यवसाय मॉडल पेश किया, जिसके तहत बैंक (पीएसबी, आरआरबी और सहकारी बैंक) एमओयू में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर जेएलजी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करते हैं। इस योजना के अंतर्गत, जेएलजी गठन और संबद्ध के लिए नाबार्ड से अनुदान सहायता का आश्वासन दिया जाता है। 2021-22 के दौरान, बैंकों द्वारा जेएलजी को वितरित ऋण में 93.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि

एक साल पहले इसमें 29.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। 31 मार्च 2022 तक प्रोत्साहित संचयी जेएलजी के संदर्भ में, दक्षिणी राज्यों ने 49 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, इसके बाद पश्चिमी राज्यों में 48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

11.6. व्यापारिक प्राप्य-राशि बड़ाकरण प्रणाली (ट्रेड्स)

IV.104 ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो एमएसएमई को अनेक वित्त-दाताओं के माध्यम से व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण / छूट की सुविधा प्रदान करके उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को प्रबंधित करने में मदद करता है। ये प्राप्तियां सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉरपोरेट और अन्य खरीददारों से बकाया हो सकती हैं। ट्रेड्स को 2014 में रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया था, और 2017 में तीन प्लेटफॉर्मों को संचालित करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे। 2021-22 के दौरान, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपलोड और वित्तपोषित चालानों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई और सफलता दर²⁶ एक साल पहले 91.3 प्रतिशत से बढ़कर 94.7 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.30)।

11.7. क्षेत्रीय बैंकिंग की पहुँच

IV.105 मार्च 2022 के अंत में, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के संकेन्द्रण के कारण, अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक शाखा द्वारा सेवा की गई आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक थी। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में अंतर कम रही थी (चार्ट IV.46)।

सारणी IV.30: टीआरडीएस के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति

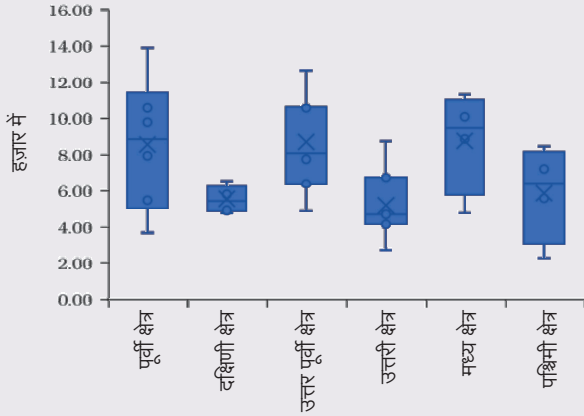
(बीजक संख्या में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अपलोड किया गया चालान		वित्तपोषित चालान	
	राशि	चालान	राशि	चालान
2018-19	251.695	6.699.57	232.098	5.854.48
2019-20	530.077	13.088.27	477.969	11.165.86
2020-21	861.560	19.669.84	786.555	17.080.14
2021-22	1,733.553	44,111.80	1,640,824	40,308.59

स्रोत : आरबीआई

²⁶ अपलोड किए गए ऐसे चालानों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वित्तपोषित होते हैं।

चार्ट IV.46: प्रति बैंक शाखा क्षेत्रवार औसत जनसंख्या
(मार्च 2022 के अंत में)



स्रोत : आरबीआई और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएस-पीआई)।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.106 मार्च 2022 के अंत में, 12 एससीबी द्वारा प्रायोजित 43 आरआरबी थे, जिसमें 21,892 शाखाएं थीं और इनका परिचालन 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख) में 29.7 करोड़ जमा खातों और 2.7 करोड़ ऋण खातों तक फैला हुआ था। उनकी 92 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थीं। दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र की रही (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

12.1. तुलन पत्र विश्लेषण

IV.107 पिछले 46 वर्षों के दौरान, सभी हितधारकों (जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों) ने आरआरबी में 8,393 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। इसके विपरीत,

2021-22 और 2022-23 के दौरान आरआरबी में 10,890 करोड़ रुपये लगाने का बजट है, जिसमें केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत योगदान, राज्य सरकारों से 15 प्रतिशत और शेष राशि प्रायोजक बैंकों से होगा। पूंजी निवेश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिचालन और अभिशासन में सुधारों के साथ प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके लिए, एक सतत व्यवहार्यता योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य ऋण विस्तार, व्यापार विविधीकरण, एनपीए में कमी और लागत को तर्कसंगत बनाना है।

IV.108 2021-22 के लिए, 22 आरआरबी के लिए पुनर्पूँजीकरण सहायता के रूप में 8,168 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। मार्च 2022 के अंत में, नाबार्ड ने प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा आनुपातिक राशि जारी करने के बाद 21 आरआरबी को 3,197.29 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार का हिस्सा जारी किया था।

IV.109 वर्ष के दौरान, आरआरबी के समेकित तुलन पत्र की वृद्धि में ऋण और अग्रिमों के साथ-साथ आस्ति पक्ष में निवेश और देयताओं में जमा और उधार की वृद्धि में सुस्ती के कारण कमी आई। आरआरबी की जमा वृद्धि एससीबी की तुलना में कम थी। मार्च 2022 के अंत में, आरआरबी में एससीबी²⁷ की सभी श्रेणियों के बीच कम लागत वाली सीएएसए जमा (कुल जमा का 54.5 प्रतिशत) का उच्चतम हिस्सा था (सारणी IV.31)।

IV.110 आरआरबी को पिछले वर्ष के अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य है। 2021-22 के दौरान, 2 आरआरबी को छोड़कर अन्य सभी ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 90 प्रतिशत से अधिक ऋण देकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया, जिसमें से

²⁷ कुल जमा में पीएसबी की सीएएसए की हिस्सेदारी 43.8 फीसदी, पीवीबी की 47 फीसदी, एसएफबी की 40.5 फीसदी और विदेशी बैंकों की 43.8 फीसदी रही।

सारणी IV.31: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	मार्च अंत में		व-द-व वृद्धि प्रतिशत में	
		2021	2022	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
1	शेयर पूंजी	8,393	14,880	6.9	77.3
2	आरक्षित	30,348	34,359	13.2	13.2
3	जमाराशियां	5,25,226	5,62,538	9.7	7.1
	3.1 चालू	11,499	12,042	7.0	4.7
	3.2 बचते	2,71,516	2,94,438	11.1	8.4
	3.3 मियादी	2,42,211	2,56,057	8.3	5.7
4	उधार	67,864	73,881	24.8	8.9
	4.1 नाबार्ड से	61,588	67,054	33.5	8.9
	4.2 प्रायोजक बैंक	3,444	3,879	-23.8	12.6
	4.3 अन्य	2,832	2,948	-24.6	4.1
5	अन्य देयताएं	19,754	19,742	-2.3	-0.1
	कुल देयताएं / आस्तियां	6,51,585	7,05,400	10.8	8.3
6	उपलब्ध नकद	2,954	3,119	3.3	5.6
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	18,947	22,174	13.2	17.0
8	चालू खाते में शेष राशि	5,987	8,127	-21.4	35.8
9	निवेश	2,75,658	2,95,665	9.9	7.3
10	ऋण और अग्रिम (शुद्ध)	3,15,181	3,42,479	12.5	8.7
11	अचल संपत्ति	1,229	1,256	-0.5	2.2
12	अन्य आस्तियां #	31,629	32,580	11.0	3.0
	12.1 संचित हानियाँ	8,264	9,062	27.8	9.7

टिप्पणी: 1. #: संचित घाटा शामिल है।
2. आंकड़ों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है। प्रतिशत भिन्नता थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

लगभग 70 प्रतिशत कृषि और 11.5 प्रतिशत एमएसएमई के लिए था (सारणी IV.32 और परिशिष्ट सारणी IV.15)।

सारणी IV.32: आरआरबी द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उद्देश्य/मार्च अंत	2021	2022
		3	4
1	2	3	4
I	प्राथमिकता (i से v)	3,00,962	3,24,207
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	90.1	89.4
	i. कृषि	2,33,145	2,52,890
	ii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	39,543	41,609
	iii. शिक्षा	2,132	1,896
	vi. आवास	21,127	22,020
	v. अन्य	5,016	5,791
II	गैर-प्राथमिकता (i से vi)	33,209	38,631
	कुल बकाया ऋण का प्रतिशत	9.9	10.6
	i. कृषि	29	0
	ii. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	434	35
	iii. शिक्षा	92	139
	iv. आवास	4,347	6,187
	v. व्यक्तिगत ऋण	8,311	10,088
	vi. अन्य	19,996	22,181
	कुल (I+II)	3,34,171	3,62,838

टिप्पणी: कुल राशि ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण कुल के साथ मेल नहीं खाने की संभावना है।

स्रोत : नाबार्ड।

12.2. वित्तीय प्रदर्शन

IV.111 2018-19 और 2019-20 में लगातार दो वर्षों तक घाटे की रिपोर्ट करने के बाद, आरआरबी ने 2020-21 में निवल लाभ दर्ज किया, जिसमें 2021-22 में और सुधार हुआ। उनके सीआरएआर में भी काफी वृद्धि हुई (सारणी IV.33)। वर्ष के दौरान, 9 प्रतिशत की विनियामकीय आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले आरआरबी की संख्या 16 से घटकर 13 हो गई और ऋणात्मक सीआरएआर वाले आरआरबी की संख्या 8 से घटकर 3 हो गई।

सारणी IV.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि		व-द-व परिवर्तन प्रतिशत में	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
ए	आय (i + ii)	53,858	56,585	8.9	5.1
	i ब्याज आय	46,803	48,048	7.1	2.7
	ii अन्य आय	7,055	8,537	22.6	21.0
बी	व्यय (i+ii+iii)	52,176	53,367	1.0	2.3
	i ब्याज व्यय किया गया	25,588	24,817	-1.5	-3.0
	ii परिचालन व्यय	20,201	21,295	0.6	5.4
	जिनमें से वेतन बिल	15,799	16,338	7.8	3.4
	iii प्रावधान और आकस्मिकताएं	6,386	7,254	14.1	13.6
	जिनमें से आय कर	1,279	1,278	37.5	-0.1
सी	लाभ				
	i परिचालन लाभ	7,872	10,337	164.9	31.3
	ii निवल लाभ	1,682	3,219	--	91.3
डी	कुल औसत आस्तियां	6,17,305	6,66,532	11.1	8.0
ई	वित्तीय अनुपात #				
	i परिचालन लाभ	1.3	1.6		
	ii निवल लाभ	0.3	0.5		
	iii आय (ए + बी)	8.7	8.5		
	ए) ब्याज आय	7.6	7.2		
	बी) अन्य आय	1.1	1.3		
	iv व्यय (क+ख+ग)	8.5	8.0		
	a) खर्च किया गया ब्याज	4.1	3.7		
	बी) परिचालन व्यय	3.3	3.2		
	जिनमें से वेतन बिल	2.6	2.5		
	ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.0	1.1		
एफ	विक्षेपणात्मक अनुपात (%)				
	सकल एनपीए अनुपात	9.4	9.1		
	सीआरएआर	10.2	12.7		

टिप्पणियाँ: 1: # वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संबंध में प्रतिशत हैं।
2: --: आरआरबी पिछले वर्ष के घाटे से 2020-21 में लाभ में आ गए।
3: आंकड़ों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण योग का भिन्न हो सकता है।
4: प्रावधानों और आकस्मिकताओं में भुगतान किए गए आयकर/आयकर के लिए प्रावधान शामिल हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

IV.112 वर्ष के दौरान, ब्याज आय मामूली दर से बढ़ी, लेकिन ब्याज व्यय में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप निवल ब्याज आय के साथ-साथ निवल ब्याज मार्जिन भी अधिक रहा। लाभ कमाने वाले आरआरबी की संख्या 2020-21 में 30 से बढ़कर 2021-22 में 34 हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.14)।

12.3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.113 चूंकि आरआरबी अपने कुल ऋण का लगभग 48 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को उधार देते हैं, इसलिए वे पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ श्रेणी में प्रमुख विक्रेता हैं। चूंकि पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ का कारोबार पीएसएलसी-सामान्य श्रेणी की तुलना में प्रीमियम पर किया जाता है, आरआरबी प्रथम श्रेणी के तहत पीएसएलसी की अधिक बिक्री करते हैं और 75 प्रतिशत के समग्र पीएसएल लक्ष्य को पूरा करने के लिए द्वितीय श्रेणी के तहत पीएसएलसी खरीदकर इसकी भरपाई करते हैं (सारणी IV.34)।

IV.114 पीएसएलसी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विविध आय बढ़ाने के लिए अपने उच्च पीएसएल पोर्टफोलियो का लाभ उठाने में मदद की है (चार्ट IV.47)। हालांकि सभी एससीबी के कुल बैंक ऋण में आरआरबी का हिस्सा सिर्फ 3 प्रतिशत है, लेकिन कुल पीएसएलसी कारोबार मात्रा (निर्गम और खरीद) में उनकी हिस्सेदारी 2021-22 के दौरान 35 प्रतिशत थी।

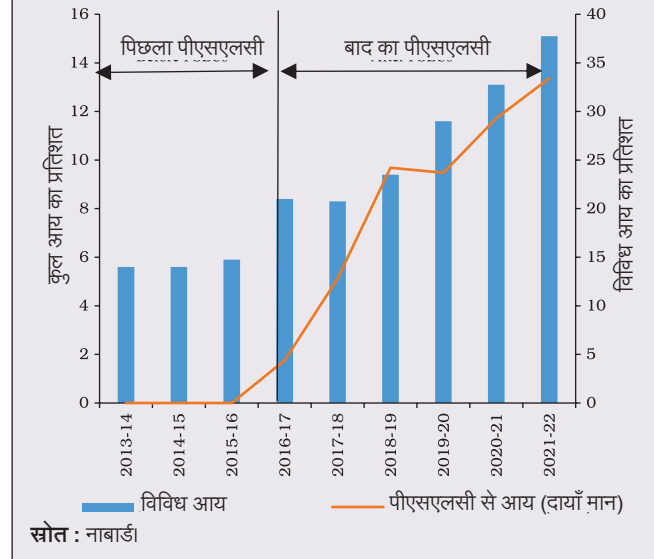
सारणी IV.34: आरआरबी के पीएसएलसी लेनदेन

(राशि करोड़ रुपये में)

पीएसएलसी श्रेणी	जारी पीएसएलसी के मूल्य		खरीदे गए पीएसएलसी के मूल्य	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
पीएसएलसी कृषि	40.731	29.850	735	1,150
पीएसएलसी सामान्य	4,004	1,750	52,628	67,771
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	3,580	7,644	7,125	6,223
पीएसएलसी एसएफ/एमएफ	78,837	1,17,163	4,953	865
कुल	1,27,151	1,56,407	65,440	76,009

स्रोत: ओएसएस विवरणी, सुनिश्चित पोर्टल, नाबाडी

चार्ट IV.47: विविध आय में पीएसएलसी का योगदान



13. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

IV.115 ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिए तथा स्थानीय क्षेत्रों में निवेश हेतु उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, देश में 79 शाखाओं²⁸ सहित दो स्थानीय क्षेत्र के बैंक परिचालन में थे। वर्ष 2021-22 में, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की समेकित तुलन पत्रों में मंदी आयी। चूंकि ऋण में आई यह मंदी जमा में आई मंदी से कम थी, ऋण-जमा अनुपात वर्ष 2020-21 में 80.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 82 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.35)।

सारणी IV.35: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की प्रोफाइल

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

	2020-21	2021-22
1. आस्तियाँ	1,166.2 (14.1)	1,273.2 (9.18)
2. जमा राशियाँ	952.5 (17.05)	1,020.3 (7.11)
3. सकल अग्रिम	769.2 (16.46)	838.0 (8.95)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

²⁸ स्रोत: बैंकिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई)।

13.1 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

IV.116 वर्ष के दौरान, खर्च किए गए ब्याज के साथ-साथ अर्जित ब्याज आय दोनों में गिरावट आई, जिससे निवल लाभ स्थिर रहा। परिचालन व्यय, विशेष रूप से वेतन बिल में तेज वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन लाभ में धीमी वृद्धि देखी गई। (सारणी IV.36)।

सारणी IV.36: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

	राशि ₹ करोड़ में		व-द-व वृद्धि प्रतिशत में	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
ए. आय (i+ii)	148	159	9.5	7.1
i. ब्याज आय	123	130	14.8	6.2
ii. अन्य आय	25	28	-10.4	11.7
बी. व्यय (i+ii+iii)	122	132	0.0	9.0
i. खर्च किया गया ब्याज	55	58	6.5	4.7
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	20	22	42.8	11.9
iii. परिचालन खर्च जिनमें से वेतन बिल	47	53	-16.7	12.8
	22	25	5.1	12.5
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ/हानि	47	49	68.4	4.3
ii. निवल लाभ/ हानि	27	26	94.3	-1.4
डी. निवल ब्याज आय	68	73	22.7	7.4
ई. कुल आस्तियां	1,166	1,273	14.1	9.2
एफ. वित्तीय अनुपात				
i. परिचालन लाभ	4.0	3.8		
ii. निवल लाभ	2.3	2.1		
iii. आय	12.7	12.5		
iv. ब्याज आय	10.5	10.2		
v. अन्य आय	2.2	2.2		
vi. व्यय	10.4	10.4		
vii. खर्च किया गया ब्याज	4.7	4.5		
viii. परिचालन खर्च	4.0	4.1		
ix. मजदूरी बिल	1.9	1.9		
x. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.7	1.7		
xi. निवल ब्याज आय	5.8	5.7		

टिप्पणी: 1. 2020-21 और 2021-22 के लिए वित्तीय अनुपात की गणना केवल वर्तमान वर्ष की आस्तियों के आधार पर की जाती है।

2. 'मजदूरी विधेयक' को कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधानों के रूप में लिया जाता है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), आरबीआई।

14. लघु वित्त बैंक

IV.117 छोटी कारोबारी इकाइयों, छोटे तथा सीमांत किसानों, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आवश्यकता अनुरूप निर्मित जमा उत्पादों तथा प्रौद्योगिकी आधारित कम-लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय समावेश को गति देने के लिए 2016 में लघु वित्त बैंकों की स्थापना की गई थी। मार्च 2022 के अंत में, पूरे देश में 5,677 देशी शाखाओं सहित बारह लघु वित्त बैंक परिचालन में थे, इनमें शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड तथा यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल थे जिन्हें वर्ष 2021-22 में लाइसेंसीकृत किया गया था।

14.1. तुलन पत्र

IV.118 वर्ष 2021-22 के दौरान, लघु वित्त बैंकों की समेकित तुलन पत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलन पत्र की तुलना में अधिक तेज गति से वृद्धि हुई। जमा वृद्धि के साथ-साथ ऋणों तथा अग्रिमों की वृद्धि भी साल-दर-साल त्वरित हुई। संतुलन पर, लघु वित्त बैंकों का ऋण जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 99 प्रतिशत से वर्ष 2021-22 में 93.2 प्रतिशत तक कम हो गया, यद्यपि यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात से उच्चतर रहा (सारणी IV.37)।

14.2 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार

IV.119 लगातार तीन वर्षों के दौरान गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 के दौरान लघु वित्त बैंकों के कुल उधार में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष में अंतराल के बाद, वर्ष 2022 में लघु वित्त बैंकों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के 75 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में, एमएसएमई पर फोकस रहा, उसके बाद यह कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों पर रहा (सारणी IV.38)।

14.3 वित्तीय कार्य-निष्पादन

IV.120 वर्ष 2021-22 के दौरान, लघु वित्त बैंकों का निवल लाभ तथा परिचालन लाभ संकुचित हो गये। यह गिरावट उच्चतर परिचालन व्ययों तथा अशोध्य ऋणों के

सारणी IV.37: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च अंत में)

क्र. मद सं.	राशि		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में)
	2021	2022	2021-22
1	3	4	5
1 शेयर पूंजी	5,375.4	5,800.2	7.9
2 आरक्षित और अधिशेष	14,800.3	16,543.5	11.8
3 स्तर II बांड स्तर II ऋण	2,468.0	1,687.7	-31.6
4 जमा	1,09,472.5	1,45,730.5	33.1
4.1 वर्तमान मांग जमा	3,964.2	5,770.0	45.6
4.2 बचत	22,198.3	43,576.8	96.3
4.3 मीयादी	83,310.0	96,383.7	15.7
5 उधार (स्तर II बांड सहित)	27,828.2	27,011.3	-2.9
5.1 बैंक	1,366.4	4,303.7	215.0
5.2 अन्य	26,461.8	22,707.6	-14.2
6 अन्य देयताएं और प्रावधान	6,076.3	7,990.8	31.5
कुल देयताएं / आरिस्त	1,63,552.5	2,03,076.2	24.2
7 उपलब्ध नकद	1,052.2	1,235.0	17.4
8 आरबीआई के पास शेष	5,869.2	7,490.1	27.6
9 अन्य बैंक शेष/वित्तीय संस्थाओं के पास शेष	12,309.1	10,212.3	-17.0
10 निवेश	30,659.8	41,661.5	35.9
11 ऋण और अग्रिम	1,08,612.6	1,35,802.4	25.0
12 अचल संपत्ति	1,676.3	2,001.0	19.4
13 अन्य आस्तियां	3,373.2	4,674.0	38.6

टिप्पणी: डेटा मार्च 2021 के अंत में 10 और मार्च 2022 के अंत में 12 अनुसूचित एसएफबी से संबंधित है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई

लिए प्रावधानीकरण के कारण आयी थी। लघु वित्त बैंकों की आरिस्त गुणवत्ता में वर्ष के दौरान मामूली सुधार आया (सारणी IV.39)।

सारणी IV.38: लघु वित्त बैंकों द्वारा उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

उद्देश्य	2021	2022
I प्राथमिकता (i से v)	70.5	75.6
i. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	22.8	26.1
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	27.1	28.8
iii. शिक्षा	0.1	0.1
iv. आवास	4.5	5.5
v. अन्य	16.0	15.1
II गैर-प्राथमिकता (i से vi)	29.5	24.4
कुल (I+II)	100.0	100.0

टिप्पणी: कुल अग्रिमों में हिस्सा।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई

सारणी IV.39: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. मद सं.	राशि		व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में)
	2020-21	2021-22	2021-22
1	2	3	4
ए. आय (i + ii)	22,499.9	25,060.0	11.4
i ब्याज आय	19,523.4	22,120.4	13.3
ii अन्य आय	2,976.4	2,939.6	-1.2
बी. व्यय (i+ii+iii)	20,462.2	24,086.5	17.7
i खर्च किया गया ब्याज	9,122.2	9,512.6	4.3
ii परिचालन खर्च	7,549.0	9,815.9	30.0
जिनमें से स्टाफ खर्च	4,301.8	5,304.5	23.3
iii प्रावधान और आकस्मिकताएं	3,791.0	4,758.0	25.5
सी. लाभ (कर पूर्व)	2,580.9	1,283.8	-50.3
i परिचालन लाभ (ईबीपीटी)	5,828.7	5,731.5	-1.7
ii निवल लाभ (पीएटी)	2,037.7	973.5	-52.2
डी. कुल आरिस्तियां	1,63,552.5	2,03,076.2	24.2
ई. वित्तीय अनुपात*			
i परिचालन लाभ	3.6	2.8	
ii निवल लाभ	1.2	0.5	
iii आय (ए + बी)	13.8	12.3	
ए. ब्याज आय	11.9	10.9	
बी. अन्य आय	1.8	1.4	
iv व्यय (क+ख+ग)	12.5	11.9	
ए. खर्च किया गया ब्याज	5.6	4.7	
बी. परिचालन खर्च	4.6	4.8	
जिनमें से, कर्मचारी व्यय	2.6	2.6	
सी. प्रावधान और आकस्मिकताएं	2.3	2.3	
एफ. विशेषणात्मक अनुपात (%)			
सकल एनपीए अनुपात	5.4	4.9	
सीआरएआर	22.1	19.3	
कोर सीआरएआर	20.1	17.6	

टिप्पणी: #: कुल आरिस्तियों के प्रतिशत के रूप में।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई

15. भुगतान बैंक

IV.121 भुगतान बैंकों की स्थापना प्रवासी श्रमिक, निम्न-आय वाले परिवारों, छोटे कारोबारों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र संस्थाओं के लिए छोटी बचतों की सुविधा देने तथा उनको भुगतान तथा धन-प्रेषण सेवाएँ देने के लिए प्रमुख संस्थाओं के रूप में की गई थी। मार्च 2022 के अंत में, छह भुगतान बैंक परिचालन में थे, जिनमें से तीन अपने परिचालनों में लाभप्रदता हासिल कर सके।

सारणी IV.40: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

क्र. मद सं.	(राशि ₹ करोड़ में)		
	2020	2021	2022
1 कुल पूंजी और आरक्षित	1,868	1,761	2,494
2 जमाराशियां	2,306	4,625	7,854
3 अन्य देयताएं और प्रावधान	4,254	6,083	8,172
कुल देयताएं / आस्तियां	8,429	12,469	18,520
1 नकद और आरबीआई के पास शेष	785	1,255	1,560
2 बैंकों और मुद्रा बाजार में शेष	2,101	2,393	3,322
3 निवेश	4,077	7,116	10,178
4 अचल संपत्ति	351	355	372
5 अन्य आस्तियां	1,115	1,350	3,088

टिप्पणी: डेटा छह से संबंधित है।
स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

15.1. तुलन पत्र

IV.122 अपने अधिदेश के अनुसार, भुगतान बैंकों का आस्तिक पक्ष एसएलआर निवेशों तथा अन्य बैंकों के पास मांग तथा अल्प सूचना पर दी गई मुद्रा राशि पर केन्द्रित है। उनकी देयताओं में 42.4 प्रतिशत जमा शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश मांग पर हैं। मार्च 2022 अंत में, सभी भुगतान बैंकों ने 15 प्रतिशत की विनियामकीय न्यूनतम सीआरएआर का पालन किया है (सारणी IV.40)।

15.2 वित्तीय प्रदर्शन

IV.123 ब्याज और गैर-ब्याज आय दोनों में वृद्धि के बावजूद, पीबी ने 2021-22 में उच्च परिचालन व्यय के कारण हानि का सामना किया (सारणी IV.41)। भुगतान बैंक मुख्य रूप से छह आय माध्यमों से अपने राजस्व अर्जित करते हैं जो इस प्रकार हैं (i) ग्राहकों को विप्रेषण तथा नकद आहरण सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम से आय; (ii) अन्य बैंकों को बीसी सेवाएं देकर; (iii) यूटिलिटी बिल भुगतानों पर लेन-देन प्रभार; (iv) नकद प्रबंधन/ वसूली सेवाएं देकर; (v) पीओएस टर्मिनलों के माध्यम से लेन-देन पर कमीशन तथा एमडीआर प्रभारों तथा अन्य छोटी लेन-देन द्वारा; तथा (vi) पैरा-बैंकिंग गतिविधियों

सारणी IV.41: भुगतान बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. मद सं.	2019-20	2020-21	2021-22
ए. आय (i+ii)			
i. ब्याज आय	348	360	460
ii. गैर-ब्याज आय	3,115	3,562	5,416
बी. व्यय			
i. ब्याज खर्च	62	100	157
ii. परिचालन खर्च	4,324	4,584	5,826
प्रावधान और आकस्मिकताएं जिसमें से	-96	36	24
जोखिम प्रावधान	3	9	17
कर प्रावधान	-100	22	5
सी. निवल ब्याज आय	286	260	303
डी. लाभ			
i. परिचालन लाभ (ईबीपीटी)	-923	-762	-107
ii. निवल लाभ/ हानि	-827	-798	-130

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

द्वारा। चूंकि भुगतान बैंकों पर उत्पाद के रूप में ऋण की पेशकश करने की रोक लगी है, उनका आय अर्जन कम हैं।

IV.124 हालांकि लागत-आय अनुपात द्वारा मापी जाने वाली दक्षता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, लेकिन लाभदायक पीबी के लिए भी मार्जिन कम रहे थे। अन्य प्रदर्शन मैट्रिक्स, जैसे आरओए, आरओई, परिचालन लाभ- कार्यशील निधि अनुपात और लाभ मार्जिन वर्ष के दौरान ऋणात्मक रहे, लेकिन नुकसान की सीमा काफी कम हो गई (सारणी IV.42)।

15.3 आवक तथा जावक विप्रेषण

IV.125 पीबी की आय का एक बड़ा हिस्सा विप्रेषण परिचालन से आय के रूप में प्राप्त हो रहा था विशेष रूप से उन्हें जिनका नेटवर्क एवं पहुंच बहुत अच्छी थी। मार्च 2020 से जून 2022 तक केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस और एनईएफटी) में पीबी के लेनदेन में लगभग 19 गुना की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन में शामिल राशि में भी 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई (चार्ट IV.48)।

IV.126 वर्ष 2021-22 में, पीबी के माध्यम से आवक और जावक विप्रेषण की मात्रा में क्रमशः 76.3 प्रतिशत और 84.5 वृद्धि

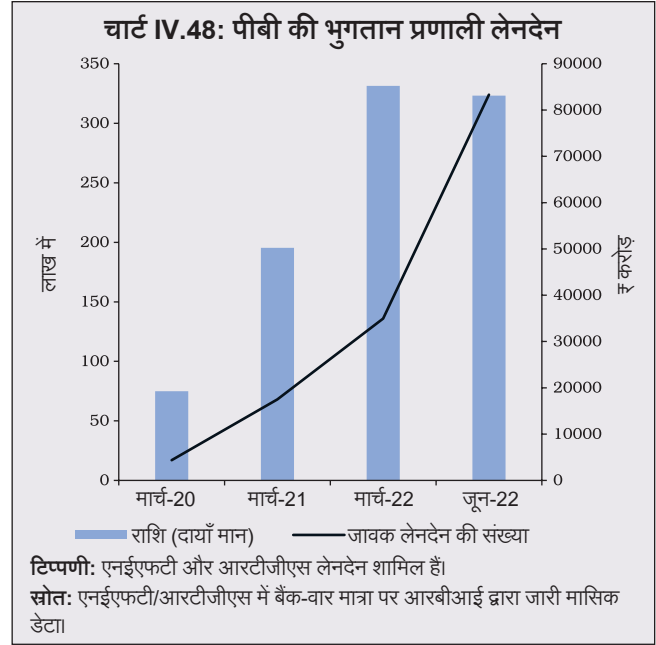
सारणी IV.42: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात (मार्च के अंत में)

क्र. Item सं.	2020	2021	2022
1 आस्तियों पर प्रतिलाभ	-9.8	-6.4	-0.7
2 इक्विटी पर प्रतिलाभ	-44.3	-45.3	-5.2
3 कुल आस्तियों में निवेश	48.4	57.1	55.0
4 निवल ब्याज मार्जिन	4.8	2.8	2.3
5 दक्षता (लागत-आय अनुपात)	124.8	116.9	99.1
6 कार्यशील निधियों को परिचालनगत लाभ	-10.9	-6.1	-0.6
7 लाभ मार्जिन	-23.9	-20.3	-2.2

टिप्पणी: डेटा 6 पीबी से संबंधित है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

हुई है और आवक और जावक विप्रेषण दोनों के मूल्य में पिछले वर्ष में मूल्य और मात्रा दोनों में दर्ज की गई 20 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। आवक और जावक विप्रेषण की संख्या में यूपीआई का शेयर सबसे अधिक था, और आवक प्रवाह के मूल्य में हिस्से के रूप में



भी पहला स्थान इसी का था। तथापि, जावक विप्रेषण के मूल्य के संबंध में सबसे बड़ा हिस्सा आईएमपीएस का था (सारणी IV.3)।

सारणी IV.43: भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण

(संख्या हजार में, राशि ₹ करोड़ में)

माध्यम	2020-21				2021-22			
	आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण		आवक विप्रेषण		जावक विप्रेषण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. एनईएफटी	13,893 (0.9)	26,295 (9.8)	8,259 (0.5)	60,649 (19.8)	37,036 (1.3)	37,999 (6.7)	7,238 (0.2)	64,610 (7.1)
i) बिल भुगतान	94 (0.0)	17 (0.0)	233 (0.0)	28 (0.0)	472 (0.0)	82 (0.0)	391 (0.0)	34 (0.0)
ii) बिल भुगतान के अलावा अन्य	13,799 (0.8)	26,278 (9.8)	8,026 (0.5)	60,621 (19.8)	36,564 (1.3)	37,918 (6.6)	6,847 (0.2)	64,576 (7.1)
2. आरटीजीएस	190 (0.0)	56,460 (21.0)	17 (0.0)	35,107 (11.4)	382 (0.0)	1,28,030 (22.4)	41 (0.0)	1,00,370 (11.1)
3. आईएमपीएस	1,36,274 (8.3)	37,466 (14.0)	1,89,879 (11.1)	65,866 (21.5)	1,95,781 (6.8)	60,838 (10.7)	1,99,386 (6.3)	4,01,203 (44.3)
4. यूपीआई	11,72,699 (71.8)	1,13,289 (42.2)	12,00,688 (70.3)	1,03,908 (33.9)	21,70,638 (75.4)	2,68,887 (47.1)	25,10,470 (79.7)	2,65,610 (29.3)
5. ई - वॉलेट	2,31,624 (14.2)	20,406 (7.6)	3,01,499 (17.7)	38,317 (12.5)	2,61,540 (9.1)	33,202 (5.8)	3,85,949 (12.2)	66,899 (7.4)
6. माइक्रो एटीएम (पीओएस)	32 (0.0)	20 (0.0)	144 (0.0)	45 (0.0)	1,361 (0.0)	499 (0.1)	57 (0.0)	27 (0.0)
7. एटीएम	- (0.0)	- (0.0)	9 (0.0)	3 (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	24 (0.0)	9 (0.0)
8. अन्य	78,208 (4.8)	14,384 (5.4)	7,185 (0.4)	2,866 (0.9)	2,12,792 (7.4)	41,322 (7.2)	48,237 (1.5)	7,266 (0.8)
कुल	16,32,920	2,68,321	17,07,680	3,06,761	28,79,529	5,70,777	31,51,403	9,05,994

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

2. डेटा 6 पीबी से संबंधित है।

स्रोत : ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

16. समग्र मूल्यांकन

IV.127 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने महामारी का बखूबी सामना किया और अधिक आघात-सहनीय और सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। समय पर प्रदत्त नीतिगत सहायता के कारण बैंकों ने बेहतर लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता, पूंजी बफर रिपोर्ट किया है। हाल ही में, बैंकों के तुलन-पत्रों में अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों के अधिक प्रवाह के साथ व्यापक ऋण वृद्धि सहित अच्छी तेजी दिखाई दी है। सरकार द्वारा ईसीएलजीएस के अंतर्गत गारंटी कवर से एमएसएमई को क्रेडिट को बढ़ावा मिला है।

IV.128. आगे यह अनिवार्य है कि बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए उचित सावधानी और सख्त क्रेडिट मूल्यांकन सुनिश्चित करें। वर्ष 2022-23 के दौरान विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बीच तेजी से बदलते समष्टि गत परिदृश्य में अनिश्चितताएं बैंकिंग क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। यदि नकारात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ता

है तो आस्ति गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए, पुनर्निर्मित आस्तियों में गिरावट की सतत निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। आस्तियों के मूल्य में कमी को रोकने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों का समय पर समाधान अनिवार्य है।

IV.129 जीएम त्रयी द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप जनसंख्या के बैंकिंग सेवा रहित और वंचित वर्ग तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में वृद्धि हुई है। यूपीआई की सफलता और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने के कारण विभिन्न चिंताएं जैसे कि तृतीय पक्षों के अनियंत्रित हस्तक्षेप, मिससेलिंग, आंकड़ों की निजता के उल्लंघन, अनुचित कारोबारी व्यवहार, अत्यधिक ब्याज दरों और वसूली के अनैतिक तरीके आदि सामने आई हैं। बैंकों को इन चुनौतियों को पार पाने के लिए उचित कारोबारी रणनीति तैयार करने, अपने अभिशासन फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने और साइबर सुरक्षा लागू करने जैसे कदम उठाने होंगे।